MAHECHA
PUBLICATION

Springboard ACADEMY

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

RAS FOUNDATION

CLASS NOTES

Available @JAIPUR JODHPUR

www.thenoteshub.com

The Notes Hub

© All Rights Reserved with the MAHECHA PUBLICATION

Contact Us : 7300134518 - 7610010054

Index

1. भारत-चीन संबंध 1
2. भारत-अमेरिका संबंध 40
3. भारत-रूस संबंध 70
4. NATO 90
5. भारत-यूरोपीयन यूनियन संबंध 96
6. भारत-पाकिस्तान संबंध 102
7. भारत-बांग्लादेश संबंध 114
8. भारत-अफगानिस्तान 123
9. भारत-नेपाल 130
10. भारत-भूटान 139
11. भारत-श्रीलंका 141
12. भारत-मालदीव 150
13. भारत-म्यांमार 157
14. BRICS 164
15. SAARC 168
16. BIMSTEC 172
17. संयुक्त राष्ट संघ 176
18. ASEAN 186
19. G-77, G-20 193
20. पश्चिम एशिया एवं सुदूर पूर्व में भू-राजनीतिक एवं रणनीतिक मुद्दे तथा उनका भारत पर प्रभाव 199
21. भारतीय विदेश नीति 224
22. अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद 232
23. गुट निरपेक्ष आंदोलन 235

भारत - चीन सम्बन्ध

* चीन का संक्षिप्त अवलोकन

जनसंख्या = 1.4 बिलियन

क्षेत्रफल = 9.6 मिलियन

→ यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

→ दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक - आयातक देश है।

→ आबादी में बहुसंख्यक = हानचीनी

अल्पसंख्यक → मंगोल
→ उइघुर मुस्लीम [शिनजियांग]
→ तिब्बत बुद्ध

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010034

* भाषा = मंदारिन

* प्रशासनिक उद्देश्य के लिए चीन का विभाजन

1. 34 प्रशासनिक इकाईयाँ
2. 23 प्रान्त
3. 4 नगरपालिका
4. 5 स्वायत्त क्षेत्र
5. 2 विशेष प्रशासनिक क्षेत्र

विशेष प्रशासनिक क्षेत्र

हांगकांग	मकाऊ
स्वतंत्र = 1997	1999
द्वारा = ब्रिटिश	पुर्तगाल

* चीनी विदेश नीति :-

→ चीनी विदेश नीति अपने प्राचीन साहित्य जैसे ART OF WAR पुस्तक सुंजु से प्रभावित है।
[सून त्जु]

→ चीन की विदेश नीति अत्यधिक आक्रामक, व्यावहारिक [परिणाम उन्मुख] और अपारदर्शी है।

→ आक्रामक विदेश नीति के कारण - वुल्फ वॉरियर कुटनीति कहा जाता है।

⊛ राजनीतिक पृष्ठभूमि :-

→ 1911 ई. में चीन में गणतंत्रात्मक क्रांति हुई। राजवंश [किंग] के स्थान पर गणतंत्रात्मक सरकार आ गई।

→ गणतंत्रात्मक क्रांति कुओमिन्तांग पार्टी के सुन यात सेन के नेतृत्व में
↳ मुख्य राजनैतिक दल
नेता = चियांग काई शेख

→ 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई।

→ जिसके बाद माओत्से तुंग [चीन में] के नेतृत्व में साम्यवादी पार्टी [का गठन हुआ।

कुओमिनतांग v/s साम्यवादी पार्टी
↘ ↙
राजनैतिक वर्चस्व संघर्ष

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610100064

→ जिसके फलस्वरूप चीन में गृहयुद्ध हुआ।

→ अन्ततः 1949 में साम्यवादी पार्टी की जीत]

→ मुख्य चीन पर अधिकार = साम्यवादी पार्टी
↓
पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना

→ कुमिनतांग [चियानकाई शेख] पार्टी = ताइवान पर अधिकार
↓
रिपब्लिक ऑफ चाइना [ROC] कहा।

→ पश्चिमी देशों ने PROC को मान्यता नहीं दी थी।

→ भारत उन पहले देशों में से था जिसने साम्यवादी चीन को मान्यता दी।

प्रथम = म्यांमार

→ प्रारम्भ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता ROC को दी गई।

→ PROC को स्थायी सदस्यता = 1971 AD

→ चीन में 1978 में आर्थिक सुधार हुये फलस्वरूप —

राजनीतिक दृष्टिकोण	आर्थिक दृष्टिकोण
↓	↓
साम्यवादी	पूंजीवाद

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010064

	साम्यवाद	पूंजीवाद
1.	समानता पर बल	→ स्वतंत्रता पर बल
2.	निजी सम्पत्ति को मान्यता नहीं	→ निजी सम्पत्ति को मान्यता
3.	बाजार सरकार के द्वारा नियंत्रित	→ बाजार में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं
4.	तानाशाही शासन	→ लोकतंत्र
5.	नास्तिक	→ धर्मनिरपेक्ष
6.	हिंसा का समर्थन	→ हिंसा का विरोध
7.	कर्तव्यों पर बल	→ अधिकारों पर बल
8.	संसाधनों का वितरण आवश्यकतानुसार	→ रीति के आधार पर

→ कार्ल मार्क्स —
दास कैपिटल
कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो

→ एडम स्मिथ -
वेल्थ ऑफ नेशन

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010064

⊛ <u>तिब्बत मुद्दा</u> :-

→ 1911 में तिब्बत ने स्वतंत्रता की घोषणा की।

→ 1950 AD में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया।

→ जिसके निम्नलिखित परिणाम हुए-

1. ब्रिटिश काल में बफर स्टेट की नीति समाप्त

2. भारत - चीन के मध्य लम्बी सीमा रेखा अस्तित्व में आई।

3. यह चीन की विस्तारवादी नीति का प्रदर्शन था।

4. ब्रिटिश काल के भारत के विशेषाधिकारों पर प्रश्नचिह्न लगा।

[A]• तिब्बत की डाक व तार सेवा भारत के अधीन थी।

[B]• तिब्बत में एक ब्रिटिश [भारत] प्रतिनिधि नियुक्त

[C]• तिब्बत में व्यापारिक केन्द्र स्थापित किये जाते थे।

→ 1951 AD में तिब्बत ने चीन का आधिपत्य स्वीकारा

→ 1954 में तिब्बत के मुद्दे पर चीन व भारत के बीच एक समझौता हुआ।

→ इस समझौते में भारत ने तिब्बत में अपने विशेषाधिकार छोड़ दिये।

→ इस समझौते को पंचशील का नाम दिया गया।

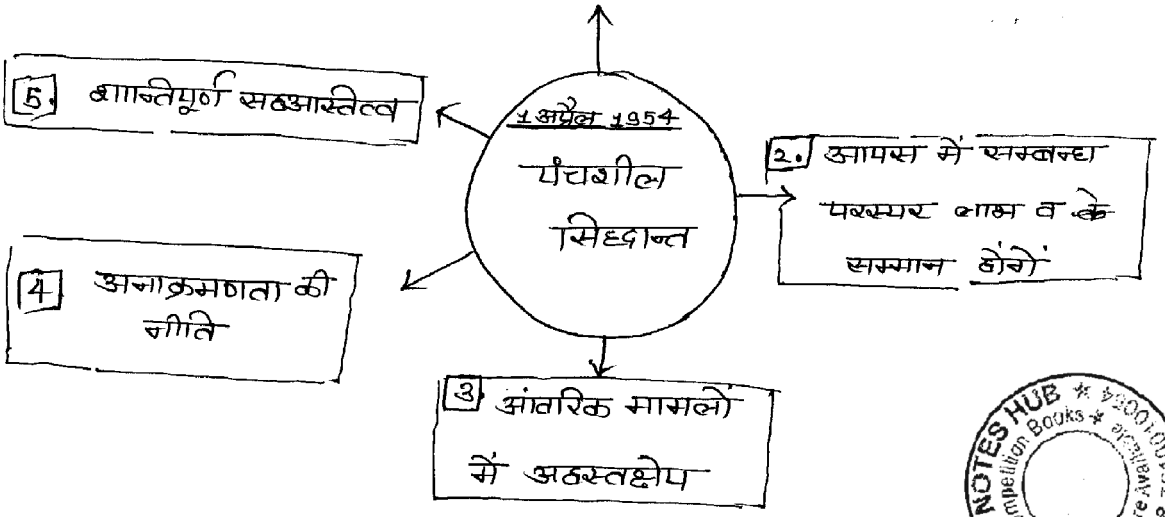

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010004

→ चीन ने तिब्बत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप शुरू किया।

→ जिसके कारण 1959 में विरोध प्रदर्शन - तिब्बत में

→ इसके विरुद्ध चीन ने दमनात्मक कार्यवाही की।

→ तिब्बती बौद्धों के धर्मगुरु दलाईलामा को तिब्बत छोड़ना पड़ा

→ उन्हें भारत में शरण दी जिसके कारण चीन की नीति में बदलाव आया तथा चीन ने पहली बार सीमा विवाद उठाया।

→ वर्तमान में चीन तिब्बत में अपने नियंत्रण को सशक्त कर रहा है।

जैसे- जनसांख्यिकी परिवर्तन

→ तिब्बत में हान मूल के लोगों को बसाया जा रहा है जिससे तिब्बती बौद्धों को अल्पसंख्यक बना सके।

→ तिब्बत में बड़े स्तर पर आधारभूत ढांचे का निर्माण

जैसे - रोड
रेल
डैम

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518

सीमा विवाद :-

→ भारत - चीन के बीच सीमा विवाद 1959 में अस्तित्व में आया।

[3488]

पश्चिमी क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र
जम्मु- कश्मीर	H.P 200	सिक्किम 220
1597 Km	UTK 345	A.P 1126 km

⊛ पाश्चिमी सीमा / क्षेत्र :-

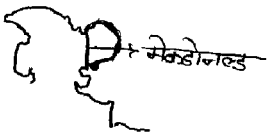

→ यहाँ विवाद अक्साई चीन के आधिपत्य को लेकर है।

→ भारत का दावा जॉनसन रेखा से है। जिसका निर्माण 1865 में ब्रिटिश काल में लद्दाख रियासत के राजस्व खातों से किया गया।

→ चीन इस रेखा को वैध नहीं मानता है, क्योंकि चीन को इसके बारे में सूचित नहीं किया गया था।

→ 1962 के युद्ध के बाद चीन ने अक्साई चीन पर अधिकार किया।

→ एक अन्य रेखा मेकडोनाल्ड लाइन है, जिसके बारे में सूचित [चीन] किया गया। लेकिन चीन ने कोई सहमति नहीं जताई।

→ यह रेखा अक्साई चीन को 2 भागों में बाँटती है।

→ वर्तमान में LAC [वास्तविक नियंत्रण रेखा] के माध्यम से नियंत्रण दबाया गया है।

→ LAC – 1962 के बाद अस्तित्व में आई।

→ यह रेखा पूरी तरह परिभाषित नहीं है। इसलिए समय-समय पर तनाव उत्पन्न होता है।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010024

2. मध्य क्षेत्र :-

→ इसमें हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र शामिल है।

→ इस क्षेत्र में अत्यधिक विवाद है।

→ इस क्षेत्र में बाराहोती [जिला - चमोली] मैदान को छोड़कर कोई विवाद नहीं।

3. पूर्वी क्षेत्र :- [अरुणाचल प्रदेश]

→ इस क्षेत्र में विवाद मेक-मेहन रेखा को लेकर है।

→ यह रेखा 1914 ई. में शिमला सम्मेलन में खींची गई थी। जहाँ हेनरी मेक मेहन ने ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व किया था।

→ चीनी प्रतिनिधि ने सम्मेलन बीच में ही छोड़ दिया इसलिए भारत और तिब्बत के बीच अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

→ चीन इस रेखा को वैद्य नहीं मानता है। और पूरे अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है।

→ चीन अरुणाचल प्र० को दक्षिणी तिब्बत कहता है।

→ चीन मेक-मेहन रेखा को वैद्य नहीं मानता क्योंकि -

1. यह साम्राज्यवादियों द्वारा खींची गई है।

2. यह समझौता तिब्बत के साथ था तथा चीन ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किये।

→ भारत चीन के दावे का खण्डन करता है -

→ 1. चीन साम्राज्यवादियों द्वारा बनाई अन्य रेखाओं को स्वीकार करता है -- चीन - म्यांमार सीमा

→ 2. तिब्बत 1914 ई. में स्वतंत्र व सम्प्रभु देश था अतः वह कोई भी समझौता कर सकता है।

✳ सिक्किम - चीन विवाद :-

→ सिक्किम का विलय भारत में 1975 में हुआ। लेकिन चीन ने इसे भारत की साम्राज्यवादी नीति बताकर विरोध किया।

→ 2003 में इसे चीन ने भारत के राज्य के रूप में मान्यता दी। परन्तु उत्तरी - सिक्किम का फिंगर टिप क्षेत्र अभी भी विवादास्पद है।

(4) अरुणाचल प्रदेश :-

→ पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में चीन का दावा बढ़ा है।

जैसे -

1. अरुणाचल के निवासियों को नत्थी वीजा जारी करना
2. चीन प्रशासनिक दस्तावेजों में AP में दक्षिणी तिब्बत कहा
3. चीन भारतीय P.M. व दलाईलामा की A.P की यात्रा का विरोध करता है।

⊛ तवांग का मुद्दा

→ यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित तिब्बती बौद्धों का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। जो वर्तमान में भारत के नियंत्रण में है।

→ 6th दलाईलामा तवांग से था। ऐसा अनुमान है कि आगामी [15th] दलाईलामा तवांग से हो सकता है।

→ यदि ऐसा होता है तो तिब्बती बौद्धों का तवांग विरोध का केन्द्र बनेगा।

→ इसलिए चीन तवांग पर अधिकार करना चाहता है।

THE NOTES HUB * All Competition Books * Notes are Available * 7300134518, 7610010054

⊛ तात्कालिक विवाद :-

→ चीन व भूटान के बीच 3 पहाड़ी क्षेत्र विवादित है।

→ 2017 में चीन ने डोकलाम पहाड़ पर सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया।

→ जिसका विरोध किया। – भारत

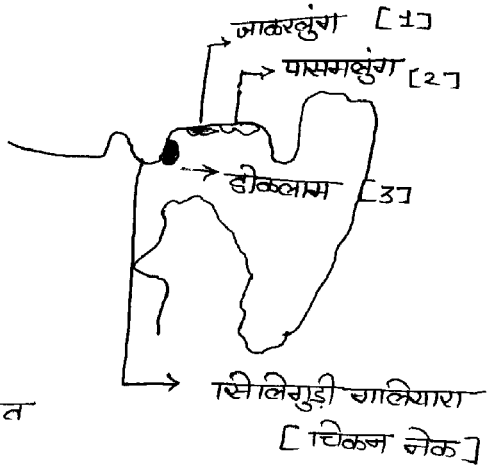

→ क्योंकि –

1. भारत व भूटान के बीच 2007 में एक मित्रता संधि हुयी जिसके अनुसार भूटान की रक्षा की जिम्मेदारी है।

2. भारत व चीन के बीच 2013 में सीमा सुरक्षा व सहयोग समझौता किया गया।

→ जिसके अनुसार जब तक सीमा-विवादों को हल नहीं किया जाता है तब तक सीमा पर यथास्थिति को परिवर्तित नहीं किया जायेगा। तथा सड़क निर्माण इसका उल्लंघन है।

→

3. <u>सिलीगुड़ी गलियारा</u> =

→ डोकलाम पठार इसके नजदीक है।

→ यह गलियारा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह उत्तर-पूर्व के राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है।

→ चीन का डोकलाम पठार पर अधिकार भारत को प्रभावित करेगा।

4. 73 दिन चला यह विवाद 2 प्रकार की नीतियों से हल किया गया —

[A] जमीनी स्तर पर सैन्य शान्ति को मजबूत बनाये रखना

[B] कूटनीतिक वार्ता को जारी रखना

THE NOTES HUB * All Competition Books & Notes are Available * 7300134518, 7610010024

* तात्कालिक विवाद - 2020 की घटनाएँ

→ भारत व चीन के बीच LAC पर विभिन्न झड़पें हुई।

1. **पैंगोंग त्सो** :- 5 मई 2020

→ यह 135 किमी लम्बी खारे पानी की झील है।

→ जो पूर्वी लद्दाख [45 km] व तिब्बत [90 km] स्थित है।

→ उत्तरी पैंगोंग पर स्थित पहाड़ी क्षेत्रों को फिंगर कहा जाता है।

→ झील से होकर LAC निकलती है भारत का दावा = फिंगर = 8
चीन का दावा = फिंगर = 2

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518

→ वर्तमान में भारत का नियंत्रण फिंगर - 4 तक था लेकिन अब फिंगर - 3 तक है।

→ चीन ने इस क्षेत्र में कारगील युद्ध 1999 व 2020 में अतिक्रमण किया

→ उत्तरी पैंगोंग में चीन की स्थिति मजबूत है।

→ 29-30 अगस्त को भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन चलाकर दक्षिण पैंगोंग पर स्थित ब्लेक टॉप व हेलमेट हिल पर कब्जा कर लिया गया।

→ द. पैंगोंग में भारत की स्थिति मजबूत हो गई।

→ दोनों सेनाओं के पीछे हटने पर सहमति बनी।

→ भारत फिंगर - 3 व चीन फिंगर - 8 पर होगा।

→ इसके निकट चुशुल घाटी स्थित जहाँ रेजांग ला स्थित है।

→ रेजांग में 18 नव. 1962 को युद्ध लड़ा गया।

2. <u>गलवान घाटी</u> :-

→ 15 जून 2020 को गलवान घाटी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 व 15 के बीच बड़ी झड़प हुयी।

→ जिसमें बिहार रेजिमेंट के 20 जवान शहीद हुये तथा चीन के 40 जवान मारे गये।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010034

→ लेकिन चीन इन आँकड़ों को अस्वीकारता है।

→ 1975 के बाद हुयी पहली हिंसक झड़प थी।

→ अक्टू. 1975 में तुलुंग ला क्षेत्र [अरुणाचल] में असम राइफल्स के 4 जवानों को धोखे से मार दिया गया था।

⊛ <u>2022 की घटना</u> :-

1. <u>यांगत्से क्षेत्र</u> [A.P] :-

→ 9 दिस. 2022 को चीनी सैनिकों ने अ. तवांग क्षेत्र के यांगत्से क्षेत्र में LAC का अतिक्रमण करने और एकतरफा तरीके से यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया।

→ भारतीय सैनिकों ने दृढ़ता व संकल्प के साथ चीन के प्रयास का विरोध किया।

→ चीनी सैनिकों को अपनी चौकियों पर लौटने हेतु बाध्य किया।

→ 2023 में अमेरिकी सीनेट द्वारा पारित प्रस्ताव मैकमोहन रेखा को भारत – चीन के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का दर्जा दिया गया है।

विवाद के अन्य क्षेत्र :-

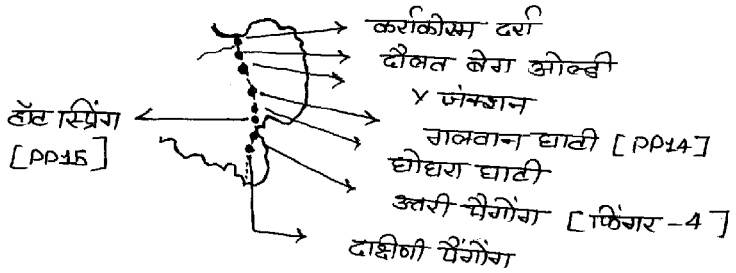

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518

चीन की आक्रामकता के कारण :-

1. भारत के द्वारा सीमा पर आधारभूत ढाँचे का निर्माण
   जैसे- दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी का निर्माण
   दार्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क का निर्माण

2. कोरोना काल में चीन की भूमिका की आलोचना वैश्विक व घरेलू स्तर पर की जा रही है।

→ इसलिए चीन इस मुद्दे से ध्यान हटाना चाहता है।

3. चीन – पाकिस्तान सम्बन्ध

4. LAC परिभाषित नहीं है।

5. पिछले कुछ समय से भारत का झुकाव अमेरिका की ओर है।
जैसे = क्वाड का निर्माण

→ इसलिए चीन भारत पर दबाव बनाना चाहता है।

6. उत्तराखंड के औली में सम्पन्न हुये युद्ध अभ्यास [भारत-अमेरिका सैन्य अभ्यास] ने चीन को उकसाया क्योंकि उसका दावा है कि यह अभ्यास LAC पर 1993 व 1996 के समझौतों का उल्लंघन है।

⊛ सीमा विवाद को कम करने के प्रयास :— [2020 की घटना के बाद]

1. तनाव को हल करने के लिए 2 प्रक्रियाओं का प्रयोग
(a) वार्ता से तनाव को कम करना
[b] सेनाओं की वापसी

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010094

2. सैन्य स्तर पर बातचीत की जा रही है, अब तक 18 दौर की बातचीत की जा चुकी है।

3. इस प्रक्रिया को चरणबद्ध, समान्वित व सत्यापित तरीके से लागू करना।

जैसे -

(i) सर्वप्रथम पैंगोंग झील के मुद्दे को हल किया गया जिसमें भारतीय सेना फिंगर-3 के पीछे चली गई तथा चीनी सेना फिंगर 8 के पीछे।

(ii) अन्य स्थानों पर भी सेना वापसी की गई है, यद्यपि कुछ टकराव के स्थान अभी भी मौजूद है जैसे - हॉट स्प्रिंग

चीन का नया सीमा कानून :- 1 जनवरी 2022

1. यह सीमा क्षेत्र के साथ नागरिकों के लिए गाँवों के विकास की अनुमति देता है।

2. नागरिक व स्थानीय संगठनों को भी सीमा अवसंरचना की सुरक्षा व बचाव का दायित्व सौंपा गया है।

3. इससे चीनी सैनिकों को सीमा पर हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत मिल जाती है।

समझौते :-

1. 1988 ई. - राजीव गाँधी की चीन यात्रा → संयुक्त सीमा कार्यदल और संयुक्त आर्थिक समूह

2. 1993 ई. :- सीमा पर शान्ति बनाये रखने के लिए समझौता

3. 1996 ई. :- विश्वास बहाली के उपायों हेतु समझौता

* 2003 AD :- सीमा विवाद को हल करने के लिए विशेष प्रतिनिधियों की नियुक्ति

[22 दौर की बातचीत पूरी कर ली है]

भारत के विशेष प्रतिनिधि = अजीत डोभाल

चीन = वांग यी

* 2005 ई :- सामरिक साझेदारी का समझौता

* 2005 ई. :-

→ सीमा विवाद को हल करने के लिए राजनीतिक मापदण्ड व निर्देशक सिद्धान्त निर्धारित किये गये।

जैसे -

1. सीमा निर्धारण के लिए स्पष्ट व पहचानने योग्य भौगोलिक संकेतकों का प्रयोग करना।

2. सीमा पर रह रहे लोगों के हितों की रक्षा करना।

* 2013 ई. :- सीमा सुरक्षा एवं सहयोग समझौता

* 2018 ई :- वुहान में अनौपचारिक सम्मेलन

* 2019 ई :- महाबलीपुरम, चैन्नई में अनौपचारिक सम्मेलन

* 2020ई. :- चीन व भारत के बीच राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना की 70 वीं वर्षगाठ

* सुझाव :-

(i) LAC को पूर्ण रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।

(ii) यह अत्यधिक जटिल व ऐतिहासिक विवाद है इसलिए दोनों पक्षों को धैर्य बनाये रखना चाहिए।

(iii) अन्य क्षेत्रों में विवादों को हल किया जाना चाहिए जिससे कि विश्वास को सशक्त किया जा सके।

(iv) सर्वप्रथम मध्य भाग को हल किया जाना

(v) समझौतों का पूर्ण रूप से पालन

समुद्री विवाद :-

* हिन्द महासागर :-

(i) भारत की 7516 km लंबी तटीय सीमा है जो हिन्द महासागर में स्थित इसकी रक्षा भारत के लिए सर्वोपरी है।

(ii) आयतन की दृष्टि से भारत के कुल व्यापार का 94% हिन्द महासागर के माध्यम से होता है।

(iii) भारत अपने ऊर्जा आयात के लिए हिन्द महासागर पर निर्भर है।

(iv) हिन्द महासागर आर्थिक महत्व के विभिन्न संसाधनों का घर है। जैसे - तेल, गैस, मत्स्य पालन

(v) ऐतिहासिक रूप से भी हिन्द महासागर पर भारत का प्रभुत्व रहा है।

→ हिन्द महासागर में चीनी गतिविधियाँ बढ़ी है जो हिन्द महासागर में भारतीय हितों के लिए चिन्ता का विषय है।

⊛ चीनी गतिविधियाँ :-

1. मोतियों की माला :-

→ इस नीति का उद्देश्य भारत को घेरना है।

→ चीन भारत की चारों दिशाओं में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगहों पर बन्दरगाहों का निर्माण कर रहा है।

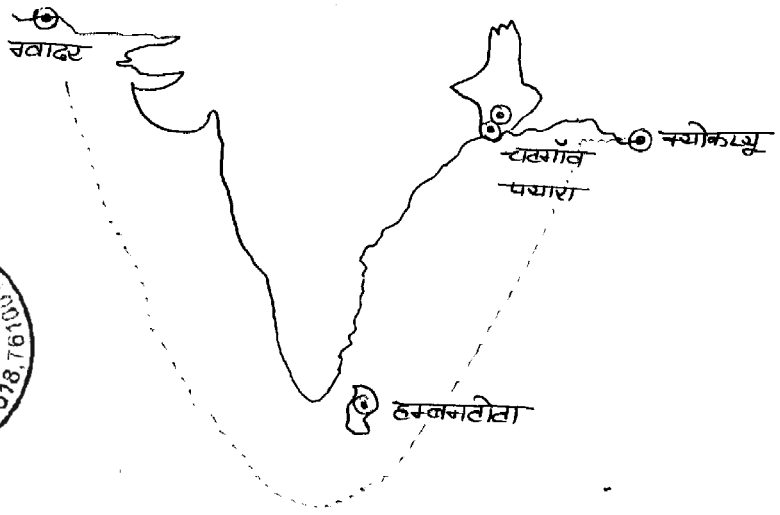

* ~~नौसैनिक~~ नौसैनिक अड्डे :- चीन भारत को घेरने के लिए हिन्द महासागर में नौसैनिक ठिकाने भी बना रहा है।

जैसे - म्यांमार = कोको द्वीप

पाकिस्तान = जिवानी

जिबूती

3. हिन्द महासागर में चीनी पनडुब्बियों की गतिविधियाँ बढ़ गई है।

→ इन पनडुब्बियों को कोलम्बो बन्दरगाह [श्रीलंका] करांची बंदरगाह [पाकिस्तान] में देखा गया।

5

(iii) 2008 ई. में चीन समुद्री लुटेरों के विरुद्ध अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है लेकिन यह आवश्यकता से अधिक जहाजों का प्रयोग कर रहा है।

* इन गतिविधियों से भारत के निम्नलिखित हित प्रभावित होते है -

1. भारत की समुद्री सीमा को खतरा
2. समुद्री व्यापार प्रभावित हो सकता है विशेषकर तेल व गैस का आयात
3. मत्स्य तथा अन्य संसाधनों का दोहन
4. हिन्द महासागर में भारत का प्रभुत्व कम हो जाएगा
5. पड़ोसी देशों से सम्बन्ध प्रभावित

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610100064

⊛ भारत की प्रतिक्रिया :-

→ हिन्द महासागर के तटीय देशों के साथ सक्रिय सम्बन्ध बनाये जा रहे हैं
जैसे - इण्डियन ओशियन रिम एसोसिएशन

* डबल फिश हुक रणनीति :-

→ जिसके तहत अमेरिकी सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया का प्रयोग
ओमान - डुकुम बंदरगाह, इण्डोनेशिया = सबंग बंदरगाह
को भारत द्वारा विकसित किया जा रहा

* ईरान में चाबहार बंदरगाह का निर्माण

* फ्रांस के रियुनियन द्वीप का प्रयोग भारत कर सकता है।

3. मालाबार युद्ध अभ्यास

4. क्वाड का निर्माण [चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद]

5. मिशन सागर [क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास]

शुरुआत = मई 2020

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010004

⊛ दक्षिण - चीन सागर विवाद

1. पारासेल [वियतनाम]
2. स्कारबोरो [फिलीपिंस
स्प्रेटली [मलेशिया - ब्रुनेई]
द्वीप दक्षिण चीन सागर में स्थित है।

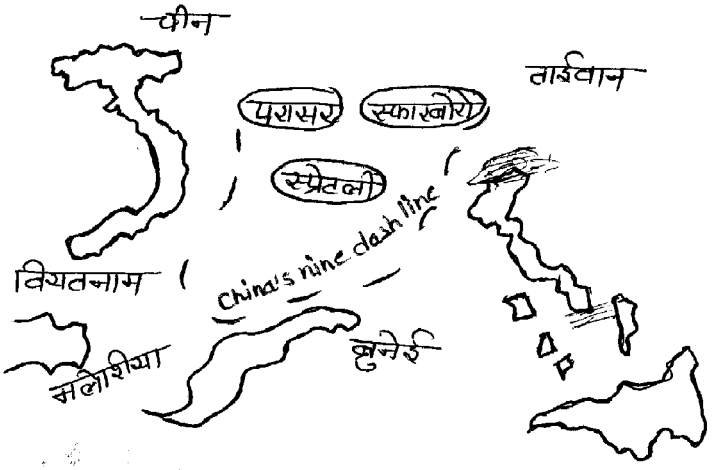

→ चीन ने इन द्वीप समूहों पर कब्जा कर लिया है तथा उनका सैन्यकरण कर दिया।

उदाहरण - मिसाइल लॉन्चिंग केन्द्रों की स्थापना

→ चीन ने दक्षिण चीन सागर के लगभग 80% हिस्से को अपने क्षेत्र के रूप में दावा किया।

→ चीन यह दावा अपनी ऐतिहासिक 9-डेस लाइन थ्योरी के आधार पर करता है।

→ यह दावा अन्तर्राष्ट्रीय नौवहन व हवाई परिवहन की स्वतंत्रता में में बाधा उत्पन्न करता है।

→ स्कारबोरो द्वीपों का मुद्दा फिलीपिन्स द्वारा मध्यस्थता की स्थायी अदालत में उठाया गया था, जिसने अपना फैसला फिलीपींस के पक्ष में दिया।

→ चीन ने इस फैसले को मानने से इंकार कर दिया। जो अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति घोर अवहेलना को दर्शाता है।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610100018

*** प्रभाव :-**

1. छोटे देशों के हित प्रभावित हो रहे है क्योंकि चाइना प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है।

2. चीन अन्तर्राष्ट्रीय समझौता / नियमों का उल्लंघन कर रहा
   जैसे- UNCLOS

3. द. चीन सागर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है, इसके सैन्यीकरण

→ जिससे वैश्विक व्यवस्था प्रभावित होगी।

⊛ प्रतिक्रिया :-

→ अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय चीन के इस दावे को स्वीकार नहीं करता है।

→ नौवहन व वायु परिवहन की स्वतंत्रता का समर्थन किया जाता है।

→ आसियान संगठन के द्वारा नियम आधारित व्यवस्था का समर्थन किया गया है।

→ क्वाड का निर्माण

→ यूरोपीय देशों के द्वारा अपनी नौ सेना को यहाँ भेजा गया है।

✶ ONGC विवाद

→ 1988 से ONGC दक्षिण चीन सागर में तेल संसाधनों की खोज कर रही है।

→ ONGC व वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था, लेकिन चीन ONGC के लिए रुकावटें व बाधायें पैदा की।

1. * हीरो के हार की रणनीति :-

- भारत ने चीन को चारों तरफ से घेरने के लिए अलग - अलग हितों वाले कई देशों के साथ सामरिक सहयोग को बढ़ाया।

जैसे - चांगी नेवल बेस – सिंगापुर = 2018

सबंग पोर्ट – इंडोनेशिया - 2018 ┐
दुक्म पोर्ट – ओमान - 2018 ┘ → सैन्य इस्तेमाल

अजम्पशन द्वीप – सेशेल्स – 2015 → सैन्य

चाबहार बंदरगाह – ईरान = बंदरगाह

THE NOTES HUB ★ 7300134518, 7610100084 ★ All Competition Books ★ Notes are Available

* भारत का सामरिक सहयोग :-

1. मंगोलिया :– सामरिक साझेदारी = 2015

→ मंगोलिया में भारत द्वारा तेल रिफाइनरी का निर्माण

2. जापान :– (i) भारत और जापान ने संयुक्त रूप से एशिया - अफ्रीका ग्रोथ कॉरीडोर बनाने की घोषणा की है।

(ii) QUAD

3. फिलीपिंस :- भारत - फिलीपिंस द्वारा दक्षिण चीन सागर में युद्ध अभ्यास किया गया।

→ भारत फिलीपिंस को ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहा है।

4. **वियतनाम :-** भारत वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल व गश्ती नौकायन बेच रहा है।

ब्रह्मपुत्र जल विवाद

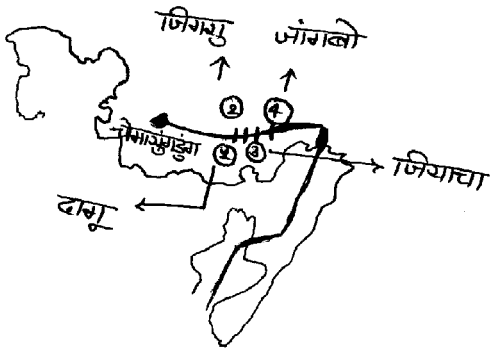

→ ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होकर गुजरती है।

→ इसे तिब्बत में यारलुंगसांगपो कहते हैं।

→ ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बाँधों का निर्माण किया जा रहा है।

→ जिसका विरोध भारत ने किया।

1. जल नियंत्रित करने से भारत में बाढ़ व सूखे की समस्या उत्पन्न की जा
2. भारत की जल विद्युत परियोजना प्रभावित
3. नदी के पारिस्थितिकीय तंत्र को नुकसान होगा।
4. बांग्लादेश के साथ बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।
5. यह भूकम्प संभावित क्षेत्र है।

→ भारत और चीन के बीच जल की सूचनाओं को साझा करने के लिए समझौता किया गया था परन्तु चीन इसका पालन नहीं करता

THE NOTES HUB ★ All Competition Books & Notes are Available ★ 7300134518, 7610100014

→ चीन का दावा है कि बाँध परियोजनायें रन ऑफ द रिवर प्रकार की है, जिसमें बड़े स्तर पर जल संग्रहण नहीं किया जा सकता।

→ भारत इस दावे का खण्डन करता है क्योंकि सेटेलाइट से प्राप्त तस्वीरें स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि यहाँ बड़े स्तर पर जल संग्रहण किया जा सकता है।

✳ समाधान :-

→ नदी के जल सम्बन्धी सूचनाओं में पारदर्शिता बरती जानी चाहिए।

→ भारत - चीन - बांग्लादेश को जल बँटवारे से सम्बन्धित समझौता करना चाहिए।

आर्थिक सम्बन्ध

→ भारत व चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार $136.26 बिलियन डॉलर का है जिसमें से चीन $118.77 बिलियन डॉलर का निर्यात करता है। भारत $17.49 bn का निर्यात करता है।

→ इस व्यापार का झुकाव चीन की ओर है। [101.28 घाटा]

* प्रभाव :-

→ यह भारत के चालू खाते के घाटे को बढ़ता है।

2. यह भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार को घटाता है।

3. यह भारत के निर्माताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है व रोजगार को प्रभावित करता है।

4. चीनी सामान की गुणवत्ता ठीक नहीं है, जिससे उपभोक्ता के हितों को नुकसान पहुँचता है।

5. चीन सामान सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करते है।
जैसे- दूरसंचार

6. मुख्य रूप से भारत कच्चे माल का निर्यात करता है जबकि चीन तैयार माल का निर्यात करता है।

→ अतः यह औपनिवेशीक काल जैसा है।

⊛ व्यापार घाटे के कारण :-

→ चीनी उत्पाद सस्ते है क्योंकि चीन उत्पादों की डम्पिंग जैसे अनैतिक व्यापार प्रथाओं का पालन करता है।

→ डम्पिंग = जब कोई उत्पाद उत्पादन लागत से कम कीमत पर दूसरे देशों में बेचा जाता है।

→ चीन समय-समय पर अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है।

→ जिससे उनके उत्पाद सस्ते हो जाते है।

→ चीन में उत्पादन का पैमाना बहुत बड़ा है जिससे प्रति यूनिट लागत घट जाती है।

→ चीन का बुनियादी ढांचा बहुत अच्छी तरह से विकसित जो इसकी उत्पादकता को बढ़ाता है।

→ तुलनात्मक रूप से लचीले पर्यावरण व श्रम कानून

→ चीन की सरकार उद्योगों को सक्रियता से मदद करती है।

→ कम दरों पर ऋण की उपलब्धता

⭐ भारत का निर्यात कम है – क्योंकि

1. भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ बुनियादी अवसंरचनात्मक कमियाँ है जो विकास को बाधित करती है -

जैसे - कमजोर अवसंरचना
अधिक ब्याज दरें
छोटे स्तर पर उत्पादन

→ चीन के बाजार में भारतीय उत्पादों के लिए पर्याप्त बाजार पहुँच उपलब्ध नहीं है। [गैर शुल्क बाधा]

→ विश्व व्यापार संगठन के स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों के कारण चीन ने भारतीय उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया।

बासमती चावल

→ भारत के निर्यात बास्केट में विविधता का अभाव है।

समाधान व प्रतिक्रिया :-

1. चीन के साथ विभिन्न सामरिक और आर्थिक सम्मेलन आयोजित किये गये है। जिनमें भारत ने व्यापार असन्तुलन के मुद्दे को मजबूती से रखा है।

2. चीन ने भारत को आश्वासन दिया है वह उन्हें बाजार पहुँच प्रदान करेगा।

3. भारत अपने निर्यात बास्केट में विविधता ला रहा है।

4. भारत के द्वारा ऐसे चीन उत्पाद व मोबाइल एप्प प्रतिबंधित किये गये है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है।

   जैसे- टिकटॉक

   5G के परीक्षण से हुआवे कम्पनी को अलग किया गया।

5. एंटिम डंपिंग ट्रायल

6. आत्म निर्भर भारत अभियान शुरू जिससे आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके।

7. चीन में भारत के निर्यातों को बढ़ाने का प्रयास

8. भारत RCEP से बाहर हो गया।

   [REGIONAL

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010004

* चीन की पहल :-

1. सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट
2. मेरीटाइम सिल्क रोड

बेल्ट एंड रोड इनिशीएटिव

* बेल्ट एंड रोड इनीशीएटिव :-

→ यह चीन की महत्वकांक्षी परियोजना है। जिसके तहत चीन को यूरोप अफ्रीका, एशिया, हिन्द महासागर व प्रशान्त महासागर से समुद्री और थल मार्ग से जोड़ा जा रहा है।

→ इसे दो भागों में बांटा गया है।

1. **सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट :-** इस पहल के तहत जमीन पर रेलवे राजमार्ग, औद्योगीक पार्क, ऊर्जा परियोजनाएं, ट्रांसमिशन लाइन व ब्रोडबैंड लाइन स्थापित की जायेगी।

2. **मेरीटाइम सिल्क रोड :-** इसके तहत समुद्रों में बंदरगाहों, गोदामों शीपयार्ड, रिफाइनरी आदि का विकास किया जायेगा।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010004

→ इस परियोजना से लाभ :- [उद्देश्य]

1. आर्थिक उद्देश्य :-

→ चीन नये बाजारों में निर्यात कर सकेगा।

→ चीनी कम्पनियों की नजर निवेश के नये अवसरों पर होगी।

3. चीन के वित्तीय संगठनों को वैश्विक स्तर पर सक्षमत किया जायेगा।

4. दुनियाभर में चीन मुद्रा की स्वीकार्यता बढ़ेगी।

5. यह चीन में आर्थिक आन्तरिक सम्पर्क सुनिश्चित करेगा।

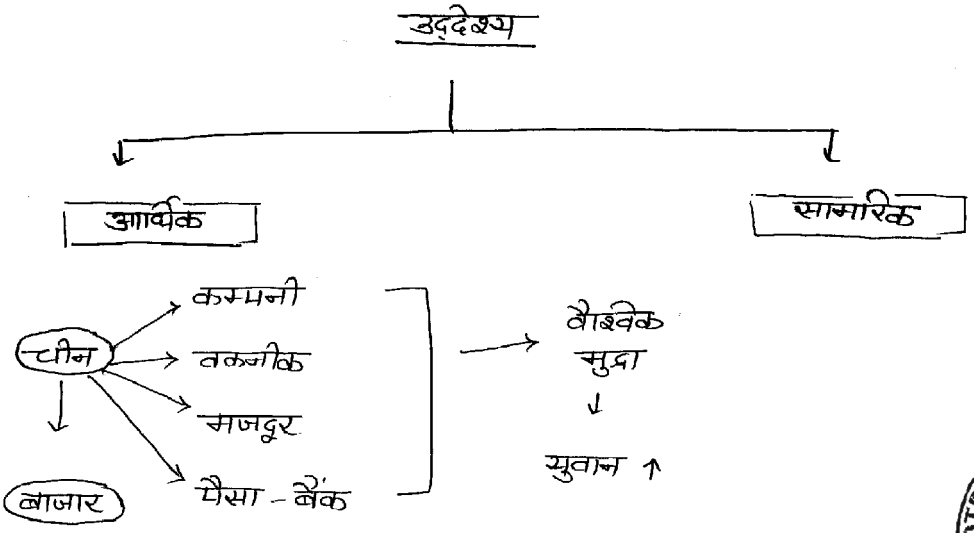

2. सामरिक महत्व :-

→ चीन खुद को वैश्विक शान्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है।

→ चीन भागीदार देशों के फैसलों को प्रभावित करना चाहता है।

→ इस परियोजना का प्रयोग अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में करेगा।

→ यह U.S.A, रूस व भारत की शान्ति व प्रभाव को कम करने का प्रयास करेगा।

→ चीन अपने आयात के लिए मलक्का जलसन्धि पर अत्यधिक निर्भर है। यह परियोजना चीन के लिए वैकल्पिक मार्ग खोलना सुनिश्चित करेगा।

* प्रभाव :-

* सकारात्मक प्रभाव :- यह परियोजना दोयागत गतिविधियों को बढ़ावा देगी। जिससे आर्थिक गतिविधियाँ व रोजगार के नये अवसरों में तेजी आयेगी।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610100004

* नकारात्मक प्रभाव :-

1. यह भागीदारी राष्ट्रों की सम्प्रभुता पर नकारात्मक/प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
2. यह कई साझेदार देशों को कर्ज के जाल में फंसा सकता है।
   उदाहरण - पाकिस्तान, श्रीलंका

→ श्रीलंका ने पहले ही हम्बनटोटा चीन को 99 साल की लीज पर दे दिया है।

3. मानवाधिकारों का हनन
4. पर्यावरणीय संकट
5. दुनिया की महाशक्तियों के बीच संघर्ष

BRI पर भारत की प्रतिक्रिया :-

1. भारत ने इसका विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि इसका एक हिस्सा POK [चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा] से गुजरता है।

2. यह भारत की सम्प्रभुता के लिए खतरा है।

3. भारत ने इसके नकारात्मक प्रभावों को रेखांकित किया है।

4. भारत, USA, जापान के द्वारा मिलकर एशिया - अफ्रीका कॉरीडॉर की शुरुआत की गई।

5. भारत अन्तर्राष्ट्रीय पहल ब्लू डॉट नेटवर्क का हिस्सा है जो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की व्यावहारिता को दर्शाता है।

6. G-7 समूह के द्वारा हाल ही में BUILT BACK BETTER WORLD पहल की शुरुआत की।

7. यूरोपीय संघ द्वारा ग्लोबल गेटवे नामक पहल की शुरुआत।

प्रोजेक्ट मौसम :-

→ सांस्कृतिक विविधता के माध्यम से हिंद महासागर के देशों को जोड़ने के लिए BRI के खिलाफ भारत की पहल
↳ संस्कृति मंत्रालय

THE NOTES HUB * All Competition Books * Notes are Available * 7300134518, 7610100094

* एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक :-

→ यह एक बहुउद्देश्य बैंक है। जो ढांचागत परियोजनाओं को ऋण प्रदान

→ करता है।

→ स्थापित = 2016

→ पूंजी = 100 B$

→ सदस्य = 106

→ योगदान - चीन - भारत - रूस

→ मुख्यालय = बीजींग [चीन]

THE NOTES HUB ★ 7610010064 ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518

* चीन - पाकिस्तान सम्बन्ध :-

-- 1963 में पाकिस्तान ने चीन को POK शक्सगाम घाटी [5180] वर्ग km] भेंट दी।

→ पाकिस्तान का मिसाइल व परमाणु कार्यक्रम चीन द्वारा प्रायोजित है।

→ पाकिस्तान BRI प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है।

→ चीन पाकिस्तान में ढांचागत परियोजनाओं का विकास कर रहा है।

जैसे - 1978 में ट्रांस काराकोरम हाइवे

* चीन - पाकिस्तान इकॉनोमिक कॉरिडोर

[यह शिनजियांग में काशगर व ग्वादर तक]

प्रारम्भ = 2015

लं. = 3000 किमी.

* अन्य परि. -

करोट बांध [POK]

कायदे - आजम [बहावलपुर, पाक]

3. साहीवाल कोयला विद्युत संयंत्र [पाक.]

4. करांची - पेशावर रेल लाइन

→ चीन - पाकिस्तान के आतंकवादी समूह को रक्षा करता है व उन्हें संरक्षण देता है।

उदाहरण - जैश ए मोहम्मद का सरगुद अजहर [पठानकोट [पुलवामा + संसद]

→ चीन NSG [परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह] में भारत का विरोध कर रहा है व पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है।

* एक चीन नीति :-

→ चीन [PROC] केवल एक है व ताइवान उसका एक हिस्सा है।

→ चीन व ताइवान दोनों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किये जा सकते।

→ इसलिए अधिकतर देशों ने भारत सहित ताइवान के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित नहीं किये।

→ लेकिन अब सीमा पर चीनी आक्रामकता के कारण भारत ने एक चीज नीति का पालन करना बंद कर दिया।

* अब :-

→ ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केन्द्र = नई दिल्ली

→ भारत ने ताइवान में इण्डिया ताइपे एसोसिएशन की स्थापना की।

→ अतः भारत को एक चीन नीति को तभी मान्यता देनी चाहिए जब चीन एक भारत नीति को मान्यता दे।

* **हांगकांग का मुद्दा :-**

→ हांग-कांग 1997 तक अंग्रेजों के अधीन था।

→ 1997 में अंग्रेजों और चीन के बीच समझौता हुआ। जिसके तहत हांग-कांग को 50 साल के विशेष दर्जा दिया गया। अर्थात्

हांगकांग का — अलग संविधान
सरकार
विधायिका
पुलिस व्यवस्था आदि है।

THE NOTES HUB * All Competition Books * Notes are Available * 7300134518, 7610100064

→ एक देश दो व्यवस्थाओं के तंत्र को अपनाया।

→ परन्तु चीन हांगकांग पर अधिकार करना चाहता है।

→ इसलिए समय-समय पर ऐसे कानून पारित किये जाते है। जिससे हांग-कांग पर अधिकार किया जा सके।

जैसे - 2020 — राष्ट्रीय सुरक्षा कानून

→ चीन के विरुद्ध - अलगाववाद, अतिवाद, आतंकवाद — के कार्य करेगा, उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

→ हांगकांग ने इसका विरोध किया लेकिन चीन ने दमनकारी नीति अपनाई।

★ उइगर मुस्लिम का मुद्दा

→ ये चीन शिनजियांग प्रान्त में एक नृजातीय समूह जो अलगाववादी आन्दोलन का नेतृत्व कर रहा है।

→ चीनी सरकार ने दमनात्मक कार्यवाही अपनाई और इसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ।

भारत - अमेरिका सम्बन्ध

→ भारत और USA के सम्बन्धों को 3 कालखंडों में बांटा जा सकता है

1. 1947 - 1991 = नकारात्मक
2. 1991 - 2005 = दबाव और सहयोग
3. 2005 के बाद = सकारात्मक

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010004

✱ 1947 - 1991 AD :—

→ इस काल में संबंध नकारात्मक थे।

→ प्रारम्भ में U.S.A ने भारत को पूंजीवादी गुट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

→ लेकिन भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई।

→ 1955 ई. में पाकिस्तान USA के गुट का सदस्य बना।

→ जिसके बाद USA के द्वारा भारत विरोधी नीति अपनाई गई।

→ 1965 व 1971 के युद्ध में USA ने पाकिस्तान का समर्थन किया

→ भारत ने वियतनाम युद्ध में USA के हस्तक्षेप की आलोचना की

→ जिसके बाद भारत को मिलने वाली खाद्य सहायता PL-480 को रोका गया।

→ भारत ने 1974 में परमाणु परीक्षण किया [ऑपरेशन स्माइल] ←
[operation Smile Buddha]

→ USA ने इसका विरोध किया।

→ परमाणु आपूर्तिकर्ता [NSG] की स्थापना की।

* 1991 – 2005 AD :–

→ इस काल में USA के द्वारा दबाव व सहयोग की नीति अपनाई गई।

→ 1996 में भारत पर CTBT पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाया गया। [Comprehensive Test Ban Theaty]

→ लेकिन भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किये क्योंकि यह एक भेदभावपूर्ण संधि थी।

→ भारत ने 11 व 13 मई 1998 [ऑपरेशन शक्ति] को परमाणु परीक्षण किया।

→ जिसके बाद USA ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाये।

→ वर्ष 2000 में क्लिंटन – अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की और आर्थिक प्रतिबंधों को हटाया।

→ 1999 में USA ने कारगिल युद्ध को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाला।

→ 2001 में USA पर 9/11 का आतंकवादी हमला हुआ जिसके बाद आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक युद्ध की घोषणा की जिसमें भारत ने USA का समर्थन किया।

→ दो देशों के बीच संबंधों में सुधार हुए।

* 2005 से अब तक :-

→ 2005 में भारत और अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु समझौते की घोषणा हुई

→ 6 सितम्बर 2008 को समझौता लागू हुआ।

* प्रावधान :-

1. भारत व USA के बीच नाभिकीय व्यापार होगा → सामग्री → तकनीक
2. भारत को NSG में खुली छूट दिलवाई जायेगी।
3. भारत अपने सैन्य व असैन्य परमाणु संयंत्रों को अलग-अलग करेगा।
4. नागरिक परमाणु संयंत्रों / असैन्य परमाणु संयंत्रों IAEA [अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण] की सुरक्षा नियमों का पालन किया जायेगा
5. जाँच अधिकारियों को जाँच की अनुमति दी जायेगी।

→ IAEA से सम्बन्धित प्रोटोकॉल कहलाते है - 123 Agreement

→ क्योंकि US एटॉमिक एनर्जी एक्ट की धारा - 123 में संशोधन किया गया और भारत को अपवाद के रूप में स्वीकार किया गया।

→ 2 कंपनियों ने भारत में निवेश की घोषणा की -

1. वेस्टिंग हाउस
2. जिई - हिताची

→ लेकिन अभी तक यह निवेश संभव नहीं सका।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518

* बाधाएँ :-

→ 2010 ई. में भारतीय संसद ने CLND कानून पारित किया [परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधि.)

→ इसकी 2 धाराओं का विरोध

1. धारा 17[B] :- नाभिकीय हादसे में जिम्मेदारी ऑपरेटर की न होकर सप्लायर की होगी।

2. धारा = 46 :- परमाणु की दुर्घटना का शिकार पक्ष संचालक और आपूर्तिकर्ता दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करवा सकता है।

* समाधान :-

→ अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2015 में भारत का दौरा किया था तथा दोनों धाराओं में संशोधन कर इस विवाद को सुलझाया।

→ वर्तमान में वेस्टिंग हाउस को तोशिबा द्वारा अधिग्रहित किया गया तथा GE - हिताची को भूमि अधिग्रहण [आंध्रप्रदेश] में समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610100034

* भारत और USA के बीच विवाद :-

1. बौद्धिक सम्पदा विवाद

→ USA के अनुसार भारत में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का सम्मान नहीं किया जाता है।

– विशेष रूप से मुबीज, सॉफ्टवेयर, दवाईयों के क्षेत्र में

→ बौद्धिक संपदा अधिकारों [IPR] के उल्लंघन के लिए अमेरिका द्वारा भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है।

* मुख्य विवाद दवाईयों के क्षेत्र में हुआ

→ कोरोना में भारत ने USA से मांग की थी वह वैक्सीन पर IPR में छूट दे।

→ शुरुआत में अमेरिकी सरकार गम्भीर नहीं थी परंतु भारत की आपत्ति पर उन्होंने वैक्सीन पर IPR में छूट दी।

* पूर्व विवाद

1. GLIVEC = स्वर ग्रीनिंग
2. Nexavar = अनिवार्य लाइसेंस

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010034

* H1-B वीजा :-

→ यह USA में कुशल श्रमिकों को दिया जानेवाला अस्थायी कार्य वीजा है।

→ भारत इस वीजा कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभार्थी है।

→ डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने इसके लिए कड़े नियम बनाये।

→ बाइडेन ने इन नियमों को पलट दिया।

CAATSA

* काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैन्क्शंस एक्ट - 2017

→ यदि कोई देश रूस / ईरान / उत्तर कोरिया — के साथ ऊर्जा व रक्षा व्यापार करेगा तो USA उस पर प्रतिबंध लगा सकता है।

→ यदि USA भारत पर प्रतिबंध लगाता है तो यह QUAD के उद्देश्य और चीन के खिलाफ भारत की सैन्य क्षमता को प्रभावित करेगा।

→ भारत ने इस पर अमेरिका से छूट की मांग की।

→ अमेरिका ने छूट दे दी।

* संरक्षणवादी नीतियाँ :-

→ विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों को बचाने की नीति।

→ USA द्वारा आयात को कम करने के लिए विभिन्न संरक्षणवादी नीतियाँ अपनाई जा रही है।

जैसे- GSP [सामान्यीकृत प्रणाली वरीयता - जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफेरेंस] की सुविधा।

THE NOTES HUB * All Competition Books & Notes are Available * 7300134518, 7610010004

* GSP :-

शुरुआत = 1976

→ इसके तहत विकासशील व अल्पविकसित देशों को आयात शुल्कों में छूट व प्राथमिकता दी जाती है।

→ भारत को दी जाने वाली छूट समाप्त = 2020

→ इसके विरोध में भारत ने 28 अमेरिकी वस्तुओं पर कर शुल्क बढ़ा दिया। जैसे-
- → सेब
- → अखरोट
- → लोह-इस्पात

→ भारत के निर्यात प्रोत्साहनों व आयात शुल्कों को USA द्वारा WTO में चुनौती दी जाती है।

* भारत का डेटा स्थानीयकरण कदम :-

→ भारत गूगल, फेसबुक जैसी कम्पनियों के लिए यह नियम लागू करने की प्रक्रिया में है।

→ जो भारतीय उपभोक्ताओं से डेटा उत्पन्न तथा एकत्रित करते है उसका अमेरिका द्वारा विरोध किया जा रहा है।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010064

* जलवायु परिवर्तन :-

→ USA में जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित 2 विचारधारा है।

(A) रूढ़िवादी :-

→ रिपब्लिकन पार्टी जलवायु परिवर्तन - ग्लोबल वार्मिंग को खारिज करता है। जैसे- USA पेरिस समझौते से बाहर

→ भारत का दावा है कि अमेरिका विकसित देश के तौर पर अपने कर्तव्य से भाग रहा है।

→ उन्हें विकासशील व अल्पविकसित देशों को तकनीकी व वित्त उपलब्ध करवाना चाहिए।

* **उदारवादी विचारधारा :-**

→ डेमोक्रेटिक पार्टी भारत पर तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक होने का आरोप लगाती है।

→ भारत इसे अस्वीकार करता है क्योंकि भारत का प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन अभी भी बहुत कम है व भारत के विकासात्मक उद्देश्यों के लिए कार्बन उत्सर्जन की कुछ मात्रा आवश्यक है।

→ भारत अपनी नीति खुद तय करेगा यही जलवायु सम्बन्धी न्याय है।

THE NOTES HUB ★ 7300134518, 7610010004 All Competition Books ★ Notes are Available ★

सहयोग के क्षेत्र

* **राजनीतिक व सामरिक सहयोग :-**

→ भारत - अमेरिकी सम्बन्धों को वैश्विक सामरिक साझेदारी से परिभाषित किया जाता है।

→ दोनों देशों के बीच विभिन्न साझा मूल्य है।

जैसे-
- लोकतन्त्र
- मानवाधिकारों का संरक्षण
- नौवहन की स्वतंत्रता
- नियम आधारित व्यवस्था

→ राजनीतिक सहयोग के लिए सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व द्वारा समय-समय पर यात्रायें की जाती है।

नमस्ते ट्रम्प, हाउडी मोदी

→ मंत्रालय स्तर पर 50 से अधिक वार्ता मंच स्थापित किये गये।

→ सबसे महत्वपूर्ण = 2+2 वार्ता

अमेरिका, आस्ट्रेलिया, जापान, रूस

* 2+2 मंत्रीस्तरीय वार्ता :-

→ यह दोनों देशों के मध्य एक उच्चतम स्तरीय संस्थागत संवाद का एक प्रारूप है।

→ इस वार्ता में दोनों देशों के विदेश, रक्षा मंत्री या सचिव भाग लेते हैं।

→ भारत के साथ 2+2 संवाद है
- → अमेरिका
- → आस्ट्रेलिया
- → जापान
- → रूस

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610100034

* 1 = 2+2 = 2018 - COMCASA

* 2 = 2+2 = दिस. 2019

→ औद्योगीक सुरक्षा अनुलग्नक

→ यह भारत में निवेश करने वाली अमेरिकी रक्षा कंपनियों के हितों की रक्षा करता है।

* 3 = 2+2 वार्ता = BECA Oct = 2020

* 4 = 2+2 वार्ता = अप्रैल = 2022

→ रक्षा आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस डायलॉग का उद्घाटन

→ अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता व्यवस्था = अंतरिक्ष सहयोग हेतु

→ यूक्रेन संकट का अवलोकन

* 4 आधारभूत समझौते :-

→ सैन्य और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका ने भारत के साथ 4 समझौते पर हस्ताक्षर किये है।

(i) GSOMIA :- जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट = 2002
[सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा]

(ii) LEMOA :- लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट

→ 2016 में हस्ताक्षर

→ दोनों देश निम्नलिखित के लिए एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का प्रयोग

1. ईंधन प्राप्त करने हेतु
2. मरम्मत
3. आपदा प्रबन्धन
4. खोज व बचाव कार्यक्रम

THE NOTES HUB * All Competition Books * Notes are Available * 7300134518, 7610010084

(iii) COMCASA :- कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट
संचार संगतता और सुरक्षा समझौता = 6 sep 2018

→ सुरक्षित संचार चैनलों का प्रयोग

→ भारत द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा उपकरणों की अन्तर संचालनीयता और उच्चतम उपयोग

(iv) BECA :– बेसिक एक्सचेंज एंड कॉ ऑपरेशन एग्रीमेंट
[बुनियादी विनिमय व सहयोग समझौता]

→ इसके तहत दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के मध्य भू-स्थानिक जानकारी को साझा किया जायेगा।

→ भू-स्थानिक मानचित्र व चार्ट को साझा किया जायेगा।

→ UAVs सेटेलाइट व निगरानी विमानों से प्राप्त डाटा सूचनाओं को साझा करना।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010004

* हिन्द प्रशान्त क्षेत्र
(एशीया प्रशान्त क्षेत्र)

→ इंडो पैसेफिक क्षेत्र एक मानसिक मानचित्र परिकल्पना है।

→ यह एक महासागरीय क्षेत्र है जिसमें शामिल है –
- a) हिन्द महासागर
- b) प्रशान्त महासागर के हिस्से
- c) पूर्वी अफ्रीकी तट

→ इस क्षेत्र में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल है
1. द. चीन सागर
2. आसियान देश
3. मलक्का जलसंधि
4. गुआम द्वीप
5. मार्शल द्वीप

* वर्तमान में भारत प्रशांत क्षेत्र में शामिल

- 1. देश = 38
- 2. विश्व का क्षेत्रफल = 44%.
- 3. विश्व की जनसंख्या = 65%.
- 4. दुनिया की कुल GDP = 62%.
- 5. दुनिया का व्यापार = 46%.

* भारत और हिन्द प्रशान्त क्षेत्र :-

→ हिन्द महासागर इक्कीसवां महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पर है।

→ भारत इस पर प्रभुत्व स्थापित करने के साथ शान्ति, स्वीकृति व मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने का पक्षधर है।

QUAD

चतुष्कोणीय सुरक्षा वार्ता

4 = देश = अमेरिका भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया

2004 अनौपचारिक रूप से सूनामी के दौरान सहयोग > 2007 विदेश मंत्रियों की बैठक व चीन का विरोध > 2017 क्वाड का गठन

मार्च 2021 पहली वर्चुअल मीटिंग > सितम्बर 2021 USA में बैठक

* क्वाड के उद्देश्य :-

1. नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था, नौवहन की स्वतंत्रता और बाजार की एक उदार व्यवस्था सुनिश्चित करना।

2. समुद्री सुरक्षा

3. जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को संबोधित करना

4. क्षेत्र में निवेश के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना

5. ~~तनक~~ तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610001004

* महत्व :-

1. इसके केन्द्र में हिन्द-प्रशान्त का क्षेत्र है जो कि भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

2. इस क्षेत्र से महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग गुजरते है जो कि वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है।

3. इस क्षेत्र चीन द्वारा उत्पन्न विवाद खुले, मुक्त, समावेशी व समृद्ध हिन्द-प्रशान्त के लिए खतरा है।

4. यह नियम आधारित व्यवस्था को भी प्रभावित करता है।

5. ये देश तकनीक, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, आपदा प्रबंधन तथा मानवीय सहायता के क्षेत्र में सहयोग कर सकते है।

6. यह समूह भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में मदद कर सकता है।

* क्वाड की चुनौतियाँ :-

1. इस समूह के उद्देश्य व विजन स्पष्ट नहीं है।
2. हिन्द-प्रशान्त की परिभाषा को लेकर भी मतभेद है।
3. चीन के द्वारा इसे एशियाई नाटो की संज्ञा दी गई है।
4. भारत व रूस के सम्बन्ध भी इससे प्रभावित हुए है।
5. इन देशों के बीच भी कुछ विवाद बने हुए है
   - वैक्सीन आपूर्ति
   - जलवायु परिवर्तन

* आगे की राह :-

1. इस समूह की औपचारिक बैठके आयोजित की जानी चाहिए।
2. इसके सचिवालय का निर्माण किया जाना चाहिए।
3. इसके विजन व उद्देश्यों को स्पष्ट करना
4. अन्य देशों को भी इसमें शामिल किया जाये
   - आयरलैण्ड
   - इण्डोनेशिया
   - ओमान
5. आधारभूत ढाँचे को बढ़ावा देना।

* इंडो पैसिफिक तथा क्वाड :-

→ हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र एक व्यापक राजनीतिक-आर्थिक संकल्पना है जबकि क्वाड रणनीतिक और सैन्य परामर्श के लिए एक मंच है जिसमें भारत, USA, आस्ट्रेलिया व जापान शामिल है।

→ पूरे हिन्द प्रशान्त क्षेत्र में स्थिरता व समृद्धि सुनिश्चित व चीन का नियंत्रित करने हेतु इस सहयोग को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

* क्वाड शिखर सम्मेलन 2023

→ 20 मई 2023 को जापान के हिरोशिमा में

* हालिया वक्तव्य :-

→ भारत-प्रशान्त क्षेत्र के लिए स्थायी भागीदार

* पहल :-

1. स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति शृंखला = ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान व विकास
2. क्वाड अवसंरचना कैलोशीय प्रोग्राम = स्थायी अवसंरचना निर्माण हेतु
3. केबल (संचार) संपर्क और सहनीयता के लिए साझेदारी समूह

4. क्वाड निवेशक नेटवर्क को लॉन्च किया गया।

→ सामरिक प्रौद्योगिकियों में निवेश की सुविधा के लिए एक मंच।

→ प्रशान्त क्षेत्र के पलाऊ में छोटे पैमाने पर ORAN तैनाती के लिए क्वाड समर्थन।

* IPEF
भारत-प्रशान्त आर्थिक संरचना

* उद्देश्य :-

1. भारत-प्रशान्त क्षेत्र में स्थिरता, समावेशी आर्थिक विकास निष्पक्षता व प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से भागीदार देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना।

→ यह मुक्त व्यापार समझौता नहीं है।

→ इसके 4 स्तम्भ है -

1. व्यापार = निष्पक्ष व लचीला
2. आपूर्ति श्रृंखला
3. स्वच्छ अर्थव्यवस्था = ऊर्जा व आधारभूत संरचना
4. निष्पक्ष अर्थव्यवस्था = कराधान व भ्रष्टाचार विरोधी।

→ भारत स्तम्भ 1 का भाग नहीं।

→ आपूर्ति श्रृंखला के लिए भारत ने 3T का विचार दिया
- 1. ट्रस्ट
- 2. ट्रांसपेरेंसी
- 3. टाइमलीनेस

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610100004

ICET

महत्वपूर्ण व उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल

→ शुरुआत = भारत + अमेरिका द्वारा, मई 2022

→ नेतृत्व = दोनों की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों द्वारा

*** सहयोग के क्षेत्र :—**

1. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
2. क्वांटम
3. 5G / 6G
4. स्पेस
5. बायो-टेक
6. सेमी-कंडक्टर

अंतरिक्ष सहयोग

→ भारत - अमेरिका विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता = 2005

→ 2019 में 10 साल के लिए नवीनीकृत

→ निसार नामक संयुक्त परियोजना नासा व इसरो द्वारा विकसित की जा रही है।

[नासा - इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार]

→ मंगलयान के प्रक्षेपण के समय नासा के द्वारा गहरे अंतरिक्ष में संचार के लिए सहायता की गई।

→ भारत - USA 2016 में साइबर फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किये गये है।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610014054

✱ निर्यात नियंत्रण समूह :—

→ USA निर्यात नियंत्रण समूह में भारत की सदस्यता का समर्थन करता है।

1. NSG = परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह

स्थापना = 1974

सदस्य = 48

→ यह नाभिकीय सामग्री और नाभिकीय तकनीक के निर्यात को नियंत्रित करता है।

→ USA द्वारा भारत को विशेष छूट दिलवाई गई।

2. MTCR [मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण शासन]

स्थापना = 1987

सदस्य = 35

→ जून 2016 में भारत 35 वॉ सदस्य बना।

→ यह मिसाइल तकनीकों के निर्यात को नियंत्रित करता है जिनकी

1. मारक = 300 km से अधिक है

2. युद्ध भार क्षमता = 500 Kg से अधिक है।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010004

3. वासेनार अरेंजमेंट :-

स्थापना = 1996

सदस्य = 42

→ भारत 2017 में इसका 42 वॉ सदस्य बना।

→ यह परम्परागत हथियारों तथा द्विउपयोगी तकनीकों के निर्यात को नियंत्रित करता है।

→ 2023 में अध्यक्षता = भारत

4. ऑस्ट्रेलिया ग्रुप :-

स्थापना = 1985

सदस्य = 43

→ 43 वॉ सदस्य = भारत [2018 में]

→ यह जैविक व रासायनिक हथियारों के निर्यात को नियंत्रित करता है।

रक्षा सहयोग

→ 2005 में डिफेंस फ्रेमवर्क समझौता किया गया ।

→ 2015 में रक्षा प्रौद्योगिकी एवं व्यापार पहल नामक समझौता किया

→ USA ने 2016 में भारत को प्रमुख रक्षा सहयोगी

→ 2018 में STA-1 [रणनीतिक व्यापार प्राधिकरण] का दर्जा दिया ।

→ इसके तहत तकनीक हस्तान्तरण व रक्षा निवेश पर बल दिया गया ।

→ भारत पहला ऐसा देश है जो USA का सैन्य सहयोगी नहीं है और फिर भी STA-1 व प्रमुख सैन्य सहयोगी का दर्जा दिया गया है ।

*** मूलभूत समझौते :-**

1] GSMIA = 2002

2] LEMOA = 2016

3] COMCASA = 2018

4] BECA = 2020

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518

*** USA से किये प्रमुख रक्षा आयात :-**

1] C-130 J हरक्युलिस एयर क्राफ्ट

2] C-17 ग्लोबमास्टर

3] चिनूक हेलीकॉप्टर

4] अपाचे हेलीकॉप्टर

5] P8 I [पॉसाइडन एयरक्राफ्ट]

सैन्य अभ्यास

*** टाइगर ट्रिम्फ :-**

→ त्रिसेना मानवीय सहायता एवं आपदा राहत [HADR] अभ्यास

*** वज्र प्रहार :-**

→ विशेष सैन्य बलों का अभ्यास

*** युद्धाभ्यास :-**

→ सैन्य अभ्यास

*** मालाबार :-**

→ बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास

→ वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास - 1992 में शुरू

→ जापान = 2015 में शामिल

→ आस्ट्रेलिया = 2020 में शामिल

*** सी ड्रैगन**

QUAD + दक्षिण कोरिया
+ कनाडा

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010064

आतंकवाद के विरुद्ध अभियान

→ USA ने पाकिस्तान की आर्थिक मदद बंद कर दी व आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बनाया।

Financial Action Task Force
वित्तीय कार्रवाही कार्य बल [FATF]

स्थापना = 1989
सदस्य = 38

→ भारत भी इसका सदस्य है।

→ FATF आतंकवादी वित्तपोषण और मनी लांड्रिंग के खिलाफ कार्य करता है

* काली सूची :- विदेशी देशों के साथ कोई व्यापार नहीं व कोई निवेश नहीं।

* ग्रे लिस्ट :- इसमें निगरानी रखी जाती है।

→ पाकिस्तान को USA की मदद से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल [2018]

2022 - में सूची से हटाया

→ USA मदद - मसूद अजहर = अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी

* [व्यापारिक सम्बन्ध]
[आर्थिक]

→ 2022-23 में USA भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी

→ भारत से सर्वाधिक निर्यात USA में किया जाता है।

* व्यापार बढ़ाने हेतु समझौते :-

1. व्यापार नीति [ट्रेड पॉलिसी फोरम] मंच 2005 :-

→ दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रालयों के बीच सहयोग

2. भारत-USA सीईओ फोरम :-

→ सीधे निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए

3. इंडिया-USA कमार्शियल डायलॉग

4. USA - इंडिया - बिजनेस काउंसिल

5. इंडिया - USA इकॉनोमिक एंड फाइनेंसियल पार्टनरशीप [EFP] डायलॉग

* अमेरिका का वर्चस्व

- सैन्य शक्ति
- आर्थिक शक्ति के रूप में [संस्थागत]
- सांस्कृतिक शक्ति

→ विश्व राजनीति में यदि कोई देश इतना शक्तिशाली हो जाए कि वह अन्य देशों के राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों पर प्रभुत्व स्थापित कर ले तब इस अवधारणा को वर्चस्व कहते है।

* सैन्य शक्ति के रूप में :-

→ शीत युद्ध की समाप्ति के बाद USA ने यह वर्चस्व स्थापित किया।

→ 1990 में ईराक ने कुवैत पर आक्रमण किया।

→ अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद शीत खाड़ी युद्ध प्रारम्भ हो गया।

→ USA ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म और ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड लॉन्च किया।

→ उन्नत तकनीक के प्रयोग के कारण इसे कम्प्युटर युद्ध कहा जाता है।

→ इसे वीडियो गेम युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि इसे पूरी दुनिया में प्रसारित किया गया।

→ 1998 ई. में आतंकवादियों ने दार-उल-इस्लाम तंजानिया, नैरोबी - केन्या में अमेरिका दूतावास पर हमला किया।

→ अमेरिका ने ऑपरेशन इन्फाइनाइट रीच शुरू किया। व सूडान और अफगानिस्तान पर हवाई हमले किये गये।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010004

→ 11 सितम्बर 2001 को अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ।

→ USA ने ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम शुरू किया व अफगानिस्तान पर हमला किया व तालिबान को सत्ता से हटाया गया।

→ 2003 में USA ने Operation Iraqi freedom के तहत ईराक पर हमला किया।

→ सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया गया।

→ इस युद्ध का घोषित उद्देश्य नरसंहार के हथियारों को समाप्त करना था। लेकिन वास्तविक उद्देश्य ईराक के तेल संसाधनों पर कब्जा करना था।

* संस्थागत्मक [आर्थिक] शक्ति के रूप में :-

→ USA विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

→ वैश्विक वित्तीय संस्थाओं पर USA का प्रभुत्व है।

→ जैसे - विश्व बैंक
IMF

→ विश्व व्यापार में USA का हिस्सा लगभग 15% है। जिसमें संरक्षणवादी व उदारवादी नीतियों को प्रभावित किया जाता है।

→ WTO के निर्णय USA की सहमति से ही लिये जाते है।

→ वैश्विक भुगतानों में डॉलर का प्रयोग और अन्य देशों की मुद्रायें डॉलर पर निर्भर है।

→ USA ने अकादमिक क्षेत्र को भी प्रभावित किया है व इसने MBA की डिग्री को USA ने मान्यता दिलवाई।

* सांस्कृतिक शक्ति के रूप में :-

→ निर्मित सहमति विकसित करने की USA की क्षमता

→ USA के द्वारा विश्व में विभिन्न प्रकार की विचारधारायें प्रचलित की गई -

1. सफलता का सिद्धान्त
2. आधुनिकता की अवधारणा
3. लोकतांत्रिक शासन
4. मानवाधिकार
5. अच्छे जीवन का विचार

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010004

→ अन्य देशों के रहन-सहन, खान-पान आदि को USA द्वारा प्रभावित किया गया। जैसे - कोको कोला
जीन्स

→ अंग्रेजी भाषा की श्रेष्ठता को USA द्वारा स्थापित किया गया।

→ USA ने हॉलीवुड का उपयोग विचारधाराओं को फैलाने के लिए किया

अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिरोध :—

→ अमेरिकी संविधान शक्ति के पूर्ण शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त पर आधारित है। अर्थात् कार्यपालिका कभी भी सर्वशक्तिशाली निकाय नहीं बन सकता।

→ अमेरिकी समाज एक मुक्त समाज है जहाँ नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।

→ अतः लोग USA की सरकार पर दबाव बना सकते है।

→ USA के नाटो सहयोगी

→ वर्तमान में विश्व बहुध्रुवीयता की ओर अग्रसर हो रहा है अर्थात् अन्य शक्तियाँ भी अस्तित्व में आ रही है।

जैसे = BRICS

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010054

भारत की प्रतिक्रिया

साम्यवादी

→ US के साथ सक्रिय सम्बन्ध बनाये नहीं जाने चाहिए क्योंकि USA का वर्चस्व भारत को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

पूंजीवादी

→ हमें अमेरिका के साथ सक्रिय सम्बन्ध बनाने चाहिए, उनके वर्चस्व का लाभ उठाना चाहिए।

अन्य

→ भारत को बहुध्रुवीय विश्व के निर्माण के लिए कार्य करना चाहिए।

→ भारत की वर्तमान नीति पूंजीवादी तथा अन्य नीति पर आधारित है।

* प्रधानमंत्री की अमेरिका की राजकीय यात्रा

→ 21 जून — संयुक्त राष्ट्र महासभा न्यूयार्क में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह

* तकनीक :-

→ भारत - अमेरिका क्वांटम समन्वय तंत्र

→ AI के संयुक्त विकास के लिए $ मिलियन का अनुदान कार्यक्रम

→ साइबर सुरक्षा पर संयुक्त रूप से वित्त पोषित अनुसंधान परियोजना

→ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला व नवाचार साझेदारी

* रक्षा :-

→ भारत - ~~अमेरिकी~~ रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र

→ इंडस - एक्स क्रिटिकल एंड इमार्जिंग टेक्नोलॉजी पर अमेरिकी पहल का एक हिस्सा है।

→ जनरल इलेक्ट्रिक और हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत में GE-F 414 जेट इंजन का निर्माण करेंगे।

* अंतरिक्ष :-

→ NASA इसरो का मानव मिशन 2023 में सहयोग करेगा।

* आर्टेमिस समझौता :-

→ 13 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग व नासा द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया।

* 7 साझेदार देश :-

1. आस्ट्रेलिया
2. कनाडा
3. इटली
4. जापान
5. लक्जमबर्ग
6. UAE
7. UK

→ अंतरिक्ष अन्वेषण को निर्देशित करने के लिए यह एक गैर-बाध्यकारी सिद्धान्त है।

→ भारत आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27 वाँ देश बन गया।

* सिद्धान्त :-

1. शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष का उपयोग।
2. अंतरिक्ष वस्तुओं का पंजीकरण
3. अंतरिक्ष विरासत का संरक्षण
4. अंतरिक्ष का विसंधार्य
5. अंतरिक्ष मलबे का प्रबंधन

भारत - रूस सम्बन्ध

*** शीतयुद्ध की महत्वपूर्ण घटनाऐं :**

1. IRON CURTAIN
2. NATO - 1949
3. वार्सा पेक्ट
4. कोरीयायी युद्ध [1950-53]
5. क्यूबा मिसाइल संकट [1961]
6. बर्लिन की दीवार का निर्माण [1961]
7. वियतनाम युद्ध [1954-74]

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610100064

*** राजनीतिक पृष्ठभूमि**

→ 1917 ई. तक रूस में राजतंत्रात्मक शासन था।

→ 1917 में लेनिन के नेतृत्व साम्यवादी क्रांति हुई व सोवियत संघ की स्थापना हुई।

→ II द्वितीय WW के बाद विश्व में 2 महाशक्तियाँ थी - USA व USSR

→ दोनों देशों के बीच एक वैचारिक युद्ध हुआ

USA ↓ पूंजीवाद

USSR ↓ साम्यवाद

→ विभिन्न सैन्य सान्धियाँ की गई जैसे - NATO
बर्साय वार्सा पैक्ट

→ दोनों गुटों के द्वारा सैन्यकरण को बढ़ावा दिया गया इसे शीतयुद्ध कहा गया।

→ 1985 में मिखाईल गोर्बाचेव USSR का राष्ट्रपति बना।

→ इसने 2 नीतियाँ अपनाई

पेरेस्त्रोइका

→ यह रूसी भाषा का शब्द है।
अर्थ = पुनर्गठन

→ राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में पुनर्गठन किया गया।

* राजनीतिक क्षेत्र :- सत्ता का विकेन्द्रीकरण और अधिक शक्तियाँ सोवियतों को दी गई

* आर्थिक क्षेत्र :- बाजार पर सरकार का नियंत्रण कम हो गया।

ग्लासनोस्त

→ यह रूसी भाषा का शब्द है
अर्थ = खुलापन

→ रूस के समाज में खुलापन लाया गया तथा नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी।

→ प्रेस को सरकार की आलोचना करने का अधिकार दिया गया।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610100094

→ इन नीतियों के कारण सोवियतों में अलगाववादी आन्दोलन शुरू हुए।

→ अतः 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया।

→ 15 नये देश अस्तित्व में आये।

→ जिसमें सोवियत संघ का उत्तराधिकार रूस था।

→ रूस ने पूंजीवाद को अपना लिया। और इसी से शीत वैचारिक युद्ध समाप्त हो गया।

→ एंड ऑफ द हिस्ट्री = फ्रांसिस फुकुयामा

→ 1991 से 2000 के बीच रूस ने USA से अच्छे सम्बन्ध बनाने का प्रयास किया।

→ किंतु USA की प्रतिक्रिया सकारात्मक नहीं थी।

* भारत रूस सम्बन्ध :-

→ शीतयुद्ध के काल में भारत ने शुद्ध निरपेक्षता की नीति अपनाई परन्तु भारत का वैचारिक झुकाव USSR की ओर रहा।

→ कश्मीर मुद्दे पर USSR ने भारत का समर्थन किया।

→ भारत के द्वारा अधिकतर रक्षा उपकरण USSR से खरीदे गये।

→ 1971 में भारत और USSR के बीच शांति, मैत्री एवं सहयोग की संधि की गई। जिससे 1971 के युद्ध में सहायता मिली।

→ 1993 में संधि का नवीनीकरण किया गया।

→ 1991 के बाद सम्बन्ध तटस्थ रहे और 2000 के बाद पुनः सक्रिय हो गये।

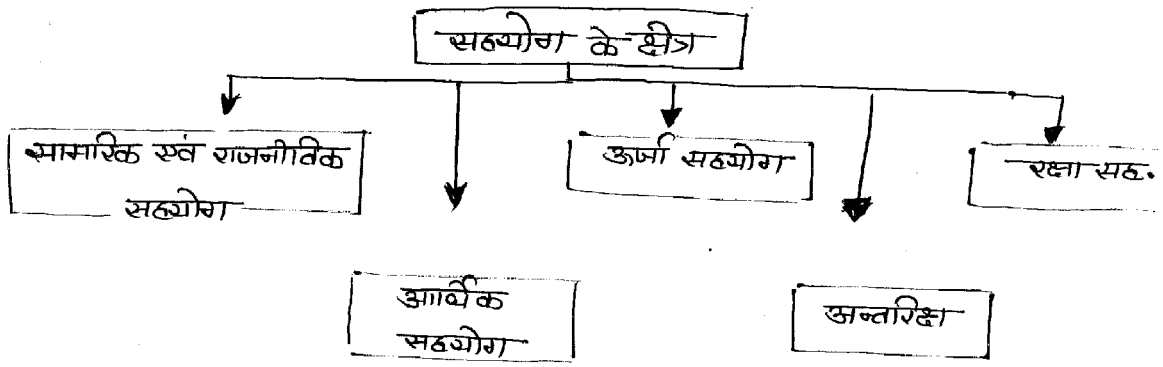

* सामरिक एवं राजनीतिक सहयोग :—

→ भारत एवं रूस के सम्बन्धों की विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी से परिभाषित किया

→ वर्ष 2000 से भारत व रूस के बीच शीखर सम्मेलन आयोजित किये जा रहे है जिसमें भारत के PM व रूस के राष्ट्रपति भाग लेते है।

→ यह सम्मेलन 1 वर्ष भारत में तथा 1 वर्ष रूस में होता है।

1.
* 20 वाँ शीखर सम्मेलन = 2019
व्लादिवोस्तक, रूस

→ भारतीय PM ने ईस्टन इकॉनोमिक फॉरम की अध्यक्षता की।

→ चीनी प्रभाव को कम करने के लिए —

1. रूस के सुदूर-पूर्व क्षेत्र के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए भारत 1 bq का निवेश करेगा।

(ii) चेन्नई व व्लादिवोस्तक के बीच एक शीपिंग लिंक स्थापित किया जायेगा।

→ वर्ष 2020 व 2021 में शिखर सम्मेलन कोरोना व समय के अभाव के कारण आयोजित नहीं किये जा सके।

→ लेकिन वास्तविक कारण भारत का USA की ओर बढ़ता झुकाव और रूस पर चीन का बढ़ता प्रभाव।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010024

* 21 वाँ शिखर सम्मेलन
2021

→ शांति, प्रगति व समृद्धि के लिए भारत-रूस साझेदारी

→ पहला भारत-रूस 2+2 संवाद

→ कलाश्निकोव राइफल्स के लिए समझौता = अमेठी, उत्तर प्रदेश में एके-203 राइफल बनाने के लिए संयुक्त उद्यम

→ सैन्य सहयोग के लिए समझौता - अगले दशक के लिए यानी 2021 से 2031 तक सैन्य प्रौद्योगीकी सहयोग

→ रेसिप्रोकाल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स [RELOS] (↑ सहयोग समझौता) पर आगे बढ़ना।

→ साइबर अटैक के लिए RBI और बैंक ऑफ रूस मिलकर काम करेंगे।

→ भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करेगा = USA के किसी भी डर के बिना S-400 वायु रक्षा प्रणाली सौदे के साथ आगे बढ़े। [CAATSA]

2. अन्तर सरकारी आयोग

पहला आयोग

→ भारत के विदेश मंत्री व रूस के उपप्रधानमंत्री भाग लेते है।

→ व्यापार, अर्थव्यवस्था विज्ञान, तकनीक सांस्कृतिक सहयोग के विषयों पर चर्चा

दूसरा आयोग

→ दोनों देशों के रक्षामंत्री भाग लेते है।

→ रक्षा सहयोग पर चर्चा

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610104004

2. ऊर्जा सहयोग

→ रूस के पास प्रचुर मात्रा में ऊर्जा संसाधन है और भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों लिए उनके आयात पर निर्भर है -

→ इसलिए इस क्षेत्र में स्वाभाविक साझेदारी स्थापित हो गई।

★ भारत की ONGC ने :-

1. निवेश = सखालिन गैस क्षेत्र तथा वेंकोर गैस क्षेत्र

2. अधिग्रहण = टॉम्स्क इंपीरियल एनर्जी लिमिटेड

→ रूस की रोजनेफ्त कम्पनी ने भारत के एस्सार समूह में 12.9 B$ का निवेश किया है।

→ यह भारत में आने वाले सबसे बड़े FDI निवेशों में से एक है।

→ भारत की GAIL और रूस की GAZPROM के बीच गैस आपूर्ति का समझौता हुआ है।

→ रूस ने कुडनकुलम [TN] में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया।

→ रूस की ROSATOM और भारत की NPCIL [न्यूक्लियर पावर कॉ-ऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड], रूपपुर [बांग्लादेश] में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रही है।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010004

3 रक्षा सहयोग

→ भारत द्वारा सर्वाधिक रक्षा उपकरण रूस से खरीदे गये है।

→ अब तक ये सम्बन्ध क्रेता-विक्रेता के थे लेकिन वर्तमान में संयुक्त उत्पादन व प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण पर जोर दिया गया है।

✱ विविधता के साथ आधुनिकीकरण :-

→ भारत अपने सैन्य उपकरणों के आधुनिकीकरण और विविधता लाने के लिए USA, फ्रांस और इजरायल जैसे देशों के से सैन्य उपकरण खरीद रहा है।

→ जैसे = भारतीय रक्षा खरीद - 2015 तक रूस से लगभग 70% से अधिक थी लेकिन 2016 - 2021 = 50% से कम है।

→ रूस से आयातित सर्वाधिक रक्षा उपकरण है –

रक्षा उपकरण

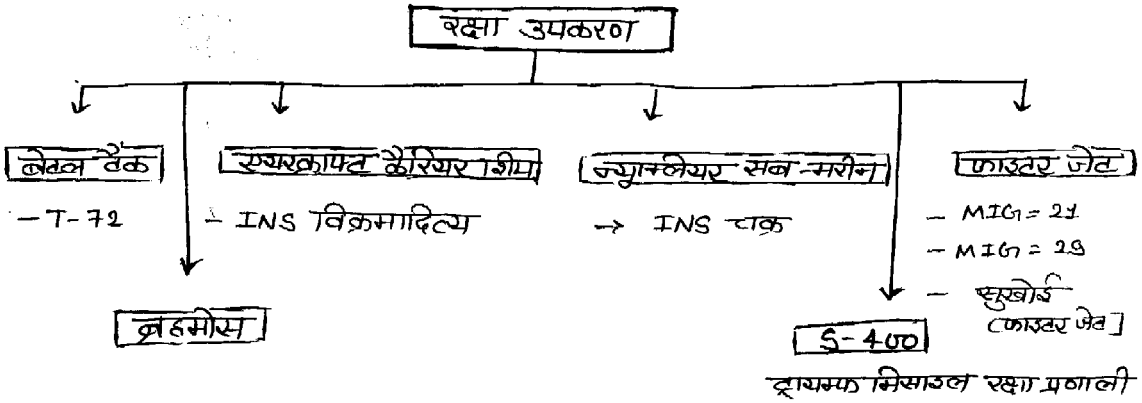

- बेटल टैंक
  - T-72
- एयरक्राफ्ट कैरियर शीप
  - INS विक्रमादित्य
- न्यूक्लियर सब-मरीन
  - → INS चक्र
- फाइटर जेट
  - MIG-21
  - MIG-29
  - सुखोई (फाइटर जेट)
- ब्रह्मोस
- S-400
  - ट्रायम्फ मिसाइल रक्षा प्रणाली

* संयुक्त उत्पादन = 1. ब्रह्मोस

→ भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल विकसित की।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books & Notes are Available ★ 7300134518, 7610100064

4. अन्तरिक्ष सहयोग

→ भारत के प्रारम्भिक उपग्रह रूस की सहायता से प्रक्षेपित किये गये

जैसे - 1] आर्यभट्ट 2] भास्कर

→ भारत के क्रायोजेनिक इंजन के विकास में रूस द्वारा मदद की गई।

7 इंजन तैयार अवस्था में दिये गये थे।

→ भारत के द्वारा गगनयान नामक मानव मिशन अन्तरिक्ष में प्रक्षेपित किया जायेगा जिसमें रूस मदद करेगा।

5. सांस्कृतिक सहयोग

→ रूस में भारतीय अध्ययन की एक मजबूत परम्परा रही है।

→ जवाहर लाल नेहरू सांस्कृतिक केन्द्र [मास्को]

→ नमस्ते रूस जैसे कार्यक्रम

6. आर्थिक सहयोग

→ भारत व रूस के बीच ऐतिहासिक रूप से गहरे सम्बन्ध है। परन्तु व्यापार में ये सम्बन्ध परिलक्षित नहीं होते है।

→ द्विपक्षीय व्यापार लगभग 10b$ है।

→ यह व्यापार रूस की ओर झुका हुआ है तथा मुख्यतः ऊर्जा संसाधनों पर केन्द्रित है।

*** कारण :-**

1. सीधे सम्पर्क का अभाव है।
2. दोनों देशों के बीच किसी भी मुक्त व्यापार समझौता नहीं किया गया
3. अधिकतर व्यापार मध्यस्थों [देश] के माध्यम से किया जाता है। जैसे- हीरे का व्यापार
4. उचित व्यापार अध्ययन नहीं किया गया। जिसके कारण एक-दूसरे [बाजार] के उत्पादों के प्रति जागरूकता का अभाव है।
5. दोनों देशों के बीच वित्तीय संस्थानों के बीच सहयोग का अभाव।

* आर्थिक क्षेत्र की समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास :-

1. अन्तर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा [INSTC] :-

→ भारत, ईरान व रूस द्वारा 2000 में INSTC की शुरुआत

→ जिसमें ईरान व कैस्पियन सागर के माध्यम से रूस व भारत को जोड़ा जा रहा है।

→ यह 7200 km लंबा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है।

→ वर्तमान में इसमें 13 सदस्य है

→ ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों के कारण यह योजना अभी तक पूरी नहीं हुई।

* चाबहार समझौता :-

→ अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन व पारगमन गलियारा = 2016

→ भारत + ईरान + अफगानिस्तान

→ चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान की सीमा पर जाहेदान तक रेललाइन व इसे जरंज - डेलाराम राजमार्ग से जोड़ना।

→ चाबहार दिवस = 31 जुलाई

2. चैन्नई - व्लादिवोस्तक समुद्री मार्ग

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010004

→ भारत व रूस के मध्य समझौता किया गया है कि मध्यस्थों की भूमिका को समाप्त करना।

→ 2025 तक व्यापार को बढ़ाकर $30b करना है।

→ सामरिक आर्थिक मंच की शुरुआत।

→ भारत व यूरेशीयाई संघ के मध्य मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत

* यूरेशियन आर्थिक संघ [EAEU]

→ यह एक क्षेत्रीय आर्थिक एकीकृत संगठन है।

स्थापना = 1 जनवरी 2015

→ यह अपनी सीमाओं के भीतर वस्तु, सेवा, पूंजी और श्रम (मानव) के मुक्त प्रवाह के लिए एक मंच है।

सदस्य :-
- 1] आर्मीनिया
- 2] बेलारूस
- 3] कजाकिस्तान
- 4] किर्गिज गणराज्य
- 5] रूस

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010034

* पूर्वी आर्थिक मंच :-

स्थापना = 2015

→ उद्देश्य :- रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना।

→ 2019 में भारत द्वारा 1 अरब डॉलर की क्रेडिट लाइन सुविधा

* चेचन्या विवाद :-

→ दक्षिण-पश्चिम रूस में स्थित चेचन्या प्रांत ने 1991 में एक लंबे अलगाववादी आंन्दोलन के बाद अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी।

प्रथम चेचन्या युद्ध = 1994-96

IInd चेचन्या युद्ध = 1999

→ रूस ने इसकी राजधानी ग्रोजनी पर अधिकार कर लिया।

→ इसके बाद रूस में विभिन्न आतंकवादी हमले हुए।

* RIC त्रिकोण [रूस, भारत, चीन] :-

→ यह विचार रूस ने दिया। क्योंकि तीनों देशों के बीच सहयोग के कई क्षेत्र है -

1. विश्व राजनीति में अमेरीकी वर्चस्व को कम करना।
2. बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण करना।
3. विकासशील देशों के हितों की रक्षा करना
4. ऊर्जा सहयोग
5. आतंकवाद के विरूद्ध सहयोग

→ वर्ष 2000 ई. में से तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठके आयोजित की जा रही है।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010004

* 18 वीं बैठक [RIC विदेश मंत्रियों की]

↳ 26 नवम्बर 2021

↳ भारत [मेजबानी = वर्चुअल]

→ भारत व चीन के विवादों के कारण यह त्रिकोण अधिक सफल नहीं रह

→ यह एक अनौपचारिक त्रिकोण है जो कि पिछले कुछ वर्षों में अस्तित्व में आय

रूस व चीन के मध्य बढ़ता व्यापार	रूस व पाक के मध्य बढ़ता व्यापार
1. S-400 ट्रायम्फ का रक्षा समझौता	→ MI-35 अटैक हेलिकॉप्टर का रक्षा सम.
2. ऊर्जा समझौता	→ संयुक्त युद्ध अभ्यास
3. रूस BRI परियोजना का सदस्य है।	→ नौसैनिक सहयोग का समझौता
4. चीन का निवेश रूस में बढ़ा है।	→ पाकिस्तान को SCO का सदस्य बनाना
5. 2022 - लिमिट लेस फ्रेंडशीप	→ ऊर्जा सहयोग

→ यदि यह त्रिकोण सशक्त होता है तो भारत के राजनीतिक व सामरिक हित प्रभावित हो सकते हैं।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610100064

→ यह त्रिकोण स्वाभाविक ना होकर परिस्थितिजन्य है -

* इसमें निम्न कमियाँ है –

1. चीन के साथ रक्षा व ऊर्जा समझौते ऐसे समय में किये गये जब रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए है।

2. दीर्घकाल में BRI योजना रूस के लिए भी एक चुनौती है। क्योंकि इससे मध्य एशीया में रूस का प्रभुत्व कम होगा।

3. पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध प्राथमिक स्तर के है दीर्घकाल के लिए पाकिस्तान विश्वसनीय सहयोगी नहीं है।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010004

यूक्रेन संकट

→ 1991 से पूर्व यूक्रेन USSR का भाग था। इसलिए यहाँ रूस का प्रभुत्व रहा।

→ रूस- यूक्रेन को यूरेशियाई आर्थिक मंच में शामिल करना चाहता था किन्तु यूरोपियन संघ इसका विरोध कर रहा था। इसलिए EU ने यूक्रेन को आर्थिक पैकेज दिया।

→ यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

→ इसके कारण यूक्रेन में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए।

→ रूसी भाषी लोगों की रक्षा के लिए रूस ने क्रीमिया पर आक्रमण कर दिया।

→ एक जनमत संग्रह के बाद रूस ने क्रीमिया पर अधिकार कर लिया।

→ इस घटना के बाद पाश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिये।

→ इसके बाद यूक्रेन के लुहान्सक व डोनेस्क प्रान्तों में अलगाववादी आन्दोलन शुरू हुए तथा यूक्रेन में गृहयुद्ध हो गया।

→ 21 फरवरी 2022 को रूस ने पूर्वी यूक्रेन में डोनेत्स्क व लुहान्सक को स्वतंत्र राज्यों के रूप में मान्यता दी।

→ इसने रूस को डोनेस्क व लुहान्सक को सैन्य सहायता प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया।

→ 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया व यूक्रेन ने मार्शल लॉ लगा दिया।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books & Notes are Available ★ 7300134518, 7610014004

✱ कारण :—

1. सोवियत संघ के पूर्व के गौरव लौटने की रूस की इच्छा
2. यूक्रेन मॉस्को व वाशिंगटन के बीच विवाद का कारण बन गया।
3. यूक्रेन की आंतरिक राजनीति में रूस और पाश्चमी देशों का अत्यधिक हस्तक्षेप
4. क्रीमिया की घटना पर अमेरिका (पाश्चिमी) की ओर से कोई प्रतिक्रिया न आने के कारण रूस को फिर आक्रमण करने का साहस मिल गया।

5. रूस की सीमा असुरक्षा – यदि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो नाटो रूस की सीमाओं के करीब आ जाएगा।

* प्रतिक्रिया :-

→ **पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया** = USA व EU ने यूक्रेन को वित्तीय सहायता प्रदान की।

→ विभिन्न मंचों पर रूस के खिलाफ संकल्प जैसे –

1. UN महासभा [UNGA]
2. UN सुरक्षा परिषद
3. IAEA [अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी]
4. FATF

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010004

→ भारत सहित अन्य देशों पर दबाव बढ़ाने के लिए प्रतिबंधों व कूटनीति का प्रयोग

→ यूक्रेन को अधिक उन्नत हथियारों की आपूर्ति –

A. USA = अब्राम्स टैंक

B. जर्मनी = लैपर्ड 2 टैंक

→ USA व EU ने रूसी बैंकों को सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन [SWIFT] मैसेजिंग सिस्टम से बाहर कर दिया।

* **SWIFT** = यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वित्तीय संस्थानों को धन हस्तान्तरण जैसे वित्तीय लेनदेन करने में सक्षम बनाता है।

* भारत की प्रतिक्रिया :—

1. भारत तटस्थ है सक्रिय निष्क्रिय नहीं।
2. भारत उस पर कार्यवाही करेगा जो भारत के हित में है क्योंकि भारी स्वतंत्र विदेश नीति है।
3. भारत कूटनीति और संवाद के रास्ते का आह्वान करता है।
4. भारत दोनों देशों के बीच संघर्ष को समाप्त करने के सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करता है।
5. भारत सभी प्रस्तावों में मतदान से दूर रहा।

* अपवाद :—

* 26 अगस्त 2022 :— पहली बार भारत ने UNSC में जेलेंस्की को वीडियो कांफ्रेंस से रोकने के रूस के प्रस्ताव के विरुद्ध मत दिया

* SCO शीखर सम्मेलन :— 16 सित. 2022

समरकन्द [उज्बेकिस्तान]

भारतीय PM = अब युद्ध का युग नहीं है।

* **G7 शिखर सम्मेलन** = हिरोशिमा, 20 मई 2023

→ भारतीय PM = भारत युद्ध को समाप्त करने के लिए जो कुछ भी कर सकता है वह करेगा।

* **भारत पर प्रभाव :-**

* **राजनीतिक प्रभाव :-**

→ भारत-रूस, भारत - USA तथा अन्य देशों से सम्बन्ध बढ़ते है।

→ भारत पहले भारत के हित के साथ स्वतंत्र विदेश नीति के मध्यम मार्ग का अनुसरण कर रहा है।

* **आर्थिक प्रभाव**

→ रूसी तेल सस्ता है इसलिए भारत विदेशी मुद्रा भंडार बचा रहा।

→ आपूर्ति श्रृंखला गड़बड़ा गई है जिससे मुद्रा स्फीति बढ़ गई लेकिन भारत इस युद्ध के बावजूद आत्मनिर्भर व सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन रहा है।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010064

* **रक्षा :-** भारत का रक्षा क्षेत्र रूसी आयात पर निर्भर है इसलिए उपकरणों और हथियारों के उन्नयन में देरी होती है।

* **कूटनीति :-** भारत 2023 में SCO, G20, शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है इसलिए भारत कठिन लेकिन प्रभावशाली स्थिति में है।

* प्रवासी संकट :-

→ यूक्रेन में पढ़ने वाले भारतीय छात्र युद्ध के कारण फँसे हुए थे।

→ भारत ने उन्हें यूक्रेन से वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया। ऑपरेशन कावेरी = सूडान में फँसे छात्रों को भारत लाने के लिए

* विश्व पर प्रभाव :-

* राजनीतिक :-

→ विश्व व्यवस्था बदल गई है।

→ USA, ब्रिटेन व EU पश्चिमी देशों ने यूक्रेन का पक्ष लिया।

→ चीन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश रूस का समर्थन करते है।

* आर्थिक :-

→ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला अस्तव्यस्त - महंगाई बढ़ी

→ रूसी प्राकृतिक गैस व तेल, यूक्रेन का गेहूँ और काले सागर के अन्य व्यापारिक चैनल बाधित हुए।

→ रूसी गैस व तेल पर यूरोपीय निर्भरता से मुद्रा स्फीति बढ़ी जिससे यूरोप में मंदी शुरू।

* पर्यावरण :-

→ बम हथियारों के प्रयोग से जंगलों, नदियों और समग्र पर्यावरण का प्राकृतिक क्षरण होता है।

→ यूक्रेन के उर्वर मैदान नष्ट हो गये जो दुनिया की गेहूँ/रोटी की की टोकरी हुआ करती है।

* परमाणु :-

→ रूस ने उकसाने पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी दी

* मानवाधिकार :-

→ बड़े लोग, बच्चे युद्ध के कारण व्यथित है।

→ यूरोप व एशिया में शरणार्थी संकट।

* विभिन्न समझौते :-

1. मिन्स्क - 1 :-

सितम्बर = 2014

→ त्रिपक्षीय समझौता

→ यूक्रेन, रूस व यूरोप सुरक्षा एवं सहयोग संगठन [OSCE]

→ यूक्रेन व रूस समर्थित विद्रोहियों के बीच संघर्ष विराम पर सहमति।

* मिन्स्क - 2 :-

फरवरी = 2015

→ 12 सूत्रीय समझौते

→ रूस, यूक्रेन, डोनेत्स्क, लुहांत्स्क और ~~on~~ OSCE
[यूरोप सुरक्षा एवं सहयोग संगठन]

→ तत्काल युद्ध विराम पर सहमति

NATO

→ उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन

→ नाटो का गठन यूरोप व उत्तरी अमेरिका के 12 देशों ने 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डी.सी में किया था।

→ इसे वाशिंगटन सन्धि भी कहा जाता है।

→ सदस्य = 31.

→ मुख्यालय = ब्रुसेल्स, बेल्जियम

→ नाटो में किसी देश को आमंत्रित या शामिल करने का निर्णय उत्तरी अटलांटिक परिषद द्वारा लिया जाता है।

* सन्धि का अनुच्छेद = 5

→ यदि किसी देश पर सशस्त्र हमला होता है तो इसे सभी सदस्यों के खिलाफ हमला माना जाता है।

* नाटो के उद्देश्य

→ राजनीतिक व सैन्य तरीकों से अपने सभी सदस्य देशों की स्वतंत्रता व सुरक्षा की रक्षा करना

* राजनीतिक उद्देश्य :-

→ लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा

* सैन्य उद्देश्य :-

→ यदि कूटनीतिक प्रयास विफल होते है तो संकट को हल करने के लिए सैन्य शक्ति का उपयोग किया जायेगा।

नाटो क्लास

→ यह वैश्विक रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक सुरक्षा परिषद है।

→ इसमें नाटो व 5 साझेदार राष्ट्र शामिल

5. आस्ट्रेलिया
2. न्यूजीलैण्ड
3. जापान
4. इजरायल
5. द. कोरिया

यूरोपीय संघ

→ यह एक क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन है।

सदस्य = 27

→ विश्व जनसंख्या = 7.5%.

GDP = 22.5%

→ वस्तु
सेवा
निवेश
मानव संसाधन
→ का मुक्त प्रवाह

→ इन देशों में साझा रक्षा व विदेश नीति होती है।

✳ उद्देश्य :-

→ यूरोप में शान्ति व लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना।

→ यूरोपीय संघ के सभी नागरिकों को बिना आंतरिक सीमाओं के स्वतंत्रता सुरक्षा और न्याय प्रदान करना।

✳ पृष्ठभूमि :-

* 1951 :- पेरिस सन्धि → यूरोपियन कोल व स्टील कम्युनिटी की स्थापना

* 1957 :- रोम संधि → यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना (6 सदस्य)

* 1967 :- दोनों संस्थाओं को विलय कर दिया गया।

* 1973 :- ब्रिटेन सदस्य बना

* 1993 :- मास्ट्रिच सन्धि → यूरोपीय संघ की स्थापना

→ यूरोपीय नागरिकता का सिद्धान्त अस्तित्व में आया।

* 1998 :- मौद्रिक संघ की स्थापना

* 2002 ई. = 12 देशों ने अपनी मुद्रा के रूप में यूरो को अपनाया।

→ इन देशों को यूरोजोन देश कहा जाता है।

* 1985 :- शेंगेन समझौता → 1995 में लागू - EU का संविधान

→ यह ऐसा मुक्त क्षेत्र है जिसमें 26 देश है।

→ 22 देश ऐसे है जो यूरोपियन संघ शेंगेन दोनों के सदस्य है।

* 2007 :- लिस्बन सन्धि → 2009 में लागू

→ EU का वर्तमान स्वरूप इसी सन्धि से आया।

→ यूरोपीय संघ के 7 अंग है -

1. यूरोपियन परिषद :-

→ यह निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है।

→ यह यूरोपीय संघ को राजनीतिक दिशा प्रदान करती है।

2. यूरोपीय संघ परिषद :-

→ यह मंत्रीमंडल की तरह कार्य करती है।

→ यह आज्ञा रक्षा व विदेश नीति तैयार करती है।

3. यूरोपीय संसद :-

→ कानून निर्माण व बजट पारित करना

4. यूरोपियन आयोग :-

→ यह नौकरशाही की तरह कार्य करती है

→ उपरोक्त 4 संस्थाओं का मुख्यालय → ब्रुसेल्स, बेल्जियम

→ जिससे यूरोपीय संघ की राजधानी कहा जाता है।

5. यूरोपीय केन्द्रीय बैंक :-

→ मौद्रिक नीति का निर्माण

फ्रैंकफर्ट, जर्मनी

6. यूरोपियन न्यायालय :-

→ कानूनों की व्याख्या करना।

→ विवादों का निपटारा करना।

→ मुख्यालय = लक्समबर्ग

7. अंकेक्षक :-

कार्य = अंकेक्षण

मुख्यालय = लक्समबर्ग

BREXIT

देश	राष्ट्र	राज्य
भौगोलिक	सांस्कृतिक	राजनीतिक
इकाई	इकाई	इकाई

→ UK स्वायत्त 4 राष्ट्रों से मिलकर बना है — इंग्लैण्ड
वेल्स
स्कॉटलैण्ड
उत्तरी आयरलैण्ड

→ 31 जनवरी 2020 → ब्रिटेन आधिकारिक तौर पर EU से बाहर निकल गया।

✱ यूरोपियन संघ की स्थापना :- समस्याएं

1. यूरोपियन संघ की आर्थिक वृद्धि दर अधिक नहीं है।

2. 2011 में यूरोपियन देशों में आर्थिक संकट आया जिसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है।

→ ग्रीस जैसे देश दिवालिया।

3. यूरोप में आतंकवाद में वृद्धि

4. शरणार्थी संकट -

(i) 2015 में पश्चिमी एशिया व उत्तरी अफ्रीका से यूरोप पहुँचे

(ii) रूस - यूक्रेन युद्ध

(iii) शरणार्थी मानव तस्करों के शिकार हो जाते है।

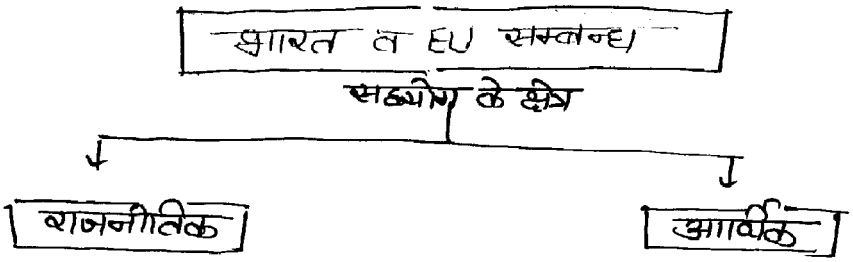

1. राजनीतिक सहयोग :-

→ भारत - EU की रणनीतिक साझेदारी आधारित है -

1. लोकतंत्र के प्रति साझा प्रतिबद्धता
2. मौलिक स्वतंत्रता
3. कानून का शासन व बहुपक्षवाद

→ 1994 = सहयोग समझौता

2000 = शीखर सम्मेलन की शुरुआत

2004 = सामरिक साझेदारी

* 15 वाँ शीखर सम्मेलन
जुलाई = 2020 (वर्चुअल)

* दृष्टि दस्तावेज :- यूरोपीय संघ - भारत सामरिक साझेदारी : 2025 के लिए रोडमैप

→ 1. असैन्य (नागरिक) परमाणु समझौता

2. → जलवायु परिवर्तन पर सहयोग

3. → विज्ञान व प्रौद्योगिकी समझौते का नवीनीकरण

* भारत व EU के नेताओं की बैठक :-

→ पोर्टो, पुर्तगाल में = हाइब्रिड मीटिंग = 8 मई 2021

→ पहली बार = EU + 27 प्रारूप में भारत के साथ बैठक

* 3 प्रमुख मुद्दों पर हुई चर्चा :-

1. विदेश नीति और सुरक्षा
2. कोविड-19 जलवायु व पर्यावरण
3. व्यापार कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी

→ मुक्त व्यापार समझौतों के लिए बातचीत फिर से शुरू करना ·

→ कनेक्टिविटी पार्टनरशीप लागू किया गया
- ऊर्जा
- परिवहन
- लोगों से लोगों की कनेक्टिविटी
- डिजीटल

THE NOTES HUB ★ All Competition Books & Notes are Available ★ 7300134518, 7610101004

2. आर्थिक सम्बन्ध :-

→ यूरोपीय संघ व भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 88 अरब डॉलर का है

→ यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है जबकि भारत EU का 9'वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार

*BTIA :-

→ व्यापार को बढ़ाने के लिए FTA पर बातचीत की जा रही है। जिसे ब्रोड बेस्ड ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट एग्रीमेन्ट कहा जाता है।

→ BTIA के लिए बातचीत 2007 से 2013 के बीच हुई थी। लेकिन 2021 तक निष्क्रिय रही।

→ 2021 से व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय संवाद स्थापित किया जा रहा है।

व्यापार और निवेश उच्च स्तरीय वार्ता

→ 17 जून 2022

→ ब्रुसेल्स, बेल्जियम

→ भारत EU ने FTA के लिए औपचारिक रूप से बातचीत फिर से शुरू की।

→ एक स्टेंडअलोन निवेश संरक्षण समझौता

→ भौगोलिक संकेतक समझौता

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610100004

भारत - यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद

→ पहली मंत्रिपरिषद बैठक = 16 मई 2023 को
ब्रुसेल्स बेल्जियम

→ परिषद सुरक्षा व समृद्धि के लिए कार्य करेगा।

★ सहयोग का क्षेत्र :-

1. हरित प्रौद्योगिकी
2. कनेक्टिविटी
3. लचीली आपूर्ति श्रृंखला

→ तीन कार्यवाही समूह की स्थापना = परिषद के अन्तर्गत

1. सामरिक प्रौद्योगिकी डिजिटल शासन और डिजिटल कनेक्टिविटी
2. हरित और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ
3. व्यापार और निवेश

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610100024

★ आर्थिक सम्बन्धों में चुनौतियाँ :-

→ EU ऑटोमोबाइल व शराब को FTA में शामिल करना चाहता है। लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है।

→ क्योंकि यह घरेलू उद्योगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।

→ यूरोपीय संघ FDI नियमों में और अधिक छूट चाहता था।

→ निवेश संबंधी विवादों के लिए यूरोपीय संघ सीधे अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थता चाहता है।

→ भारत डेटा सिक्योर कंट्री का दर्जा मांग रहा है।

→ WTO के स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता सम्बन्धी आयों के तहत भारत के खाद्य उत्पादों पर अक्सर प्रतिबंध लगा दिया जाता है।

1. अल्फांसो आम
2. जेनेरिक दवाएँ

भारत व EU के बीच विवाद

1. EU की मानवाधिकार संबंधी विवाद :-

→ प्रारम्भ में यूरोपीय संसद ने जम्मु कश्मीर व नागरिकता संशोधन आदि. के मुद्दे पर भारत सरकार की आलोचना की।

→ EU ने रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत की आलोचना की।

2. आनुवांशिक रूप से संशोधित चावल

→ यूरोप ने भारतीय चावल को GM फसल बताते हुए खारिज कर दिया लेकिन भारत ने इसका विरोध किया।

→ क्योंकि भारत व्यावसायिक रूप से चावल नहीं उगाता

3. रूस-यूक्रेन युद्ध :

→ EU ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिये।

→ परन्तु भारत रूस से व्यापार कर रहा है।

→ इससे भारत व EU के रिश्ते प्रभावित हुए है।

→ EU द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि भारत अप्रत्यक्ष रूप से रूस की मदद कर रहा है।

भारत - पाकिस्तान सम्बन्ध

✱ पाकिस्तान की समस्यायें -

→ कमजोर लोकतांत्रिक मुल्यों के कारण बार - बार सैन्य शासन

(a) 1958 - 69 = जनरल अयुब खाँ

(b) 1967 - 71 = याह्या खाँ

(c) 1978 - 88 = जिया उल हक

(d) 1999 - 2008 = परवेज मुशर्रफ

→ विदेश नीति = भारत विरोधी एजेंडे पर आधारित

→ आतंकियों का शरणगाह

→ आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610100084

पाकिस्तान में सत्ता के एक से अधिक केन्द्र

- सरकार
- सेना
- ISI
- आतंकवादी संगठन
- धार्मिक नीति

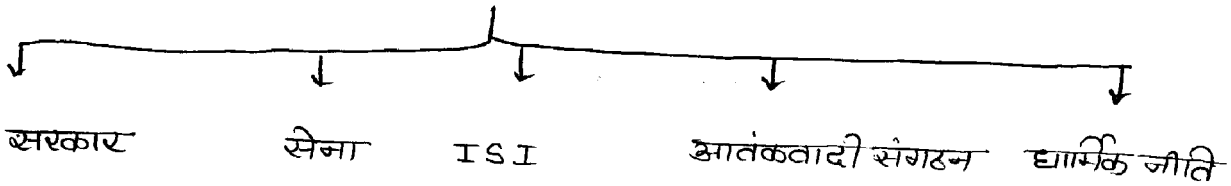

→ इससे बातचीत की प्रक्रिया बाधित है।

* भारत व पाकिस्तान के मध्य विवाद :-

1. कश्मीर मुद्दा :-

→ स्वतंत्रता के समय J & K पर हरिसिंह का शासन था।

→ विलय के लिए 2 प्रकार के समझौते किये गये -

(1) SSA (Stand still Agreement) (2) IOA (Instrument of Accession

→ यथा स्थिति बनाये रखने के लिए अस्थाई समझौता (~~विलय पत्र~~)

→ सम्प्रभुता स्थाई समझौते के माध्यम से हस्तान्तरित (विलय पत्र)

→ 26 Oct 1947 :- J & K का IOA के जरिए भारत में विलय

→ 27 Oct 1947 :- भारत व पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू

→ 1 जनवरी 1948 :- भारत ने इस मुद्दे को UN में उठाया।

→ UN ने 5 सदस्य आयोग का गठन किया।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610100004

UNCIP = भारत - पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग

→ संघर्ष विराम की घोषणा

→ सैन्य निरीक्षण दल का गठन

→ दोनों देश अपने सैनिकों को हटा लेंगे और भारत कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पर्याप्त बल रख सकता है।

→ उपरोक्त शर्तों को पूरा करने के बाद एक जनमत संग्रह आयोजित किया जाना चाहिए।

→ भारत व पाक ने उन सिफारिशों को खारिज किया।

* 3 अन्य प्रयास भी किये गये, किन्तु असफल रहे

- मैक नॉटन आयोग
- ओवन डिक्सन आयोग
- ग्राहम आयोग

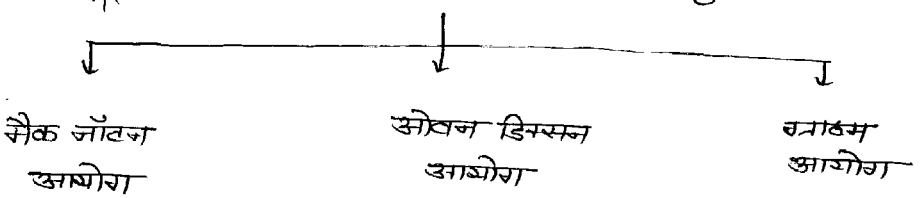

— अनुच्छेद - 370 —

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010064

* दिल्ली समझौता - 1952 :-

→ भारतीय संविधान के तहत J&K को विशेष दर्जा

→ 1954 में अनु 35(A) जोड़ा गया।

370 से पहले	370 के बाद
→ J&K को विशेष अधिकार	→ कोई विशेष भारतीयों नहीं
→ दोहरी नागरिकता	→ एकल नागरिकता
→ अलग झंडा (J&K)	→ झंडा = तिरंगा
→ ST/SC के लिए अलग आरक्षण X	→ SC/ST आरक्षण के पात्र होंगे
→ दूसरे राज्य के भारतीय नागरिकों को J&K में जमीन या संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं।	→ दूसरे राज्य के ~~लिए~~ लोग J&K में जमीन/संपत्ति खरीद सकेंगे।
→ RTI लागू नहीं	→ RTI लागू होगा
→ विधानसभा का कार्यकाल	→ केन्द्र शासित प्रदेश J&K

* 1965 का युद्ध

अप्रैल-1965 – पाकिस्तान का कच्छ के रन पर हमला

* ~~अप्रैल~~

* 5 अगस्त 1965 = ऑपरेशन जिब्राल्टर पाक का J&K पर हमला

* 4 Sep. 1965 – ऑ. ग्रैंड स्लैम छंब व अखनूर पर हमला (J&K)

ताशकंद समझौता

(10 जनवरी 1966)

→ USSR की मध्यस्थता में

→ कश्मीर विवाद के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थता

→ सेना 5 अगस्त 1965 से पहले की स्थिति में चली जायेगी

→ युद्धबंदियों की रिहाई

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518

शिमला समझौता

→ 2 जुलाई 1972

भारत = इंदिरा गाँधी

पाक. = जुल्फिकार अली भुट्टो

→ कश्मीर विवाद का कोई अन्तर्राष्ट्रीयकरण नहीं

→ LOC को परिभाषित किया गया।

→ युद्धबंदियों को रिहा किया गया।

→ युद्ध में अधिग्रहित भूमि वापस की जायेगी।

→ बांग्लादेश > एक स्वतंत्र राज्य

→ विज्ञान - प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010004

*** कश्मीर में अलगाववाद :-**

→ युद्धों में पराजित होने के बाद पाकिस्तान की नीति में परिवर्तन हुआ और उसने कश्मीर में अलगाववाद व आतंकवाद भड़काना शुरू किया

→ कश्मीर में आतंकी गतिविधियाँ 1989 में शुरू

विभिन्न समूह

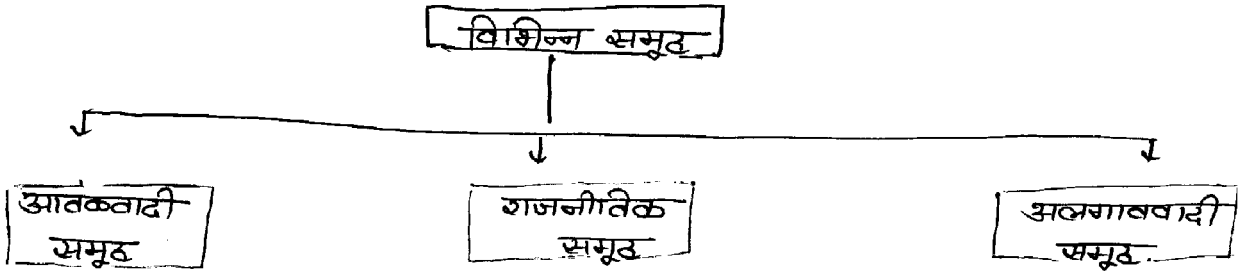

- **आतंकवादी समूह**
  - → मुख्य उद्देश्य भारत से अलग होना व हिंसा का समर्थन करना
  - जैश ए मोहम्मद
  - हिज्ब उल मुजाहिद्दीन
  - लश्कर ए तैयबा
- **राजनीतिक समूह**
  - NC
  - PDP
- **अलगाववादी समूह**
  - जम्मू कश्मीर के समाज में रहकर वह भारत में अलगाववाद को भड़काते है।
  - हुर्रियत कांफ्रेंस
  - JK लिबरेशन (JKLF)

सिन्धु नदी जल विवाद

→ 19 सितम्बर 1960

मध्यस्थता = विश्व बैंक

→ सिन्धु व उसकी सहायक नदियों को 2 क्षेत्रों में बाँटा गया।

1] पूर्वी नदियाँ :-

→ रावी, व्यास, सतलज

→ ये नदियाँ भारत को दी

2] प. नदियाँ :-

→ सिन्धु, झेलम, चेनाब — पाकिस्तान

→ लेकिन भारत प. नदियों के पानी का उपयोग भी कर सकता है।

- पेयजल
- सीमित क्षमता की जल विद्युत
- नौवहन

→ कुल पानी का 80% पानी पाकिस्तान को तथा 20% भारत को।

→ इसे लागू करने के लिए सिन्धु जल आयोग का गठन किया गया

→ विवाद समाधान के लिए एक तंत्र दिया गया।

विवाद — 1. समाधान
प्रश्न — 2. स्थायी सिन्धु जल आयोग
मतभेद — 3. निष्पक्ष विशेषज्ञ
विवाद — 4. मध्यस्थता के स्थायी न्यायालय

* वर्तमान परिदृश्य :-

→ भारत अपने हिस्से के जल का केवल 95% उपयोग करता है।

→ जल के पूर्ण उपयोग के लिए निम्नलिखित परियोजनाएँ विकासित

1. शाहपुरकंडी
2. उझ बाँध
3. रावी व्यास लिंक नहर

→ इस समझौते का झुकाव पाक की ओर है इसलिए इस पर बातचीत की जानी चाहिए।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books & Notes are Available ★ 7300134518, 7610100044

* किशनगंगा जलविद्युत परियोजना :-

→ किशनगंगा (नीलम) नदी पर

→ झेलम की सहायक नदी गुरेज लद्दाख से निकलती है।

→ भारत ने बांदीपुर में 330MW की पनबिजली जल विद्युत परियोजना विकसित की।

→ पाक. ने इस पर आपत्ति जताई लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थता ने फैसला भारत के मत में दिया।

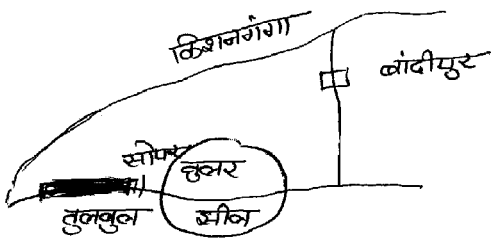

तुलबुल बैराज

→ झेलम नदी सोपोर शॉत से बारहमुल्ला तक नौगम्य है लेकिन सर्दियों में नदी में पानी की उपलब्धता कम हो जाती है जो नौवहन को प्रभावित करती है।

→ इस समस्या के समाधान के लिए भारत ने तुलबुल बैराज बनाने का निर्णय लिया।

→ लेकिन पाक की आपत्ति के बाद 1987 में इस परियोजना को रोक दिया गया।

→ उरी व पुलवामा हमलों के बाद भारत ने इस परियोजना को फिर से शुरु करने का फैसला दिया।

बगलिहार पॉवर विवाद

→ चिनाब नदी पर

कुल क्षमता = 900 MW

→ पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति जताई और 3 तटस्थ विशेषज्ञ (स्विस इंजीनियर रेमंड लेफाइट) ने अपनी रिपोर्ट में कुछ मामूली बदलावों का सुझाव दिया।

→ जैसे- बाँध की ऊँ. को कम करना

भण्डारण क्षमता को कम करना

→ भारत ने इन परिवर्तनों को स्वीकार किया व विवाद सुलझ गया

अन्य जल विवाद

* विवाद	नदी
1. पाकदुल	मरुसुदन नदी [सभी चिनाब की सहायक]
2. रातले	चिनाब
3. लोअर निम्नकलई	चिनाब
4. मीनार नाला	चन्द्रभागा

सरक्रीक विवाद

→ 96 Km लंबा दलदली मुहाना

→ 1908 में कच्छ के शासकों व सिंध के नवाब के बीच विवाद को सुलझाने के लिए ब्रिटिश अधिकारी सरक्रीक को नियुक्त किया गया

→ उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कुछ विवादित नक्शों को प्रयोग किया

→ जिनमें पूर्वी किनारे - हरी रंग की लाइन से दर्शाया गया।

→ पाकिस्तान के अनुसार यह अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है।

→ भारत ने इसे खारिज किया।

→ भारत के अनुसार थालवेग सिद्धान्त का प्रयोग करना चाहिए।

* थालवेग सिद्धान्त :-

→ यदि कोई जल निकाय 2 देशों के बीच स्थित है तो सीमा जल निकाय के मध्य (चैनल) से गुजारी जायेगी।

* महत्व :-

1. इस क्षेत्र में तेल, गैस व मत्स्य के विशाल संसाधन उपलब्ध है।
2. इस क्षेत्र का उपयोग मुम्बई हमले जैसी आतंकी गतिविधियों में किया गया है।

सियाचीन विवाद

→ यह दुनिया का सबसे कठिन युद्ध मैदानों में से एक है।

→ -40°c = तापमान गीर जाता है।

→ औसत ऊँ - 3000 - 4000 m है।

→ LOC को 1972 AD में NJ9842 बिन्दु तक परिभाषित किया गया → लेकिन इसके बाद यह स्पष्ट नही है।

→ पाक का दावा है कि -

LOC काराकोरम पास तक है लेकिन भारत के अनुसार यह सालटोरो रिज की ओर है।

→ इसके बीच का क्षेत्र = सियाचीन

* महत्व :-

→ यह रणनीतिक रूप से अक्साई चीन व शाक्सगाम घाटी के बीच स्थित है

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610110004

* <u>ऑपरेशन मेघदूत</u> :– 1984 AD

→ भारत ने उस पर अधिकार ~~कर~~ कर लिया – भारत के नियंत्रण में

करतारपुर कॉरिडोर

→ करतारपुर गुरुद्वारा सिक्ख धर्म में पवित्र है क्योंकि गुरु नानक ने अपने आखरी 18 साल यहीं बिताये थे।

→ गुरुद्वारा दरबार साहिब [पाकिस्तान] व गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक (भारत) को जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर विकसित किया गया।

→ उस गलियार में वीजामुक्त एवं पासपोर्ट मुक्त प्रवेश उपलब्ध है।

→ कुल लंबाई = 6 किमी. (4 पाक – 2 भारत)

→ <u>महत्व</u> :– सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करना

→ <u>खामी / कमी</u> :– भारत में खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010084

आर्थिक सम्बन्ध

→ 1996 - भारत ने पाक को MFN का दर्जा दिया

→ विश्व व्यापार संगठन के तहत मोस्ट फेवर्ड नेशन सिद्धान्त है जो सभी व्यापारिक भागीदारों के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करता है।

→ द्विपक्षीय व्यापार करीब 2 अरब डॉलर का था।

→ 16 फरवरी 2019 (पुलवामा हमले के बाद) भारत ने सभी पाकिस्तानी सामानों पर 200% सीमा शुल्क लगाया।

→ 7 अगस्त 2019 = पाक ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार निलंबित किया।

→ 16 फरवरी 2020 - भारत MFN का दर्जा वापिस ले लिया।

भारत – बांग्लादेश सम्बन्ध

* 1947 = पाकिस्तान पूर्वी व पश्चिमी पाक में विभाजित हुआ।

→ पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाक के साथ भेदभाव किया गया
जैसे – आर्थिक भेदभाव
नस्लीय भेदभाव
भाषायी भेदभाव

* <u>21 फरवरी 1952</u> :- पूर्वी पाक में बांग्ला भाषा के लिए विरोध प्रदर्शन
21 फरवरी = अन्तर्राष्ट्रीय भाषा दिवस

4.* <u>राजनीतिक भेदभाव</u>

→ 1970 चुनाव में अवामी लीग (शेख मुजीब उर रहमान) ने बहुमत हासिल किया। लेकिन याहिया खाँ की सरकार ने इन चुनावों को रद्द कर दिया।

→ पूर्वी पाक में विरोध प्रदर्शन हुए व मुजीब उर रहमान को गिरफ्तार कर लिया (25 मार्च 1971)।

→ 25 मार्च 1971 – पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन सर्च लाइट

→ पूर्वी पाक में क्रूर सशस्त्र अभियान

→ इसके मु. विरुद्ध मुक्ति वाहिनी का गठन किया गया जो स्थानीय लड़कों की सेना थी।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010004

* 3 दिसम्बर 1971:- ऑपरेशन चंगेज खान

→ पाक ने भारत पर हवाई हमले किये।

* 4 दिसम्बर 1971:- ऑपरेशन ट्राइडेंट

→ भारतीय नौसेना ने करांची बन्दरगाह पर हमला किया।

4 दिसम्बर = नेवी डे

→ 16 Dec 1971 को 93000 पाकिस्तानी सैनिको आत्मसमर्पण कर दिया। बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया।

→ शेख मुजीब उर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने

→ 15 अगस्त 1975 को उनकी हत्या कर दी गई थी।

* बांग्लादेश में 2 प्रमुख राजनीतिक दल है -

1. अवामी दल :-

→ संस्थापक = मुजीब उर रहमान

→ वर्तमान नेता = शेख हसीना

→ नीतियाँ भारत के पक्ष में है।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610100034

2. BNP (बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी):-

→ जिया उर रहमान

→ वर्तमान नेता = खालिदा जिया (पत्नी)

→ मुख्य विपक्षी दल

→ भारत के खिलाफ नीतियाँ

* भारत - बांग्लादेश के बीच विवाद :-

समुद्री सीमा विवाद

* न्यू मूर द्वीप / पूर्वासा द्वीप :-

→ यह भारत व बांग्लादेश की सीमा पर ज्वारीय द्वीप है।

→ समुद्र में 25000 वर्ग किमी. क्षेत्र विवादित था।

→ बांग्ला ने स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में उठाया।

* निर्णय :-

→ बांग्लादेश — 19000 वर्ग किमी

भारत — 6000 वर्ग किमी.

→ भारत ने इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि भारत अन्तर्राष्ट्रीय नियमों कानूनों व संस्थाओं का सम्मान करता है।

* भूमि सीमा विवाद :-

→ 100 वें संविधान संशोधन 2015 द्वारा हल किया गया।

* नदी विवाद :-

(A) गंगा नदी विवाद :-

→ कलकत्ता पोर्ट गंगा नदी की वितरिका हुगली पर स्थित है।

→ बंदरगाह के कामकाज के लिए निरन्तर जल धाराएँ बनाये रखने के लिए फरक्का बैराज का निर्माण भारत द्वारा किया गया।

→ जिसका बांग्लादेश ने विरोध किया।

→ इसे सुलझाने के लिए 1996 में गंगा नदी जल समझौता हुआ।

→ जिसके मुताबिक यदि नदी में कुल पानी की मात्रा 70000 क्युसेक से कम है तो आधा बांटा जायेगा।

→ गुजराल सिद्धान्त के आधार पर = समझौता

* गुजराल सिद्धान्त :-

पूर्व PM = IK गुजराल

→ भारत के पड़ोसी देशों को अधिक रियायतें देनी चाहिए और बदले में रियायतों की मांग नहीं करना

→ इसका उद्देश्य = पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाना।
(आधार)

THE NOTES HUB * All Competition Books & Notes are Available * 7300134518, 7610110084

* तीस्ता नदी विवाद :-

→ उद्गम = सिक्किम "चोलहामो झील"

→ सहायक = रंगपुग

→ यह प. बंगाल से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है।

→ भारत लगभग 55% पानी का उपयोग कृषि के लिए करता है।

→ नदी पानी के बंटवारे को लेकर विवाद

→ अब तक 2 बार समझौता हो चुका -

वर्ष	भारत	बांग्लादेश	नदी का पानी
1983	39%	36%	25%
2011	42.5%	37.5%	20%

→ प. बंगाल में विरोध के कारण यह समझौता लागू नहीं हो सका।

→ फिलहाल बांग्लादेश पानी के बराबर बंटवारे की मांग कर रहा है -

* बराक नदी विवाद :-

→ मेघना नदी की सहायक

→ मणीपुर से निकलती है

→ इस नदी पर भारत द्वारा टिपाईमुख जलविद्युत परि. का निर्माण किया जा रहा है।

→ बांग्लादेश = विरोध

→ भारत ने आश्वासन दिया कि इस परि. का लाभ बांग्लादेश के साथ साझा किया जायेगा।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610100064

* फेनी नदी विवाद :-

→ यह नदी भारत व बांग्लादेश के मध्य सीमा बनाती है। (त्रिपुरा)

→ जल बंटवारे का विवाद सुलझ गया।

→ जल का उपयोग → त्रिपुरा → पेयजल

→ इस नदी पर पुल त्रिपुरा के सबरूम व बांग्लादेश (रामगढ़) को जोड़ता है।

→ पुल का नाम = मैत्री सेतु

→ पुल ने चटगाँव बंदरगाह तक पहुँचान आसान बना दी।

→ इससे उत्तरी पूर्वी के राज्यों में आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेगी।

सहयोग के क्षेत्र

* **राजनीतिक सहयोग :-**

1. उच्च स्तरीय दौरे व आदान-प्रदान :-

-> भारतीय PM ने बांग्लादेश की आजादी के 50 साल (2021) पूरे होने पर बांग्लादेश में विभिन्न समारोहों में भाग लिया।

2. बांग्लादेश के PM का भारत दौरा :- 5-8 Sep-2022

* सहयोग :-

सूचना प्रौद्योगिकी

आतंकवाद व अलगाववाद

रोहिंग्या मुद्दे पर विवाद

→ बांग्लादेश रेलवे व भारतीय रेलवे कर्मचारियों के बीच प्रशिक्षण

* मुजीब छात्रवृत्ति :- बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान भारत के रक्षा बलों के कार्मिकों के वंशज को।

THE NOTES HUB * All Competition Books * Notes are Available * 7300134518

आर्थिक संबंध

→ भारत - बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।

→ द्विपक्षीय व्यापार = 18 बिलियन डॉलर

→ भारत ने 2021 में इन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 8 B$ की ऋण सहायता दी

रक्षा सहयोग

→ भारत ने बांग्लादेश के रक्षा उपकरणों में संयुक्त उत्पादन और आधुनिकता को बढ़ावा देने के लिए 500 मिलियन डॉलर की रक्षा सहायता दी।

* संयुक्त अभ्यास :-

1. SAMPRITI (सेना)
2. TABLE TOP (वायु)
3. IN-BN CORPAT (नेवी)
4. एक्सरसाइज बोंगोसागर (नौसेना)
5. SAMWEDHNA (बांग्लादेश-नेपाल-श्रीलंका व संयुक्त अरब अमीरात और आपदा राहत (HADR) अभ्यास

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010064

* कनेक्टिविटी :-

→ बांग्लादेश ने मालवाहक जहाजों के पारगमन व परिवहन के लिए भारत को चटगांव व मोंगला पोर्ट उपलब्ध करवा दिए।

→ मैत्री सेतु फेनी नदी पर 1.9 Km पुल

→ BBIN परियोजना

* विभिन्न ट्रेन सेवा :-

1. बंधन एक्सप्रेस
2. मैत्री
3. मिताली

* BBIN :- (मोटर वाहन समझौता)

→ बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल

→ इस समझौते के माध्यम से चार देशों के बीच माल (वस्तु), यात्री, निजी वाहनों की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित की जायेगी।

→ भारत बांग्लादेश व नेपाल ने BBIN को लागू करने के लिए (MVA) समझौता ज्ञापन दिया।

* बांग्लादेश का महत्व :-

* बांग्लादेश का सहयोग जरूरी है -

1. 4096 किमी लंबी सीमा का प्रबंधन करना
2. सीमा पर अपराधों को रोकने के लिए जैसे - मानव तस्करी जाली नोट, नशीले पदार्थ हथियार आदि।
3. भारत की पड़ोस प्रथम नीति और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के सफल कार्यान्वयन के लिए।
4. पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय विभिन्न उग्रवादी संगठन जो बांग्लादेश में शरण लिए हुए है के विरुद्ध कार्यवाही करना।
5. चीन के प्रभाव को कम करना।
6. पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए बांग्लादेश के साथ व्यापार बढ़ाना।
7. चिकनेक कॉरिडॉर पर निर्भरता कम करने के लिए बांग्लादेश के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध

9) दोनों सार्क व बिम्सटेक के सदस्य है।

10) BBIN मोटर वाहन समझौते को लागू करके के लिए बांग्लादेश का सहयोग आवश्यक

* बांग्लादेश में चीनी गतिविधियाँ :-

→ बांग्लादेश के लिए चीन सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।

→ चीन ने अल्पविकसित देशों के लिए अपने शुल्क - मुक्त, कोटा-मुक्त कार्यक्रम के तहत बांग्लादेश के 97% आयात पर शून्य शुल्क लगाया।

→ चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा आयुर्वेकर्ता (खरीदार) है।

→ चीन बांग्लादेश में मिसाइल परीक्षण केन्द्र स्थापित कर रहा है।

→ चीन की BRI परियोजना का एक हिस्सा है इसलिए वहाँ पर बुनियादी परि. का विकास।

भारत - अफगानिस्तान सम्बन्ध

*** राजनीतिक पृष्ठभूमि :-**

→ 1973 - राजतंत्र का स्थान गणतांत्रिक सरकार ने ले लिया।

→ 1978 - साम्यवादी सरकार का गठन

→ साम्यवादी सरकार ने भूमि एवं धार्मिक सुधार किये जिनका अफगानिस्तान की जनजातियों ने विरोध किया।

→ मुजाहिदीन का गठन (US समर्थित)

→ इससे कम्युनिस्ट सरकार कमजोर हुई।

→ 1979 अफगानिस्तान में USSR के हमले से गृहयुद्ध शुरु हुआ।

→ 1988 - जिनेवा समझौता

→ 1989 - USSR ने अपनी सेनायें वापिस बुला ली।

→ 1996 - तालिबान सत्ता में आया

→ 1996 - 2001 = तक तालिबान सरकार

→ अमेरिका पर 9/11 हमला हुआ

→ USA द्वारा ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम

→ अफगानिस्तान = लोकतंत्र

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610100034

* तालिबान :-

→ यह एक सुन्नी कट्टरवादी आतंकवादी संगठन है।

→ स्थापना = 1994

→ संस्थापक = मुल्ला उमर

→ अर्थ = विद्यार्थी

→ वर्तमान में चीफ = मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंदजादा

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610110034

* अफगानिस्तान पर तालिबान की पुनः स्थापना :-

* शांति समझौता - 29 फरवरी 2020

→ अमेरिका - तालिबान समझौता

→ अफगान से USA सेना बाहर निकलेगी

→ अफगानिस्तान की धरती का प्रयोग USA व उनके सहयोगियों के विरुद्ध नहीं किया जायेगा।

→ इस समझौते से तालिबान को मान्यता मिल गई। (राजनीतिक)

* मई 2021 :- तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए 1 सैन्य अभियान शुरू किया।

→ USA ने घोषणा की कि 31 अगस्त 2021 तक अमेरिकी सेना अफगान से वापस चली जायेगी।

→ लेकिन 15 अगस्त 2021 को तालिबान का काबुल पर अधिकार

→ USA की सेना को अफगान से भागना पड़ा।

* प्रभाव :-

* अफगानिस्तान पर प्रभाव :-

1. अफगान सेना की हार
   - a) लोकतांत्रिक सरकार के प्रति वफादारी का अभाव
   - b) अफगान की सेना को अकेले लड़ने का अनुभव नहीं था।
   - c) मनोबल की कमी
   - d) भ्रष्टाचार

2. मानवीय संकट जिसमें महिलाओं व युवाओं के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लग गया।

3. लोकतंत्र विफल हो गया

4. हिंसा बढ़ी

5. आतंकवादियों की शरणगाह बन सकता है।

6. अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010064

* USA पर प्रभाव :-

1. USA आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध हार गया।

2. महाशक्ति के रूप में छवि समाप्त

3. कमजोर नेतृत्व का प्रदर्शन

4. USA द्वारा किये गये निवेश का प्रयोग तालिबान के द्वारा किया जायेगा। जैसे = अत्याधुनिक हथियार

5. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर USA का नेतृत्व व प्रभुत्व कम।

* पाकिस्तान पर प्रभाव :-

→ पाकिस्तान व तालिबान के संबंध बहुत गहरे है।

→ भारत के विरुद्ध तालिबान की मदद मांगी जायगी

→ पाक द्वारा अफगान के संसाधनों का दोहन किया जा सकता है।

→ डूरंड रेखा के मुद्दे पर पाकिस्तान को तालिबान का समर्थन मिलेगा

→ USA के साथ पाक के सम्बन्ध बिगड़े है।

→ पाक में भी तहरीक ए तालिबान सशक्त हो सकता है।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610100034

* चीन पर प्रभाव :-

1. चीन - तालिबान सम्बन्ध स्थापित हुए

2. अफगान BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया।

3. चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) का अफगानिस्तान तक विस्तार

4. इसमें चीन को पेशावर - काबुल मोटरवे का निर्माण प्रस्तावित है।

5. चीन - अफगानिस्तान - पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की बातचीत का इस्तेमाल भारत पर दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है।

* भारत की गतिविधियाँ :-

→ भारत अफगानिस्तान में लोकतंत्र का समर्थक है।

→ सामरिक साझेदारी समझौता = Oct - 2011

* रक्षा :-

→ अफगानिस्तान की सेना को सशक्त करने के लिए MI-35 अटैक हैलिकॉप्टर उपलब्ध करवाये गये है।

→ अफगान के सैन्य अधिकारियों को भारत द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है।

* भारत द्वारा विकासात्मक गतिविधियाँ :-

1. जरंज - डेलाराम हाइवे

→ इसके माध्यम से भारत मध्य एशिया से जुड़ सकता है।

→ अफगान को मध्य एशिया का द्वार कहा जाता है।

→ सलमा बाँध, हेरात जिसे भारत - अफगान मैत्री बाँध कहा जाता है।

→ कानुल से पुल ए खुमरी तक ट्रांसमीशन लाइन।

→ संसद भवन का निर्माण

* हार्ट ऑफ एशिया - इस्तांबुल प्रक्रिया (HoA-IP) :-

→ शुरुआत = 2011, इस्तांबुल से

→ अफगानिस्तान व उसके आसपास शांति स्थापित करना।

* अश्गाबात समझौता - 2016

→ मध्य एशिया व फारस की खाड़ी के बीच वस्तु के परिवहन व परिवर्तन के लिए

→ मध्य एशिया के साथ भारत इसका हिस्सा है।

* तालिबान शासन के बाद अफगानिस्तान पर भारत का रुख :-

→ भारत ने अफगान में तालिबान शासन को मान्यता नहीं दी।

→ भारत ने अफगान में अपनी उपस्थिति फिर से स्थापित करने के अफगान में दूतावास फिर से खोल दिये।

* UNSC संकल्प 2593 :-

→ भारत द्वारा UNSC में तालिबान पर प्रस्ताव

→ अफगान के क्षेत्र का इस्तेमाल किसी देश को धमकाने या आतंकवादियों को पनाह देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

* दिल्ली डायलॉग - जनवरी 2022 :-

→ मेजबानी = भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

→ प्रतिभागी = मध्य एशियाई देश

→ अफगान पर तालिबान के कब्जे के बाद क्षेत्र में सुरक्षा और शांति के बारे में चर्चा करने के लिए।

* वर्तमान परिदृश्य :-

→ दिसम्बर 2022 में तालिबान ने भारत से मानवीय आधार पर अपनी विकासात्मक गतिविधियों को फिर से शुरू करने और पाकिस्तान के साथ उनके संघर्ष में सहायता करने का आग्रह किया है।

THE NOTES HUB
All Competition Books
Notes are Available
7300134518

* ऑपरेशन देवी शक्ति :-

→ अफगानिस्तान में तालिबान के अधिकार के बाद भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए चलाया गया।

भारत-नेपाल सम्बन्ध

* सांस्कृतिक सम्बन्ध :-

→ हिन्दू धर्म बहुसंख्यक धर्म है।

→ नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के 4 मुख्य पुजारियों में से एक भारत से होगा।

→ भगवान बुद्ध :-

⊙ जन्मस्थली = लुम्बिनी (नेपाल)

⊙ कर्मस्थली = भारत

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010034

→ नेपाल की राजशाही का सम्बन्ध राजस्थान (मेवाड़) से है।

→ नेपाल में मधेशी जनजाति जिनके वैवाहिक संबंध भारत में है।

→ नेपाली नागरिकों को भारत में व्यापार करने की इजाजत है।

→ नेपाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया

→ मैत्री संधि = 1950

→ दोनों देशों की सीमा खुली रखी गई।

* राजनीतिक पृष्ठभूमि :-

→ 1990:- निरंकुश राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र

→ 1990 के दशक में नेपाल में एक सशस्त्र माओवादी आंदोलन शुरू

→ 2006 :- राजशाही खत्म कर दी गई और माओवादी पार्टियों को मान्यता दी गई।

→ 2015 :- नेपाल का नया संविधान

प्रमुख राजनीतिक पार्टियाँ

नेपाली कांग्रेस
→ मुख्य नेता = शेर बहादुर देउबा
→ भारत की ओर झुकाव

नेपाली कम्युनिष्ठ पार्टी
→ दो मुख्य नेता
a) के.पी. शर्मा ओली
b) पुष्प कमल दहल (प्रचंड)
→ दोनों नेताओं के बीच सत्ता संघर्ष
→ चीन की ओर झुकाव

जनता कम्युनिष्ठ पार्टी
→ मधेशीयों की प्रमुख पार्टी
→ नेता = बाबूराम भट्टराई
→ भारत की ओर झुकाव

✳ भारत व नेपाल के बीच चुनौतियाँ :-

✳ मधेशी समस्या :-

→ मधेशीयों ने संविधान में राजनीतिक भेदभाव के कारण 2015 में नेपाल के संविधान का विरोध किया था।

→ भारत ने मधेसियों का समर्थन किया।

→ नेपाल ने आरोप लगाया कि भारत - नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है।

✳ कालापानी विवाद :-

→ कालापानी (उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला) भारत - चीन - नेपाल की सीमा पर है।

* 1816 - सुगौली की संधि :-

1. अंग्रेजों v/s नेपाल

→ इसमें काली नदी को भारत व नेपाल के बीच सीमा बनाया गया था।

→ काली - पूर्व = नेपाल
पश्चिम = भारत

→ काली नदी के उद्गम को लेकर विवाद है।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610100034

→ भारत - लिपुलेख [कालापानी क्षेत्र के पूर्व] से निकलती है।

→ नेपाल - लिम्पियाधुरा [कालापानी क्षेत्र - पश्चिम] से निकलती है।

→ इसलिए दोनों कालापानी क्षेत्र पर अपना दावा करते है

→ हाल ही नेपाल के नये नक्शों में कालापानी - लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया।

→ भारत इन दावों से इनकार करता है।

→ यह क्षेत्र भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।

→ 1963 ई. में चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ITBP की एक पोस्ट स्थापित की गई थी।

→ विपुलेख दर्रा = कैलास - मानसरोवर यात्रा → महत्वपूर्ण

→ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत व नेपाल ने एक आयोग का गठन किया।

* सुस्ता विवाद

→ यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में भारत व नेपाल की सीमा पर स्थित है।

→ यहाँ गंडक नदी को भारत व नेपाल के मध्य सीमा माना जाता है।

→ नदी में प्रवाह के परिवर्तन के कारण यह क्षेत्र भारत के अधीन आ गया।

→ कालापानी विवाद को सुलझाने के लिए — भारत द्वारा उस्तेमाल

*** नेपाल में चीन की गतिविधियाँ :-**

→ साम्यवाद + माओवाद विचारधारा का प्रसार

→ मधेशी आन्दोलन के दौरान नेपाल व चीन के रिश्ते मजबूत हुए।

→ तेल की आपूर्ति के लिए वाणिज्यिक समझौता

→ नेपाल BRI परियोजना का सदस्य है।

*** मूलभूत ढाँचा परियोजनाएं**

a) पोखरा हवाई अड्डा

b) जल विद्युत परि

c) तिब्बत - काठमांडु रेल परियोजना

d

THE NOTES HUB * All Competition Books * Notes are Available * 7300134518, 7610010094

→ भारत पर नेपाल की अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए चीन ने अपना तियानजिन बंदरगाह खोला।

→ नेपाल में चीन की गतिविधियाँ भारत पर दबाव बनाने हेतु है।

*** सहयोग के क्षेत्र :-**

→ 2014 से भारत - नेपाल सम्बन्धों का आधार HIT फॉर्मूला है -

1. हाई - वे
2. आई - वे
3. ट्रांस - वे

* **आर्थिक :-**

→ नेपाल का अधिकांश व्यापार भारत के साथ होता है।

→ द्विपक्षीय व्यापार करीब 7 अरब डॉलर का है।

→ नेपाल में भारत के Rupay कार्ड का उपयोग

* **आपूर्तियाँ :-**

→ तेल - गैस - दवाईयाँ

→ नेपाल भूकम्प के दौरान 1 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता

→ $ 750 मिलियन [ऋण)

— $ 250 मिलियन [अनुदान]

* **जलविद्युत परियोजनायें :-**

a) पंचेश्वर जल विद्युत परियोजना [महानदी पर]

b) उच्च कर्नाली HEP

c) अरुण HEP

THE NOTES HUB * All Competition Books * Notes are Available * 7300134518, 7610100034

* **ऊर्जा :-**

→ बिजली व्यापार के लिए ट्रांसमिशन लाइन

जैसें -

कटैया [I] ⟶ किसहा [N]

रक्सौल [I] ⟶ परवानीपुर [N]

→ मोतिहारी तेल - गैस पाइपलाइन अमलेखगंज

* पारगमन :-

→ नेपाल समुद्री व्यापार के लिए भारत का उपयोग करता है -

1. कलकत्ता बंदरगाह
2. विशाखापत्तनम

* रक्षा :-

→ सैन्य अभ्यास "सूर्य किरण"

* राजनीतिक सम्बन्ध :-

नेपाल के PM का भारत दौरा

* परियोजनाएं :-

1. कुर्था - बिजलपुरा रेलवे लाइन
2. भारतीय अनुदान के तहत ~~बर्हिडा~~ बथनाहा [भारत] से नेपाल सीमा शुल्क भाई तक भारतीय रेलवे कार्गो ट्रेन
3. गोरखपुर - नुतनवा ट्रांसमिशन लाइन का संयुक्त उद्घाटन
4. मोतिहारी- अमलेखंज पेट्रोलियम पाइपलाइन

* एकीकृत चेकपोस्ट [ICP]

→ नेपालगंज [N] ⟶ रुपईडीहा [I]

→ भैरहवा [N] ⟶ सोनौली [I]

* समझौते :- (MOI)

1. पारगमन की संधि
2. पेट्रोलियम अवसंरचना सहयोग
3. भारत - नेपाल सीमा पर दोधारा चंदानी चेक पोस्ट
4. सीमा पार भुगतान के लिए NPCIL व NCHL नेपाल
5. लोअर अरुण HEP
6. फुकोट - कर्णाली HEP

* भारत - नेपाल सम्बन्धों को बेहतर करने के उपाय :-

1. भारत को नेपाल की सम्प्रभुता का सम्मान करना चाहिए और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
2. नेपाल में भारत द्वारा किये गये कार्यों का (सकारात्मक) प्रचार-प्रसार करना चाहिए।
3. भारतीय P.M ने 2018 में भारत - नेपाल सम्बन्धों के लिए एक नया 5T फॉर्मूला दिया —
   - → परंपरा
   - → व्यापार
   - → पर्यटन
   - → तकनीकी
   - → परिवहन

THE NOTES HUB * All Competition Books * Notes are Available * 7300134518

* नेपाल को संदेश दिया जाना चाहिए कि चीन भारत की जगह नहीं ले सकता। क्योंकि -

→ भारत नेपाल के दक्षिण में है जो भौगोलिक दृष्टि से अनुकूल क्षेत्र है जबकि चीन नेपाल के उत्तर में है जो भौगोलिक दृष्टि से कठिन क्षेत्र है।

भारत - भूटान संबन्ध

→ सीमा - 699 किमी

→ भारत व भूटान के सम्बन्धों का आधार आपसी विश्वास, सद्भाव व समझ पर है।

→ सीमायें खुली और पारगमन

* पुनाखा की संधि :- 1910 :-

→ अंग्रेजों ने भूटान को रक्षित राज्य का दर्जा दिया

→ 1947 में भूटान ने स्वतंत्र रहना चुना।

* मित्रता और सहयोग की संधि - 1949

→ फरवरी - 2007 में नवीनीकृत

* व्यापार - वाणिज्य - पारगमन पर भारत - भूटान समझौता - 1972

→ संशोधित - 2016

→ यह मुक्त व्यापार व शुल्क मुक्त पारगमन व्यवस्था है।

* भारत - भूटान ऊर्जा विद्युत सहयोग और प्रोटोकॉल - 2009

→ मोंगदेछु परियोजना - दिसम्बर 2022 - 720 MW

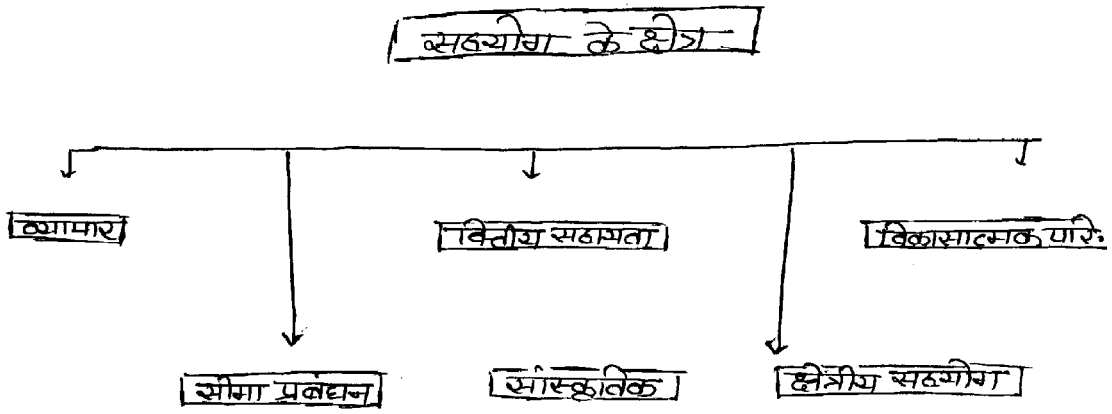

सहयोग के क्षेत्र

- व्यापार
- सीमा प्रबंधन
- वित्तीय सहायता
- सांस्कृतिक
- क्षेत्रीय सहयोग
- विकासात्मक परि.

* भूटान में चीनी गतिविधियाँ

-> भूटान और चीन के बीच औपचारिक राजनयिक सम्बन्ध नहीं है। लेकिन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए इनके मध्य बातचीत की जाती है।

1. डोकलाम विवाद = 2017
2. सकतेंग वन्य जीव अभयारण्य :-

-> 2020 में चीन ने इस पर दावा किया।

-> भूटान ने चीन के इस दावे को खारिज कर दिया है कि वह भूटान का अभिन्न व सम्प्रभु क्षेत्र है।

THE NOTES HUB ★ 7300134518, 7610100 ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518

* थ्री स्टेप रोड मैप :-

-> अक्तू 2021 में भूटान और चीन ने सीमा विवाद से निपटने के लिए यह समझौता

-> थ्री स्टेप रोड मैप अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।

भारत - श्रीलंका सम्बन्ध

→ श्रीलंका एक द्विपीय देश है।

→ बहुसंख्यक - सिंहल समुदाय

→ अल्पसंख्यक = तमिल

→ तमिल समुदाय पूर्वी तथा उत्तरी प्रान्तों में केन्द्रित है।

→ स्वतंत्रता के बाद सिंहालियों द्वारा तमिलों के साथ विभिन्न भेदभाव किये गये -

- नागरिकता
- भाषायी
- धार्मिक
- राजनीतिक

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010084

→ इन भेदभावों के विरुद्ध तमिलों के द्वारा LTTE की स्थापना की गई

Liberation Tigers of Tamil Elam [राष्ट्र]

→ उद्देश्य - एक अलग तमिल राष्ट्र बनाना। (स्थापना - 1976

नेता = V. प्रभाकरन

→ 1983 में LTTE ने श्रीलंका की सेना पर हमला किया → जिससे गृहयुद्ध शुरू हो गया।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010004

★ राजीव - जयवर्धने समझौता :-

→ तमिल भाषा को मान्यता दी जायेगी

→ उत्तरी और पूर्वी प्रांत का विलय किया जायेगा।

→ प्रान्तीय सरकार को अधिक राजनीतिक शक्तियाँ दी जायेगी

→ LTTE आत्मसमर्पण करेगी

→ भारतीय शांति सेना IPKF (इण्डियन पीस कीपिंग फोर्स) भेजेगा।

★ कमियाँ :-

→ LTTE ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया।

→ शांति सेना को भेजने का निर्णय एक भारी भूल साबित हुआ

→ लगभग - 1200 सैनिक शहीद व 2600 - घायल

→ इस हस्तक्षेप से तमिल भावनायें आहत हुई।

→ इसके कारण 1991 में - राजीव गाँधी की हत्या

→ इस घटना के बाद भारत ने तमिल मुद्दे में हस्तक्षेप बंद कर दिया।

★ ऑपरेशन पवन :-

→ 1987 : भारत ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी।

★ ऑपरेशन पुमलाई / ईगल मिशन - 4 :-

→ 1987 :- भारतीय वायुसेना द्वारा जाफना शहर में खाद्य आपूर्ति पहुँचाना।

→ 2005 में महिन्दा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति बने जिनके द्वारा LTTE के विरुद्ध एक बड़ा अभियान छेड़ा गया।

→ अन्ततः 2009 में LTTE को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया।

→ प्रभाकरण की हत्या कर दी गई।

सहयोग के क्षेत्र

* राजनीतिक :-

→ सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व की बैठक

→ भारत के PM ने भारत की स्ट्रेंथ ऑफ फ्लॉवर की नीति के हिस्से के रूप में 2019 में श्रीलंका का दौरा किया।

→ स्ट्रेंथ ऑफ फ्लावर नीति

→ भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, सेशेल्स जैसे हिन्द महासागर के देशों के साथ घनिष्ठ राजनीतिक - आर्थिक सम्बन्ध रखता है।

* आर्थिक :-

→ 2000 - मुक्त व्यापार समझौता

→ श्रीलंका सार्क में भारत के सबसे बड़े व्यापार भागीदारों में से एक है।

→ 2022 - सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका और RBI द्वारा मुद्रा विनिमय समझौता

→ इसके तहत भारत ने श्रीलंका को 500 मिलियन डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट के तौर पर दिये।

* **सांस्कृतिक :-**

→ बौद्ध धर्म का प्रचार

→ 1977 = सांस्कृतिक सहयोग समझौता

→ 1997 = भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र - कोलम्बो

भारत और श्रीलंका के बीच मुद्दे :-

→ श्रीलंका सरकार ने 2005 के बाद LTTE के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया। जिससे मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ।

→ यह मुद्दा "संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार" परिषद में उठाया गया।

→ जिसमें भारत की प्रतिक्रिया घरेलू राजनीति से प्रेरित थी।

→ भारत का मतदान -

2010 = श्रीलंका के पक्ष

2012 = श्रीलंका के खिलाफ

2014 = अनुपस्थित

2021 = अनुपस्थित

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010064

→ श्रीलंका सरकार ने आश्वासन दिया कि घरेलू न्यायिक तंत्र से इस मामले में न्याय किया जायेगा।

* **सुझाव :-**

→ घरेलू न्यायिक प्रक्रिया को जल्दी शुरू किया जाना चाहिए।

→ 13 वाँ CA लागू किया जाना चाहिए (यह राजीव - जयवर्धने समझौते का परिणाम)

3. विस्थापितों का पुनर्वास किया जाना चाहिए।

4. उत्तरी क्षेत्र का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए।

5. 2 समुदायों के बीच एक सौहार्द स्थापित किया जाना चाहिए।

* मछुआरों का मुद्दा :-

→ भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा नहीं है।

→ भारतीय मछुआरे श्रीलंकाई जल में मत्स्यग्रहण का कार्य करते है।

→ भारतीय मछुआरे बॉटम ट्राउलर का उपयोग करते है जिसके परिणामस्वरूप मत्स्य संसाधनों का अधिक दोहन और जैव विविधता को अधिक नुकसान होता है।

→ श्रीलंकाई नौसेना के द्वारा भी भारतीय मछुआरे के विरुद्ध कार्यवाही भी की जाती है।

* कच्चातिवु द्वीप :-

→ यह भारत व श्रीलंका के बीच स्थित निर्जन द्वीप है।

→ स्वतंत्रता के बाद दोनों देशों ने इस पर अपना दावा किया।

→ 1974 ई. में भारत ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया।

→ यद्यपि भारत को इस क्षेत्र में मत्स्यग्रहण का अधिकार दिया गया था।

→ परन्तु वर्तमान में श्रीलंका इस क्षेत्र में मत्स्यग्रहण की अनुमति नहीं देता

→ तमिलनाडु की विधानसभा ने इस द्वीप को वापस लेने के लिए बार-बार प्रस्ताव पारित किये जाते है।

* समाधान :-

1. सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पर चर्चा की जाती है।
2. संयुक्त कार्य समूह का गठन
3. मछुआरे की समस्या के स्थायी समाधान खोजने के लिए मंत्रियों के स्तर का तंत्र
3. नौसेनाओं के बीच समन्वय के लिए एक हॉट लाइन स्थापित की गई।
4. भारत - कोलंबो में समुद्री बचाव समन्वय केन्द्र (MRCC) स्थापित करेगा - भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड [BEL]

* सुझाव :-

1. बहुदिवसीय मत्स्यगन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
2. बॉटम ट्राउलर के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
3. समुद्री सीमा के दोनों ओर एक साझा क्षेत्र बनाया जाना। जिसमें मछुआरों को चेतावनी दी जाये।
4. यह मुद्दा आजीविका से जुड़ा है। इसलिए मानवीय दृष्टिकोण का उपयोग किया जाना

* चीन की गतिविधियाँ :-

→ श्रीलंका BRI का सदस्य है।

→ चीन बुनियादी ढांचा परियोजना विकसित कर रहा है -

जैसे - हम्बनटोटा बंदरगाह
कॉलम्बो पोर्ट सिटी
कोलम्बो से कैंडी रोड प्रोजेक्ट
कोयला आधारित ऊर्जा परि.

→ भारत के मिसाइल प्रक्षेपण के दौरान चीन का उपग्रह ट्रेकिंग पोत युवान वांग - 5 हम्बनटोटा पोर्ट तक पहुँचा था।

→ चीन श्रीलंका की राजनीति में भी हस्तक्षेप करता है।

→ 2018 का राजनीतिक संकट चीन द्वारा उत्पन्न किया गया था।

→ जिसमें भारत समर्थक PM रानिल विक्रमासिंघे को चीन समर्थक महिंदा राजपक्षे से प्रस्थापित कर दिया गया।

* भारत की गतिविधियाँ :-

1. भारत और श्रीलंका आतंकवाद के विरुद्ध एक-दूसरे का सहयोग कर रहे हैं।

2. श्रीलंका ने अपने भारत के साथ अपने पहले असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

3. भारत विकास कर रहा है -

1. त्रिंकोमली पेट्रोलियम हब
2. उत्तरी प्रान्त में कांकेसंथुरई पोर्ट
3. हम्बनटोटा हवाई अड्डा
4. उत्तरी प्रान्त में लगभग 50 हजार आवास

THE NOTES HUB * All Competition Books & Notes are Available * 7300134518, 7610010024

→ भारत और जापान संयुक्त रूप से कोलंबो बंदरगाह (ईस्ट कोस्ट टर्मिनल) विकसित कर रहे है।

→ भारत जापान के 3 द्वीपों में हाइब्रिड बिजली परि. की स्थापना करेगा-

1. नैनातिवु
2. डेल्फ्ट या नेदुनथीवु
3. अनलैतिवु

THE NOTES HUB ★ 7300134518, 7610010004 ★ All Competition Books ★ Notes are Available

* श्रीलंका का आर्थिक संकट :- कारण

1\. गृहयुद्ध :- 26 वर्ष लंबा

2\. खाद्य संकट :- श्रीलंका ने अचानक जैविक खेती की नीति अपनाई जिससे खाद्य उत्पादन में कमी आई।

3\. राजनीतिक कुप्रबंधन :-

→ लोक लुभावनी राजनीति के तहत करों में कटौती की गई जिससे सरकार की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

4\. चीन का ऋण जाल :

5\. पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था :-

→ ईस्टर बम विस्फोट व कोविड -19 के कारण पर्यटन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव

4. रूस - यूक्रेन संकट :- इसके कारण तेल की कीमतों में वृद्धि हुई जिससे श्रीलंका में तेल संकट उत्पन्न हो गया।

→ श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भण्डार ऐसी स्थिति में लगभग समाप्त हो गये जिसने अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादों को खरीदने की क्षमता को प्रभावित किया।

* भारत की भूमिका :-

* नवम्बर - 2021 :- श्रीलंका की कृषि गतिविधियों के लिए नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक की आपूर्ति की गई।

* जनवरी - 2022 :- मुद्रा विनिमय समझौते (सार्क ढांचे के तहत) के तहत 400 मिलियन डॉलर दिये गये।

* फरवरी - 2022 :- तेल आयात के लिए 500 मिलियन डॉलर दिये।

* मार्च - 2022 :- अन्य आयातों के लिए $ 1 बिलियन प्रदान

→ श्रीलंका में भारत का सबसे बड़ा FDI निवेश

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610001004

भारत – मालदीव सम्बन्ध

*** राजनीतिक पृष्ठभूमि :-**

→ 2008 तक → तानाशाही शासन

* 2008 → लोकतंत्र की स्थापना

→ राष्ट्रपति = मोहम्मद नशीद

→ भारत की ओर झुकाव

→ 2012 में आतंकवाद व भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद सत्ता से हटा दिया गया था।

→ 2012 :- अब्दुल्ला यामीन नये राष्ट्रपति बने

→ चीन की ओर झुकाव

→ यामीन सरकार ने आपातकाल लागू कर दिया।

→ आपातकाल के बाद मालदीव में चुनाव हुए।

→ 2018 = मोहम्मद इब्राहिम सोलिह राष्ट्रपति

→ भारत की ओर झुकाव

THE NOTES HUB * All Competition Books * Notes are Available *

*** भारत व मालदीव के मध्य चुनौतियाँ :-**

*** चीन की गतिविधियाँ :-**

→ यामीन सरकार के दौरान इसमें वृद्धि हुई।

→ चीन व मालदीव के बीच मुक्त व्यापार समझौता

→ 2018 में चीन ने भारत को मालदीव में सैन्य कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी दी थी।

→ मालदीव के लोगों को चीन में 30 दिन का वीजा मुक्त प्रवास

→ BRI परि. का सदस्य जिसके तहत विभिन्न परियोजनाओं का विकास

→ इसकी वजह से मालदीव कर्ज के जाल में फंस गया।

→ माले एयरपोर्ट परियोजना का निर्माण भारत की GMR इंफ्रा प्राइवेट Ltd. द्वारा किया जा रहा है, जिसे रद्द करके एक चीनी कम्पनी को दिया गया।

* चीन - मालदीव मैत्री पुल :-

→ यह मालदीव की राजधानी माले और पड़ोसी हुलहुले द्वीप को जोड़ता है।

* इंडिया आउट अभियान :-

→ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होने व संचार के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के नीच स्थित होने के कारण भारत ने मालदीव को दो निगरानी विमान दिये व इसकी देखरेख के लिए भारतीय सेना को तैनात किया।

→ मालदीव के लोगों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह मालदीव की सम्प्रभुता के लिए खतरा है।

→ पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने भारत के खिलाफ इस विरोध को 1 जन आंदोलन में बदल दिया।

→ इसके बाद भारत ने विमान को तटों से हटा लिया।

→ मालदीव सरकार ने मई 2022 में इस आन्दोलन पर प्रतिबंध लगा दिया।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610014004

भारत की गतिविधियाँ :-

*** राजनीतिक :-**

*** ऑपरेशन कैक्टस :-** 1988

→ मालदीव में तख्तापलट की कोशिश को रोकने के लिए भारत ने सैन्य अभियान चलाया।

*** भारत PM का दौरा 2018 :-**

→ राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए

→ मालदीव में लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

*** 2019 - दौरा :-**

→ दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के बाद पहली विदेश यात्रा [स्विंग-फ्लोवर]

→ मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा (2022)

* **आर्थिक :-**

→ बुनियादी ढाँचे का विकास

* **ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट :-**

1. → मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजना
2. → माले व निकटवर्ती द्वीपों के बीच 6.74 किमी लंबा पुल लिंक
3. भारत ने प्रदान किया -

   अनुदान = 100 मिलियन डॉलर

   लाइन ऑफ क्रेडिट = 400 मि. डॉलर

THE NOTES HUB * All Competition Books * Notes are Available * 7300134518, 7610100064

* **माले व कोच्ची के बीच सीधी कार्गो फेरी सुविधा**

* **रक्षा सह :-**

→ मालदीव की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 50 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता प्रदान करना।

* **UTF हार्बर परियोजना**
  (उथुरु थिला फाल्हू द्वीप)

→ भारत मालदीव में अनुदान सहायता परियोजना के तहत UTF हार्बर परि. विकसित करना।

→ नौसैनिक जहाजों के लिए रखरखाव व मरम्मत केन्द्र का विकास करना।

*** ऊर्जा सहयोग :-**

→ मालदीव का 2030 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य

→ भारत आक्षय ऊर्जा हस्तान्तरण, 2022 के तहत मदद कर रहा है।

→ मालदीव एक सूर्य, एक विश्व एक ग्रिड का हिस्सा है।

*** ऑपरेशन-नीर :-**

→ मालदीव में पेयजल संकट के दौरान भारत ने पेयजल उपलब्ध करवाया।

*** ऑपरेशन-संजीवनी :-**

→ भारत ने मालदीव को COVID-19 से लड़ने के लिए आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की।

⊛ वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड :-

→ 2015 → अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

भारत + फ्रांस

सदस्य देश = 121

मुख्यालय = गुरुग्राम

→ 2018 → वन सन वन वर्ल्ड, वन ग्रिड अवधारणा

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610100034

* **ऑपरेशन समुद्र सेतु - 2022**

→ वंदे भारत मिशन के साथ शुरु

→ COVID-19 के दौरान भारतीयों को वापस लाने के लिए।

* **ऑपरेशन समुद्र सेतु - 2**

→ कोविड से लड़ने के लिए चिकित्सा उपकरण व O_2 की आपूर्ति

* **मिशन सागर** [क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा व विकास]

→ शुरुआत - मई 2020

→ INS केसरी = हिन्द महासागर के देशों को भोजन व चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करवाने की भारत की पहल

मालदीव
मॉरीशस
मेडागास्कर
कोमरूस
सेशल्स

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610100064

* **मिशन सागर - II**

→ शुरु = नवम्बर 2020

→ INS ऐरावत ने सूडान, द. सूडान, जिबूति और इरीट्रिया को खाद्य सहायता प्रदान की।

* मिशन सागर III :-

→ INS कित्वान

→ मैत्रीपूर्ण विदेशी देशों को भारत की मानवीय सहायता व आपदा प्रबन्धन सहायता -

जैसे - वियतनाम

कम्बोडिया

भारत - म्यांमार सम्बन्ध

* राजनीतिक पृष्ठभूमि :-

→ 1937 तक म्यांमार ब्रिटिश भारत का हिस्सा था।

→ 4 जनवरी 1948 :- म्यांमार को आजादी मिली

[1989 - बर्मा → म्यांमार]

→ आजादी के बाद लोकतंत्र की स्थापना

→ "यू नू" - प्रधानमंत्री बने - गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेता

→ 1962 = म्यांमार में तख्तापलट

→ स्थापित = सैन्य सरकार [जुंटा सरकार]

→ 1989 - म्यांमार में चुनाव

→ आन सान सू की पार्टी NLD [नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी] ने जीत हासिल की।

→ जुंटा सरकार ने चुनाव रद्द कर दिया और आंग सू को गिरफ्तार कर लिया।

→ 1991 → सू की - नोबेल का शांति पुरस्कार
[लोकतंत्र की स्थापना के प्रयासों के लिए]

→ 2008 :- अन्तर्राष्ट्रीय दबाव के बाद नया संविधान

→ 2010 → चुनाव

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available

→ USDP – म्यांमार सेना द्वारा समर्थित पार्टी

→ NLD ने चुनाव का बहिष्कार किया क्योंकि आंग सू की रिहा नहीं हुई।

→ बाद में सू की रिहा हुई।

→ 2015 – सू की पार्टी ने आम चुनाव जीता

→ लेकिन वह राष्ट्रपति नहीं बनी क्योंकि उसके दोनों बेटों के पास ब्रिटिश नागरिकता थी

→ 2020 → चुनाव

→ NLD को बहुमत मिला।

→ 1 फरवरी 2021 = फिर से तख्तापलट

→ आंग सान सू की और म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंट को गिरफ्तार किया।

→ म्यांमार में आपातकाल की घोषणा कर दी गई।

→ तख्तापलट का म्यांमार के लोगों ने विरोध किया।

→ यह तख्तापलट – मिन आंग लाइंग → कार्यवाहक राष्ट्रपति मिंट स्वी।

* म्यांमार के संविधान की कमियाँ / तख्तापलट के कारण :-

→ म्यांमार की संसद में 25% सीटें सेना के लिए आरक्षित है।

→ C.A के लिए 76% वोटों की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि सेना के समर्थन के बिना कोई संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता।

→ म्यांमार के 2 उपराष्ट्रपतियों में से 1 सेना से है।

→ म्यांमार में रक्षा गृह व सीमा मंत्रालय सेना के अधीन है।

→ सेना को आपातकाल लगाने की शक्ति प्राप्त है।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610100024

* रोहिंग्या का मुद्दा :-

→ रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन प्रान्त में रहने वाली एक जनजाति है जो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखती है।

→ म्यांमार की सरकार इन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया मानती है।

→ 1982 ई के नागरिकता अधिनियम में इन्हें नागरिकता से वञ्चित कर दिया गया।

→ समय - समय पर इनके खिलाफ दंगे होते रहते है।

→ म्यांमार सेना की ओर से इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है।

→ इसलिए रोहिंग्याओं को म्यांमार छोड़ना पड़ा और उन्होंने बड़ी संख्या में बांग्लादेश में शरण ली

→ इन्हें बांग्लादेश ने भसन चार नामक द्वीप पर बसाया।

→ भारत में करीब 40-50 हजार रोहिंग्या मौजूद है।

→ भारत सरकार इन्हें शरणार्थी नहीं मानती क्योंकि ये बांग्लादेश के रास्ते भारत आये।

→ इसलिए इन्हें घुसपैठिया माना जाता है।

→ कुछ रोहिंग्याओं में कट्टरवादी तत्व भी सक्रिय हो गये और अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी का गठन किया।

→ इन्हें भारत में बोधगया में हुए आतंकवादी हमलों के लिए दोषी ठहराया जाता है।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010034

⊛ भारत में शरणार्थी समस्या :-

→ म्यांमार में तख्तापलट के कारण कई शरणार्थी भारत आये जैसे - मणिपुर व मिजोरम में चिन शरणार्थी।

→ भारत सरकार को शरणार्थियों की समस्या के समाधान के लिए एक एकीकृत नीति बनाने की आवश्यकता है।

→ भारत शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कन्वेंशन 1951 का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।

* भारत की गतिविधियाँ :-

→ भारत - म्यांमार की 1640 Km लंबी सीमा उत्तर-पूर्वी राज्यों नागालैण्ड व मणिपुर के साथ लगती है।

→ म्यांमार एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है।

→ भारत की प्रथम पड़ोस नीति व एक्ट ईस्ट नीति के तहत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।

* सम्बन्धों का आधार = 5B व 3C

* 5B -	3C
1. बौद्ध धर्म	1. कल्चर
2. व्यवसाय	2. कॉमर्स
3. बॉलीवुड	3. कनेक्टिविटी
4. भरतनाट्यम	
5. बर्मा टिक	

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610101004

* कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्राजेक्ट :-

→ इस परियोजना के तहत भारत व म्यांमार समुद्र, नदी व सड़क मार्ग जुड़ेंगे

* **लाभ :-**

1. चिकननेक पर भारत की निर्भरता कम हो जायेगी।
2. उत्तरी-पूर्वी राज्यों से जुड़ने के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध
3. पड़ोस प्रथम व एक्ट ईस्ट
4. हिंसक गतिविधियाँ कम होगी
5. उत्तरी-पूर्वी राज्यों का विकास

* **IMT हाइवे :-**

→ इसके जरिए भारत, म्यांमार व थाइलैण्ड को सड़क मार्ग से जोड़ा जायेगा।

→ म्यांमार को द. पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010004

* **चीन की गतिविधियाँ :-**

1. म्यांमार चीन BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा है।

→ बुनियादी परियोजना का विकास

1. मायितसोन बांध
2. क्योकफ्यो बंदरगाह
3. चीन-म्यांमार तेल और गैस पाइपलाइन

* वर्तमान म्यांमार संकट पर भारत का रुख :-

1. हिंसा की तत्काल समाप्ति
2. बातचीत के माध्यम से मुद्दों का शान्तिपूर्ण समाधान।
3. म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना
4. बंदियों की रिहाई
5. मध्यस्थता की सुविधा के लिए एक विशेष आसियान दूत की नियुक्ति
6. म्यांमार को सहायता।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610100?4

BRICS

ब्राजील | रूस | भारत | चीन | साउथ अफ्रीका

→ 2001 में गोल्डमैन सेच के कर्मचारी जीम ओ निल ने अपनी रिपोर्ट Building Better Global Economic BRIC में इसका विचार रखा।

→ इस रिपोर्ट में कहा गया कि 21 वीं सदी में यह 4 अर्थव्यवस्थायें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।

→ 2030 – चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

→ 2050 – भारत दुनिया की 3rd सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

→ इसलिए इन देशों को आपस में सहयोग करना चाहिए

→ 2006 – BRIC देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक

→ 2009 – आधिकारिक शुरुआत रूस के येकतेरिनबर्ग शिखर सम्मेलन से

→ 2010 = साउथ अफ्रीका को शामिल किया

→ SA ने पहली बार 2011 के शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

* BRICS का उद्देश्य / महत्व :-

1. देश - 5
2. विश्व का सतही भाग = 26%
3. विश्व की जनसंख्या = 42%
4. विश्व का कुल GDP = 23%
5. विश्व का व्यापार = 17.

→ बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण

→ विकासशील देशों के हितों की रक्षा

→ समतापूर्ण वैश्विक व्यवस्था का निर्माण

→ अन्तरराष्ट्रीय संगठनों का लोकतंत्रीकरण

→ सहयोग
- → आतंकवाद
- → जलवायु परिवर्तन
- → वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार

* BRICS की उपलब्धियाँ :-

→ 2009 से निरन्तर शीखर सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है।

→ 2012 - शीखर सम्मेलन - नई दिल्ली

→ इसमें BRICS बैंक का विचार

→ IMF में सुधार की मांग की गई।

* न्यू डवलपमेंट बैंक [NDB]

→ 2014 के फोर्टेलेजा ब्राजील सम्मेलन में BRICS बैंक की स्थापना की गई।

→ यह विश्व बैंक का विकल्प होगा।

मुख्यालय = शंघाई [चीन]

* क्षेत्रीय मुख्यालय :-

द० अफ्रीका - जोहान्सबर्ग

ब्राजील = साओ पाउलो

भारत = नई दिल्ली

→ यह एक बहुपक्षीय बैंक है जो सतत विकास परियोजनाओं व बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्त प्रदान करता है।

कुल पूंजी = 500 अरब डॉलर

जिसमें सदस्य देशों की बराबर हिस्सेदारी है।

→ यहाँ मत मूल्य बराबर है।

* आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था [CRA] :-

→ कुल पूंजी = 100 बि. डॉलर

→ चीन - 41 बि. डॉलर

भारत - 18

ब्राजील - 18

रूस - 8

S.A - 5

→ सदस्य देशों में भुगतान संतुलन के संकट के समय उपयोग किया जा सकता है।

→ यह IMF का विकल्प है।

* चुनौतियाँ :- BRICS

1. भारत - चीन जैसे देशों में आपसी विवाद
2. पूंजी की कमी
3. संस्थागत सुधारों के प्रति अलग दृष्टिकोण
   जैसे - NSG
   UNSC
4. यह स्वाभाविक गठजोड़ नहीं है क्योंकि देशों के बीच भौगोलिक सांस्कृतिक, आर्थिक जैसे विभिन्न अन्तर है।
5. BRI प्रोजेक्ट जैसी चीन की संदिग्ध महत्वाकांक्षायें
6. विदेश नीति में संतुलन बनाना कठिन – सीमित सफलता

THE NOTES HUB * All Competition Books * Notes are Available * 7300134518, 7610014004

* 14वाँ शिखर सम्मेलन :- बीजिंग [चीन] → बीजिंग घोषणा - वर्चुअल
[2022 - अध्यक्ष = चीन]

सहयोग

- आतंकवाद
- व्यापार
- स्वास्थ्य
- पारम्परिक दस्तावेज
- प्रौद्योगिकी
- भ्रष्टाचार

* भारत द्वारा प्रस्ताव :-

→ BRICS दस्तावेजों का डिजीटलीकरण

→ MSME क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाना।

SAARC

SOUTH ASIAN ASSOCIATION FOR REGIONAL COOPERATION

दक्षिण - एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन

→ यह एक क्षेत्रीय अन्तसरकारी संगठन है।

स्थापना = 1985 [ढाका]

विचार = जिया उर रहमान

मुख्यालय = काठमांडु

→ विश्व का-

जनसंख्या = 24 %

क्षेत्रफल = 3.4 %

GDP = 4.2 %

सदस्य

1. भारत
2. नेपाल
3. भूटान
4. पाकिस्तान
5. बांग्लादेश
6. अफगानिस्तान
7. मालदीव
8. श्रीलंका

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610100634

* उद्देश्य :-

1. सदस्य देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करना।
2. सदस्य देश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना।
3. क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता को विकसित करना।
4. अन्य क्षेत्रीय संगठनों से सहयोग स्थापित।

✳ SAARC की उपलब्धियाँ :- 1. आर्थिक

✳ SAPTA [1993] :-

→ लागू = 1995

→ इसमें सदस्य देशों को आयात शुल्कों में वरीयता दी गई।

✳ SAFTA – South Asian Free Trade Agreement

→ लागू = 1 जनवरी 2006

→ सदस्य देशों को 2 श्रेणियों में बाँटा गया -

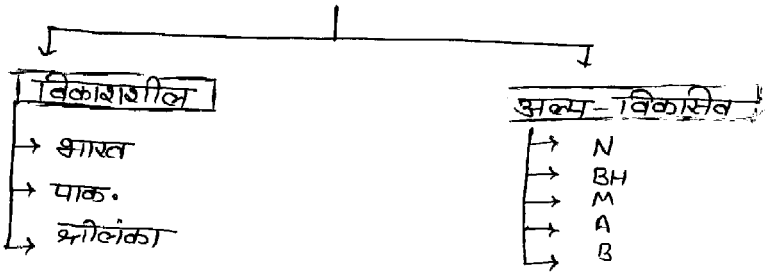

- विकासशील
  - भारत
  - पाक.
  - श्रीलंका
- अल्प-विकसित
  - N
  - BH
  - M
  - A
  - B

→ इन्हें सभी वस्तुओं पर शुल्क खत्म करने के लिए 2012 तक का समय दिया गया।

→ इन्हें शुल्क समाप्ति के लिए 2016 तक का समय दिया गया।

→ परन्तु यह समझौता पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। क्योंकि पाकिस्तान द्वारा गैर-शुल्क बाधाओं का प्रयोग किया गया।

जैसे- नकारात्मक सूची को बढ़ाना

→ 2014 में मोटर वाहन समझौते पर बातचीत हुई परन्तु पाक के विरोध के कारण यह समझौता नहीं किया जा सका।

→ अन्ततः BBIN समझौता [बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल] किया।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610101004

3. भारत के द्वारा SAARC देशों को समर्पित एक उपग्रह प्रक्षेपित किया गया।

* G-SAT-9 :-

→ जो कि मौसम पूर्वानुमान आपदा प्रबन्धन, दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ चिकित्सा जैसी सेवायें उपलब्ध करवायेगा।

→ पाक इस परियोजना का सदस्य नहीं है।

4. SAARC संगठन को भारत के द्वारा 30 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है।

5. भारत में SAARC विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। – दिल्ली

6. सार्क देशों के बीच आपदा प्रबंधन अभ्यास 2015 में भारत में आयोजित

* Note :- * 18 वॉ शिखर सम्मेलन [2014] – काठमांडु

* 19 वॉ शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद में प्रस्तावित था पाक की आतंकवादी गतिविधियों के कारण – असफल

THE NOTES HUB * All Competition Books * Notes are Available * 7300134518, 7610100094

* सार्क की समस्या [विफलताएँ व चुनौतियाँ] :-

1. नियमित रूप से शीखर सम्मेलनों का आयोजन नहीं
2. क्षेत्रीय मुद्दों पर द्विपक्षीय मुद्दों का हावी होना।
3. पाक के द्वारा असहयोग की नीति
4. पाक द्वारा इस क्षेत्र में आतंकवाद को बढ़ावा
5. समझौते का पूर्ण रूप से लागू न होना।
6. बाह्य शक्तियों का हस्तक्षेप जैसे – USA, चीन
7. भारत के प्रति - "बिग ब्रदर सिन्ड्रोम" की आशंका

→ भारत अन्य देशों के मुकाबले अत्याधिक बड़ा है।

8. संशाधनों का अभाव
9. विवाद निवारण तंत्र का न होना

* SAARC का पुनरुद्धार :-

1. दक्षीण - एशियाई देशों का एक प्राकृतिक समूह है।
2. BIMSTEC सार्क का पूरक है प्रतिस्थापक नहीं
3. SAARC की 18 मीटिंग हो चुकी है जबकि BIMSTEC अभी शुरुआती चरण में है।

1. SAARC का कमजोर होना पड़ोसी देशों को दूसरे संगठनों जैसे SCO की तरफ आकर्षित कर सकता है।
5. आर्थिक एकीकरण हेतु आवश्यक
6. पड़ोस प्रथम नीति

BIMSTEC

बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल

→ 6 जून 1997 बैंकॉक घोषणा के माध्यम से → स्थापना

→ जून 1997 BIST-EC संगठन का गठन

↳ बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड → इकोनोमिक को-ऑपरेशन

→ दिसम्बर - 1997 ⇒ म्यांमार को शामिल किया गया। तथा यह BIMSTEC बन गया।

→ 2004 में नेपाल व भूटान को शामिल किया गया। तथा इसे वर्तमान नाम दिया गया।

सचिवालय = ढाका [2014]

महासचिव = तेनजिन लेकफेल

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518

→ विश्व की जनसंख्या = 22%

→ सकल घरेलू उत्पाद = $ 3.7 ट्रिलियन

→ इसमें 16 विषय निर्धारित किये गये हैं — तथा इन्हें सदस्य देशों के बीच बाँटा गया।

→ भारत का विषय = सुरक्षा

* 6 फोकस क्षेत्र :-

1. व्यापार
2. तकनीकी
3. ऊर्जा
4. परिवहन
5. पर्यटन
6. मत्स्यपालन

* सिद्धान्त :-

1. संप्रभुता व समानता का सम्मान
2. क्षेत्रीय अखण्डता का सम्मान
3. आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप
4. अनाक्रमण
5. शांतिपूर्ण सहअस्तित्व
6. राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518

* BIMSTEC की संरचना :-

1. शिखर सम्मेलन
2. मंत्रीस्तरीय बैठके
3. क्षेत्रीय मंत्रिस्तरीय बैठक
4. वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक
5. बिम्सटेक स्थायी कार्य समिति

* 5 शीखर सम्मेलन आयोजित किये जा रहे है -

* 1st = 2004 → बैंकॉक
* 2nd = 2008 → नई दिल्ली
* 3rd = 2014 → नॉपव्योडॉ, म्यांमार
* 4th = 2018 → नई दिल्ली

* 5 वॉ शीखर सम्मेलन - 30 मार्च 2022
  ↳ श्रीलंका

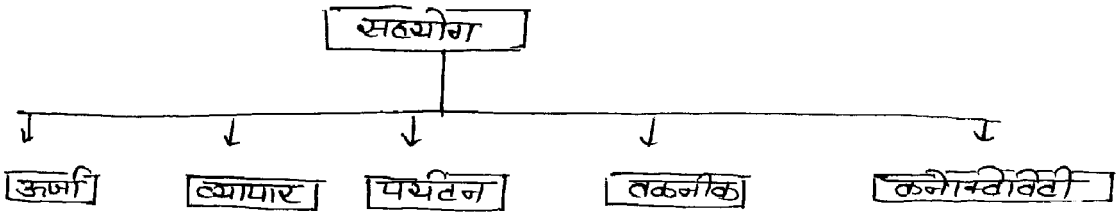

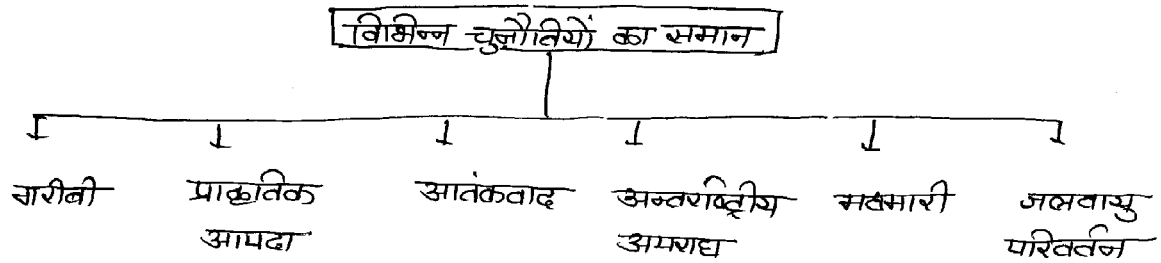

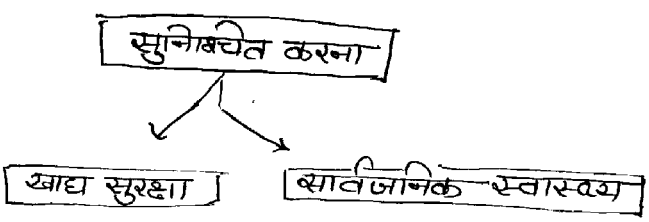

* BIMSTEC की विशेषतायें :—

1. पाक की अनुपस्थिति के कारण आपसी ~~सहयोग~~ ~~सहयोग~~ आसान

2. इन सबके हित बंगाल की खाड़ी में केन्द्रित

3. बंगाल की खाड़ी में आपसी जुड़ाव सुनिश्चित होता है।

4. इसमें दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल है अर्थात —

भारत की एक्ट ईस्ट तथा पड़ोस प्रथम नीति स्वतः शामिल

5. इन शक्तियों में बड़ी शक्तियों का हस्तक्षेप नहीं

6. भारत के अलावा थाईलैण्ड भी उपलब्ध है जो एक मजबूत अर्थव्यवस्था है।

7. BIMSTEC की कार्यप्रणाली अधिक व्यवस्थित है।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610101004

* आगे की राह :—

1. नियमित शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाना चाहिए।

2. सदस्य देशों को BIMSTEC को अधिक वरीयता देनी चाहिए।

3. BIMSTEC के सचिवालय को अधिक प्रभावशाली बनाना

4. 2004 से BIMSTEC देशों के बीच एक मुक्त व्यापार पर बातचीत चल रही है इसे शीघ्र पूरा करना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र संघ

विचार = 1941 → अटलांटिक चार्टर

→ अमेरिका → रूजवेल्ट → हस्ताक्षर
→ ब्रिटेन → चर्चिल → हस्ताक्षर

→ सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन → 26 जून 1945

→ संयुक्त राष्ट्र चार्टर के विस्तृतसंरचना पर हस्ताक्षर किये गये।

स्थापना → 24 अक्टूबर 1945

(संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस)

* मुख्यालय = न्यूयार्क

* सदस्य → 51 [वर्तमान – 193]

* संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषायें है –

→ अंग्रेजी
→ फ्रेंच
→ रूसी
→ चीनी
→ स्पेनिश
→ अरबी

* UN के उद्देश्य :-

1. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा बनाये रखना
2. विश्व में –
   - आर्थिक
   - राजनीतिक
   - सामाजिक

   → सहयोग
3. वैश्विक समस्याओं के समाधान हेतु संयुक्त प्रयास
4. विश्व में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना
5. लोकतंत्र को बढ़ावा

THE NOTES HUB * All Competition Books * Notes are Available * 7300134518, 7610010064

UN के अंग

1. महासभा
2. सुरक्षा परिषद
3. सचिवालय
4. आर्थिक-सामाजिक परि
5. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय
6. न्यास परिषद

* महासभा :-

→ संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख सभा

2. गैर बाध्यकारी संकल्प पारित
3. UN का बजट पारित करना
4. बैठक → प्रत्येक वर्ष → सितम्बर माह में

→ बैठकों की अध्यक्षता → अध्यक्ष [सदस्य देशों में से चुनाव]

→ कार्यकाल = 1 वर्ष ।

* चुनाव :-

A. सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य

B. महासचिव

C. आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य

d. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय जज

E. नये सदस्य को शामिल कराना

* सुरक्षा परिषद :-

→ UN का सबसे शक्तिशाली संस्थान

→ कार्य → अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा व शान्ति बनाये रखना।

→ बाध्यकारी प्रस्ताव पारित करना

→ इन्हें लागू करने के लिए सैन्य हस्तक्षेप व आर्थिक प्रतिबंधों का प्रयोग

→ इसमें कुल 15 सदस्य है –

स्थायी	अस्थायी
5	10

- → अमेरिका
- → चीन
- → रूस
- → फ्रांस
- → UK

- → वीटो पावर प्राप्त
- → स्थायी सदस्यों की सहमति के बिना कोई फैसला नहीं
- → यह एक नकारात्मक शक्ति है।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010004

→ 10 गैरस्थायी सदस्य – 2 वर्ष अवधि → क्षेत्रीय आधार पर

- → 5 सदस्य – एशिया, अफ्रीका [3]
- → 2 सदस्य – पाश्चिमी यूरोप
- → 1 सदस्य – पूर्वी यूरोप
- → 2. सदस्य – लैटिन अमेरिका, द. अमेरिका

* **सचिवालय :–**

→ यह UN की नौकरशाही है।

→ मुख्य कार्य –

- → 1. बैठके आयोजित करना
- → 2. निर्णयों का कार्यान्वयन
- → 3. रिपोर्ट जारी
- → 4. अंतराष्ट्रीय मंचों पर UN का प्रतिनिधित्व करना

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610101004

→ प्रमुख – महासचिव – जिसे सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा चुना जाता है।

→ कार्यकाल = 5 वर्ष

→ वर्तमान – एंटोनियो गुटेरिस

[पुर्तगाल के पूर्व P.M, 9 वें महासचिव]

* आर्थिक एवं सामाजिक परिषद :-

→ मुख्य कार्य - विश्व में आर्थिक एवं सामाजिक विकास सुनिश्चित

सदस्य - 54

कार्यकाल = 3 वर्ष

→ UN से सम्बन्धित विशेष एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित

जैसे - विश्व बैंक
खाद्य व कृषि संगठन
यूनेस्को
विश्व मौसम विज्ञान संगठन

→ इसके अंतर्गत कुछ विशेष आयोग भी स्थापित किये गये है -

जैसे - जनसंख्या नियंत्रण आयोग
महिला सशक्तिकरण आयोग
सतत आयोग (विकास)
विकास आयोग

* अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय :→

→ मुख्य कार्य - सदस्य देशों के बीच विवादों को सुलझाना
- अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों की व्याख्या करना

* न्यायाधीश - 15 [क्षेत्रीय आधार पर चुनाव]

→ कार्यकाल = 9 वर्ष मुख्यालय - हेग [नीदरलैण्ड]

→ वर्तमान - दलवीर सिंह भंडारी [जोधपुर]

* न्यास परिषद :-

→ मुख्य कार्य → शासनादेश प्रणाली के क्षेत्रों का प्रशासन संभालना था।

→ 1994 में पलाऊ की स्वतंत्रता के बाद इसके अधीन कोई क्षेत्र नहीं

→ इसलिए संगठन निष्क्रिय हो गया।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010094

(4) संयुक्त राष्ट्र का मूल्यांकन :-

* सफलताएँ :-

→ तीसरे विश्व युद्ध को रोकने में सफलता मिली।

→ परमाणु ऊर्जा के प्रसार को रोकने के लिए NPT तथा CTBT प्रकार की सन्धियाँ

→ अन्तर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए प्रयास

a) अब तक 70 से ज्यादा शांति मिशन भेजे जा चुके है जैसे-

सोमालिया

सूडान

नाइजीरिया

कोरियाई युद्ध

b) 2001 में शांति नोबल पुरस्कार प्रदान किया।

→ मानवाधिकारों को बढ़ावा दिया गया।

→ विश्व में लोकतंत्र का प्रसार

→ मानव विकास के लिए सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किये।

→ जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए -

पृथ्वी शीखर सम्मेलन

क्योटो प्रोटोकॉल

पेरिस समझौता

* **विफलताएँ :-**

→ UN शीत युद्ध को रोकने में असफल रहा उससे शस्त्रीकरण, सैन्यीकरण शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला।

→ वह खुद को लोकतांत्रिक नहीं बना पाया।

→ अफ्रीका व द. अमेरिका का सुरक्षा परिषद में कोई स्थायी सदस्य नहीं

→ आतंकवाद को परिभाषित नहीं कर पाया।

→ स्थायी देशों के हितों की रक्षा के लिए सैन्य हस्तक्षेप का उपयोग किया जाता है।

→ परमाणु हथियार अभी भी मौजूद है

→ परमाणु को रोकने के लिए की गई सन्धियाँ भेदभावपूर्ण है।

→ UN अपने बजट के लिए आत्मनिर्भर नहीं है। [USA - योगदान सर्वाधिक]

→ वर्तमान में ज्वलंत मुद्दों का सुलझाने में विफल

यूक्रेन संकट

द. चीन सागर विवाद

अफगानी संकट

* सुधार :-

→ संरचनात्मक सुधार लागू करने की जरूरत

जैसे- आज की राजनीतिक स्थिति के अनुसार सुरक्षा परिषद का विस्तार

→ द० अमेरिका व अफ्रीका का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

→ महासभा की पावर बढ़ाना।

→ UN की सुरक्षात्मक गतिविधियों की तुलना में विकासात्मक गतिविधियों पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

→ UN के निर्णयों एवं कार्यों में पारदर्शिता लाना।

* संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका :-

→ भारत UN के संस्थापक सदस्यों में से एक था।

→ सेन फ्रांसिस्को सम्मेलन - भारत की ओर से S. रामास्वामी मुदालियार ने भाग लिया।

→ भारत सुरक्षा परिषद 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है।

→ 1953 - विजयलक्ष्मी पंडित महासभा की अध्यक्ष बनी

→ 1946 - भारत ने UN की रंगभेद नीति का विरोध किया।

→ 1960 - भारत उपनिवेशों को स्वतंत्रता देने की घोषणा का सह प्रायोजक था।

→ 1965 - भारत जर्मनी सौदभाव खत्म करने के प्रस्ताव हस्ताक्षर करने वाला पहला देश था।

→ भारत UN के बजट में निरन्तर योगदान दे रहा है।

→ भारत परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है।

→ भारत UN के शांति मिशनों में सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाला देश है भारत वर्तमान में 14 शांति मिशनों में भाग ले रहा है।

* सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने का भारत का दावा

1. भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
2. दुनिया का हर छठा व्यक्ति भारतीय है।
3. UN के सुरक्षा मिशनों में भारत ने सर्वाधिक योगदान है।
4. भारत विश्व की 5 वीं सबसे बड़ी बढ़ती अर्थव्यवस्था है।
5. भारत अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लगातार योगदान दे रहा है।

→ इसलिए पंचशील सिद्धान्तों को अपनाया गया है।

6. भारत एकमात्र परमाणु शक्ति सम्पन्न देश है जो परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है।
7. भारत विकासशील देशों में अग्रणी है।
8. भारत आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत आवाज है।
9. जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भारत की ओर से प्रयास किये जा रहे हैं।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610100034

✳ स्थायी सदस्यता पाने के लिए प्रयास :-

1. G-4 का निर्माण
   - → जर्मनी
   - → जापान
   - → भारत
   - → ब्राजील

→ जो सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग कर रहे है।

→

2. अफ्रीका, द. अमेरिका, कैरिबियाई देशों के समूह L-69 ने भारत की सदस्यता का समर्थन किया है।

3. अफ्रीकी संघ के C-10 संगठन ने भारत की सदस्यता का समर्थन किया।

4. चीन को छोड़कर अन्य स्थायी सदस्यों ने मौखिक रूप से भारत की सदस्यता का समर्थन किया।

5. भारत ने विभिन्न राजनीतिक मंचों पर यह आवाज उठाई है।

6. भारत - अफ्रीका फोरम शिखर - सम्मेलन 2015 में 54 देशों ने भारत की सदस्यता का समर्थन किया।

ASEAN

ASIAN ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS

स्थापना = 8 अगस्त 1967 [बैंकॉक]

सचिवालय = जकार्ता

आदर्श वाक्य - एक दृष्टि एक पहचान एक समुदाय

* सदस्य = 10

थाईलैण्ड	ब्रुनेई - 1984
मलेशिया	लाओस = 1995
इंडोनेशिया [बाली]	वियतनाम = 1995
सिंगापुर	म्यांमार = 1997
फिलीपिंस	कंबोडिया = 1999

THE NOTES HUB * All Competition Books * Notes are Available * 7300134518, 7610010064

* उद्देश्य :-

*. सदस्य देशों के बीच सम्बन्ध आसियान के सिद्धान्त पर आधारित है। जिसके अनुसार -

1. दूसरे देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना।
2. दूसरे देशों की सम्प्रभुता व अखण्डता (क्षेत्रीय) का सम्मान
3. क्षेत्रीय विवादों को बातचीत से सुलझाना

* आसियान के विभिन्न संगठन :-

→ आसियान एक सफल संगठन है।

→ इसमें आसियान द्वारा विभिन्न देशों से बातचीत की जाती है -

आसियान + 1	आसियान + 3	आसियान + 6
भारत + आसियान	चीन	चीन
चीन + आसियान	जापान	जापान
USA + आसियान	दक्षिण कोरिया	द. कोरिया
		आस्ट्रेलिया
		न्यूजीलैण्ड
		भारत

आसियान + 6

→ आसियान द्वारा इन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किये गये हैं।

RCEP

REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP

→ यह आसियान एवं उसके 5 मुक्त व्यापार समझौते वाले देशों [भारत को छोड़कर] के मध्य सम्पन्न क्षेत्रीय व्यापार समझौता है।

1. वस्तु
2. सेवा
3. निवेश
4. भौतिक सम्पदा

→ शामिल

कार्यान्वयन = 1 जनवरी 2022

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010034

* भारत इससे पीछे हट गया क्योंकि –

1. भारत में चीन से आयात बढ़ सकता है जिससे व्यापार घाटा और अधिक बढ़ जायेगा।

2. अन्य आसियान देशों के साथ व्यापार भी असंतुलित है।

3. भारत 3 प्रकार की व्यवस्थायें चाहता था –

* चीन के लिए – 74%
* आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैण्ड = 86%
* अन्य देशों के लिए = 94%

→ सम्मिलित करने का प्रस्ताव

→ लेकिन बाकी देश इस पर सहमत नहीं हुए।

4→ भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का विरोध किया।

5→ जापान व द. कोरिया बौद्धिक सम्पदा के कड़े नियम चाहते थे।

6. आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैण्ड से डेयरी आयात बढ़ सकता है।

7. भारत रूल ऑफ ऑरिजिन के लिए सख्त नियम चाहता था।

8. भारत ऑटो ट्रिगर ऑर्डर चाहता था

↳ शर्त – यदि आयात में अत्यधिक वृद्धि हो तब भारत फिर से आयात शुल्क बढ़ा सकता है।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610100004

* RCEP – आगे की राह :-

1. भारत को तत्काल प्रभाव से आर्थिक सुधार लागू करने चाहिए जिससे कि भारतीय उद्योग तथा निर्यात प्रतिस्पर्धी हो सके।

2. निकट भविष्य में RCEP का सदस्य बनना चाहिए।

3. USA व EU के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को पूरा करना

* आसियान + 8

आसियान +6 → U.S.A
→ रूस

→ इसके रक्षा मंत्रियों की भी बैठक होती है।

→ इसे ईस्ट-एशिया समिट भी कहा जाता है।

THE NOTES HUB * All Competition Books * Notes are Available * 7300134518, 7610100004

* एशियन रिजनल फोरम :-

→ यह क्षेत्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने का मंच है।

स्थापना = 1997

सदस्य = 27

* आसियान इकॉनोमिक कम्युनिटी :-

→ 2015 में AEC की स्थापना

→ यह एक सांझा बाजार है जिसमें → वस्तु, सेवा, निवेश, मानव संसाधन → आदि का मुक्त प्रवाह

* कमियाँ :-

→ आसियान दक्षिण-चीन सागर विवाद को हल करने में असफल रहा।

भारत - आसियान सम्बन्ध

* राजनीतिक सम्बन्ध :-

* 1991 - पूर्व की ओर देखो नीति प्रारम्भ की गई।

* 1991 :- भारतीय एक क्षेत्रीय संवाद भागीदार है।

* 1996 :- भारत पूर्ण संवाद भागीदार बना।

* 2002 :- भारत + आसियान शीखर सम्मेलन प्रारम्भ

* 2012 :- रणनीतिक व सामरिक साझेदारी

* 2014 :- पुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया।

* 2017 :- 25 वर्ष पूर्ण होने पर स्मरण वर्ष के रूप में मनाया गया।

→ रणनीतिक साझेदारी का केन्द्र समुद्री क्षेत्र होगा।

* 2022 :- 30 वर्ष पूर्ण होने पर मैत्री वर्ष के रूप में नामित किया गया।

* आर्थिक सम्बन्ध :-

* 2003 :- भारत-आसियान व्यापार परिषद

*→ आसियान भारत का 4th सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।

→ द्विपक्षीय व्यापार करीब = 400 अरब डॉलर

* 2009 :- वस्तुओं में मुक्त व्यापार समझौता

* 2014 :- सेवाओं व निवेश में FTA

→ भारत आसियान के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य।

* रक्षा सम्बन्ध :-

* आसियान - भारत समुद्री अभ्यास - [AIME-2023]

→ 8 मई 2023 को दक्षिण-चीन सागर में

* अन्य अभ्यास :-

* बोल्ड - कुरुक्षेत्र = भारत + सिंगापुर

* मिलन अभ्यास = आसियान समूह

* मैत्री अभ्यास = भारत - थाईलैण्ड

19 वाँ आसियान - भारत शिखर सम्मेलन
[कंबोडिया – नवम्बर - 2022]

→ मौजूदा रणनीतिक साझेदारी को व्यापार रणनीतिक साझेदारी में बदलना

* **सहयोग के क्षेत्र :-**

1. समुद्री गतिविधियाँ
2. आतंकवाद विरोध
3. अन्तर्राष्ट्रीय अपराध
4. साइबर सुरक्षा
5. डिजिटल अर्थव्यवस्था
6. पर्यावरण

THE NOTES HUB * All Competition Books * Notes are Available * 7300134518, 7610014004

→ दोनों हिन्द प्रशान्त क्षेत्र में – शान्ति, स्थिरता, समुद्री सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता → को बढ़ाने हेतु कार्य करेंगे।

→ आसियान - भारत समझौते (व्यापार) [AITIGA] की समीक्षा में तेजी लाने का प्रस्ताव है।

G-77

सदस्य - 77 [वर्तमान - 134]

→ UNCTAD की अनुशंसा पर 1964 में स्थापना
[UNITED NATIONS CONFERNCE ON TRADE & DEVELOPMENT]

→ पहली मंत्रिस्तरीय बैठक = 1967 - अल्जीरिया [द. अफ्रीका

→ सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था को साउथ समिट कहा जाता है।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610014004

* उद्देश्य :-

1. दक्षिण - दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना।

2. विकासशील देशों में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना।

3. फिलहाल - G-77 का दायरा UN की महासभा तक सीमित है

4. हर साल सभी देशों को मौका देने के लिए राष्ट्रपति पद बदला जाता है।

जैसे - 2022-23 - क्यूबा

G-24

→ यह G-77 देशों के विकासशील देशों का समूह है।

G – 20

सदस्य = 19 देश + EU

स्थापना = 1999

[1997 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद]

* यह प्रतिनिधित्व करता है -

GDP = 85%
जनसंख्या = 2/3
व्यापार = 80%
→ विश्व

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610104004

→ यह प्रमुख विकसित व विकासशील देशों का समूह है।

→ मंच → केन्द्रीय बैंकों के गवर्नर
→ देशों के वित्त मंत्रियों के मंच
→ द्वारा शुरू

मंच
- मौद्रिक ↓ केन्द्रीय बैंक के गवर्नर
- राजकोषीय ↓ वित्त मंत्री

→ इसका मुख्य कार्य सदस्य देशों की राजकोषीय व मौद्रिक नीति के बीच समन्वय स्थापित करना है।

→ 2007-08 की वैश्विक मंदी के बाद इसका पुनर्गठन किया गया।

→ इसे राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन बनाया गया।

→ पहला शिखर सम्मेलन – 2008 – वाशिंगटन डी.सी

→ इसके बाद से नियमित सम्मेलन आयोजित किये जा रहे है।

*** G-20 के उद्देश्य :–**

1. वित्तीय विनियमन को बढ़ावा देना।
2. एक नया अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय ढाँचा तैयार करना।
3. स्थिरता एवं जलवायु परिवर्तन के लिए नीति समन्वय

THE NOTES HUB * All Competition Books * Notes are Available * 7300134518, 7610010024 *

वार्ता

1. **वित्तीय ट्रैक**

→ इसमें केन्द्रीय बैंक के गवर्नर व वित्त मंत्री भाग लेते है।

→ आर्थिक मुद्दों पर चर्चा

2. **शेरपा ट्रैक**

→ प्रत्येक देश एक शेरपा नियुक्त करता है जो G-20 की बैठकों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है

→ इसके अन्तर्गत भ्रष्टाचार, राजनीतिक जुड़ाव आदि पर चर्चा [आर्थिक मामलों के अतिरिक्त

→ यह विभिन्न एंगेजमेंट ग्रुप से मिलता है।

* **एंगेजमेंट ग्रुप :-** अर्थ = समाज के विभिन्न तबके

— जी-20 ट्रोइका —

→ शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए 3 समूहों देशों के समूहों का एक प्रबन्धन समूह गठित।

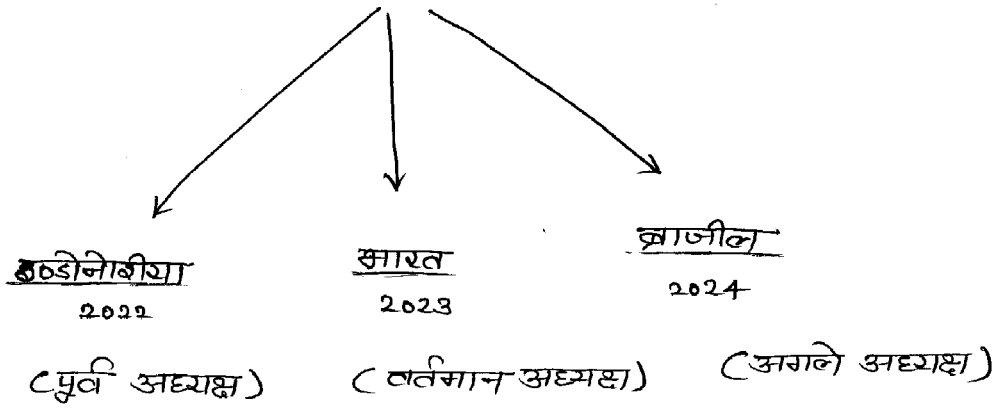

इंडोनेशिया	भारत	ब्राजील
2022	2023	2024
(पूर्व अध्यक्ष)	(वर्तमान अध्यक्ष)	(अगले अध्यक्ष)

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610100034

* **उद्देश्य :- महत्व :**

1. प्रतिनिधि समूह
2. वृद्धि और विकास को समर्थन
3. अन्य मुद्दे = जलवायु परिवर्तन

* **उपलब्धियाँ :-**

→ 2008 के वित्तीय संकट के दौरान आपातकालीन वित्त घोषणा

→ कराधान सम्बंधी सुधार

* G-20 - आगे की राह :-

* दक्षता बढ़ाने हेतु सुधार-

1. सचिवालय स्थापित किया जाये
2. आर्थिक मुद्दों पर ध्यान देना
3. गैर आर्थिक मुद्दों को अन्य मंचों के लिए छोड़ देना
4. सदस्य देशों को वैश्विक हितों के लिए कार्य करना चाहिए।
5. संकीर्ण राष्ट्रीय हितों को कम प्राथमिकता देना।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010004

* भारत की G-20 की अध्यक्षता

→ 1 दिसम्बर 2022 → 30 नवम्बर 2023

→ भारत विभिन्न 32 कार्यक्षेत्रों में 50 से अधिक शहरों में 200 से अधिक बैठकों की मेजबानी करेगा।

→ 9-10 सितम्बर 2023 को भारत के प्रगति मैदान नई दिल्ली में G-20 शिखर सम्मेलन की 18 वीं बैठक की मेजबानी करेगा

* लोगो [प्रतीक चिह्न]

→ यह भारत के राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरणा लेता है।

→ यह पृथ्वी ग्रह को कमल के साथ जोड़ता है।

पृथ्वी ग्रह = जीवन के प्रति भारत के ग्रह समर्थक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

कमल = चुनौतियों के बीच विकास

* थीम :-

"वसुधैव कुटुम्बकम्"

[एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य]

→ यह महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है।

→ यह पृथ्वी ग्रह पर सभी जीवन के मूल्यों [मानव, पशु, पौधे, व सूक्ष्मजीव] की पुष्टि करता है।

→ यह विषय व्यक्तिगत जीवनशैली के साथ-साथ राष्ट्रीय विकास व दोनों स्तरों पर लाइफ [जीवन] [LiFE] (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) पर प्रकाश डालता है।

भारत की प्राथमिकताएँ :-

1. हरित विकास, जलवायु वित्त व लाइफ [लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट - LiFE]
2. त्वरित समावेशी व लचीला विकास
3. SDG की तेज प्रगति
4. तकनीकी बदलाव व डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर
5. 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान
6. महिलाओं के नेतृत्व में विकास

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610100064

पश्चिम एशिया

* **अरब स्प्रिंग** :-

→ उत्तरी अफ्रीका व प. एशिया के वे देश जहाँ अरबी भाषा बोली जाती है अरब देश कहलाते है।

→ 2010-11 ई. में यहाँ तानाशाही शासनों को लोकतंत्र से प्रतिस्थापित किया गया।

→ इस घटना को अरब स्प्रिंग कहते है।

उदाहरण = 2010 - ट्युनीशिया

→ दमनकारी शासन व निम्न जीवन स्तर के कारण विरोध प्रदर्शन

→ मिस्र = होशनी मुबारक हटाये गये

→ यमन

→ लीबिया - UNSC द्वारा सैन्य हस्तक्षेप के बाद गद्दाफी की तानाशाही को हटाया गया।

* **सीरिया** —

→ बशर अल असद की तानाशाही द्वारा शासित जिसने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610100084

→ रूस के वीटो के कारण उसके विरुद्ध सैन्य हस्तक्षेप नहीं हो सका जिससे सीरियाई गृहयुद्ध शुरु हो गया।

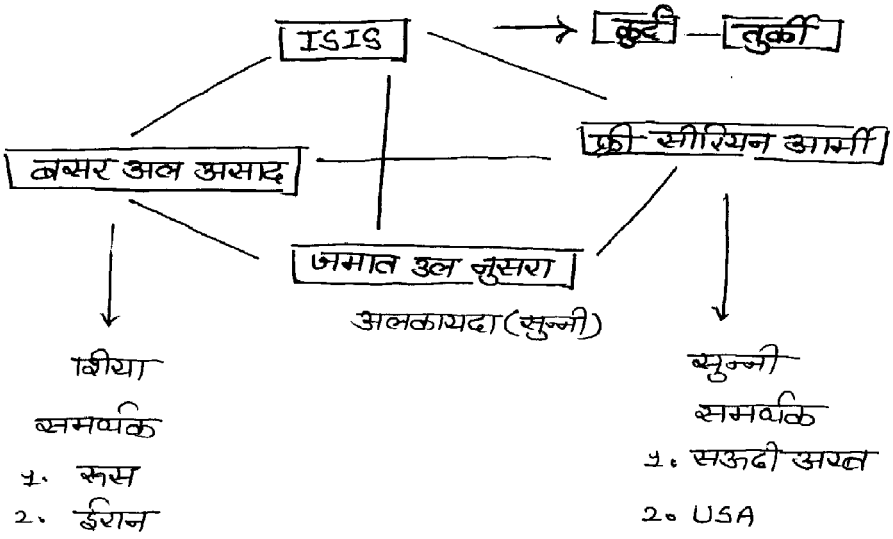

* कुर्द :-

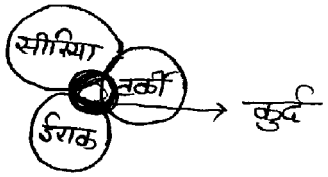

→ यह एक जनजाति है जो सीरिया, तुर्की, व ईराक में रहती है।

* माँग - कुर्दिस्तान बनाने की।

→ कुर्द बलों ने जमीन पर ISIS के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनकी सेना को YPG कहा जाता है।

→ पहले उन्हें अमेरिका का समर्थन हासिल था।

→ लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार ने उनसे समर्थन वापस ले लिया।

→ जिसके बाद तुर्की ने उन पर हमला कर दिया।

THE NOTES HUB
All Competition Books & Notes are Available
7300134518, 7610010004

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010034

★ ISIS [इस्लामिक स्टेट ऑफ ईराक एंड सीरिया] :-

अन्य नाम = IS

→ उदय - ISIS :- उत्तरी ईराक में सुन्नी बहुमत है। जबकि दक्षिणी ईराक में शिया।

★ 2003 — ईराकी फ्रीडम

→ अमेरिका ने हमला कर सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया।

→ शियाओं के प्रभुत्व वाली लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की।

→ इस सरकार ने सुन्नियों के साथ भेदभाव किया। जिसका फायदा अलकायदा को मिला।

→ अलकायदा की शाखा इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक की स्थापना अबू बक्र अल बगदादी ने की थी।

→ 2011 में अमेरिकी सेना को इराक से हटा लिया गया।

→ 2012 में सीरिया में गृहयुद्ध शुरु हो गया। जिसके चलते ISIS को हथियार भी सप्लाई किये गये।

→ इराक की सरकार बहुत कमजोर थी इसलिए ISI ने उत्तरी इराक पर कब्जा कर लिया।

→ ISIS की स्थापना 2014 में हुई थी, बगदादी ने खिलाफत प्रणाली को पुनर्जीवित किया व खुद को खलीफा घोषित किया।

* ISIS का पतन :-

→ 2014 में अमेरिका के नेतृत्व में हवाई हमले किये गये थे।

→ ISIS के खिलाफ ईरान व रूस ने भी हमला बोला।

→ जमीनी स्तर पर लड़ाई कुर्द बलों द्वारा लड़ी गई।

→ तेल संसाधनों को उनसे मुक्त कराया था।

→ इनके खिलाफ दूसरे देशों की सुरक्षा एजेंसियों ने कार्यवाही की।

→ मार्च 2019 में अमेरिकी सेना ने एक ऑपरेशन में बगदादी को मार गिराया।

→ ISIS इस समय अफ्रीका में सक्रिय है।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010004

⊕ भारत पर प्रभाव :-

1. भारत से भी कुछ युवा ISIS में शामिल हुए हैं इसलिए हिंसक गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं।

2. शीया - सुन्नी विवाद बढ़ सकता है।

3. साम्प्रदायिक सौहार्द्र भंग हो सकता है।

4. कश्मीर व उत्तरी केरल में ISIS के सक्रिय होने से आतंकी गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं।

5. शरणार्थी संकट हो सकता है।

✪ यमन संकट :-

→ अरब स्प्रिंग के दौरान यमन में एक शिया नेता अल हूती द्वारा अलगाववादी आन्दोलन चलाया गया था।

→ उनके अनुयायी = हूती विद्रोही

→ हूती विद्रोहियों के विरोध के कारण यमन के राष्ट्रपति मंसूर हादी को सऊदी अरब में शरण लेनी पड़ी।

→ ऐसी परिस्थितियों में सऊदी अरब के नेतृत्व में सुन्नी देशों ने यमन पर हवाई हमले किये तथा यहाँ गृहयुद्ध शुरू कर दिया।

→ यमन में मानवीय संकट पैदा हो गया।

→ UN की मध्यस्थता से एक शांति समझौता हुआ। लेकिन यह समझौता लागू नहीं हुआ।

→ हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल था।

* ऑपरेशन राहत :-

→ भारतीयों द्वारा यमन से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610100034

भारत - ईरान सम्बन्ध

★ **इजराइल - फिलिस्तीन विवाद :-**

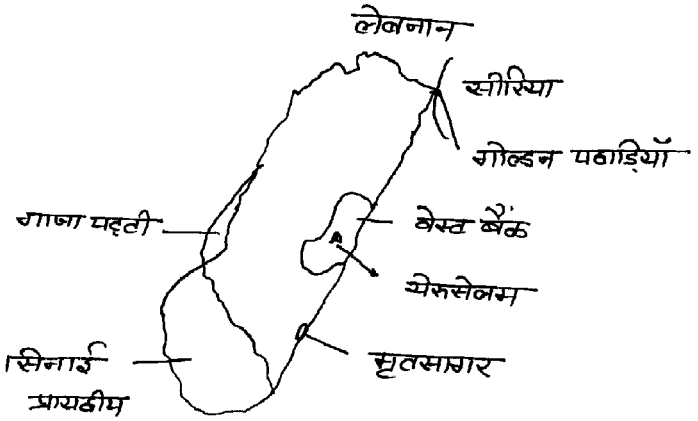

येरूसेलम का धार्मिक महत्व :-

→ येरूसेलम निम्न 3 धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है।

1. इस्लाम :-

→ यहाँ अल अक्सा मस्जिद है जो मक्का व मदीना के बाद इस्लाम में तीसरी सबसे पवित्र जगह है।

→ यहीं पर डॉमऑफ रॉक स्थित

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610014004

2. यहूदी :-

→ यहूदियों की सबसे पवित्र जगह हॉली ऑफ हॉलीज येरूसेलम में स्थित

→ यद्यपि इसकी वर्तमान स्थिति ज्ञात नहीं है।

→ वर्तमान में यहूदियों की सबसे पवित्र जगह वेस्टर्न वॉल है।

3. ईसाई :- ईसा मसीह को येरूसेलम में ही सूली पर लटकाया गया था, जहाँ एक चर्च का निर्माण किया गया।

→ प्रारम्भ में इस क्षेत्र में यहूदियों का निवास था परन्तु कालान्तर में वे यूरोप के विभिन्न देशों में बस गये।

* भारत पर प्रभाव

→ 1. भारत का ऊर्जा आयात प्रभावित होगा।

2. ईरान में चल रहे चाबहार बंदरगाह जैसे प्रोजेक्ट प्रभावित होंगे।

3. ईरान में चीन का प्रभाव बढ़ेगा।

4. ईरान और चीन के बीच 400 अरब डॉलर का समझौता

→ चीन ईरान में बुनियादी ढांचे का निर्माण

→ ईरान चीन को तेल व गैस की आपूर्ति करेगा।

भारत - ईरान सम्बन्ध

→ 1947 तक दोनों देशों की सीमा साझा थी।

→ भारत व ईरान ने 15 मार्च 1950 को राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किये

→ तेहरान घोषणा = 2001

→ नई दिल्ली घोषणा - 2003

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518

* चाबहार बंदरगाह का महत्व :-

→ मध्य एशिया से भौतिक सम्पर्क स्थापित किया जायेगा।

→ ईरान के साथ रिश्ते मजबूत होंगे।

→ इससे अफगानिस्तान में शान्ति स्थापित करने में मदद

→ ग्वादर बंदरगाह का महत्व कम होगा।

→ प. एशिया के व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे।

→ चीन के बढ़ते प्रभाव को कम किया जा सकता है।

GCC - खाड़ी सहयोग परिषद

→ स्थापना = 1982

→ मुख्यालय = रियाद [सऊदी अरब]

→ सदस्य — सऊदी अरब
ओमान
UAE
बहरीन
कुवैत
कतर

OPEC

ORGANIZATION OF PETROLEAM EXPORTING CON.

स्थापना = 1960

मुख्यालय = वियना

सदस्य = 13

→ यह सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को नियंत्रित करता है।

इजराइल–फिलिस्तीन विवादः–

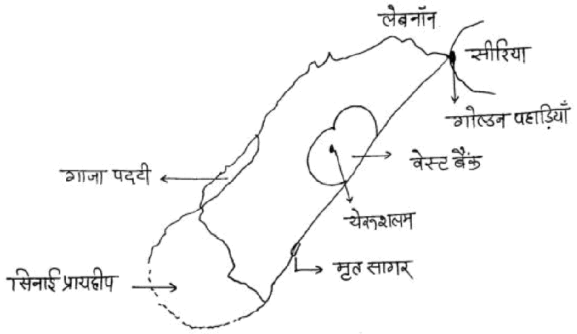

THE NOTES HUB * All Competition Books & Notes are Available * 7300134518

येरूशलम की धार्मिक महत्ताः–

- यह तीन धर्मों के लिये महत्वपूर्णः–
  - (i) इस्लाम– यहाँ अल–अक्सा मस्जिद स्थित है जो कि इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। यहाँ पर डोम ऑफ रॉक स्थित है।
  - (ii) यहूदी– इनका सबसे पवित्र स्थल 'Holy of Holies' है जो येरूशलम में स्थित है। वर्तमान में यहूदियों का सबसे पवित्र स्थल 'Western Wall' है। ऐसा मान जाता है कि Western Wall, Holy of holies के सबसे निकट स्थित है।
  - (iii) ईसाई– ईसा मसीह को येरूशलम में ही सूली पर लटकाया गया था। इसेलये यहाँ एक चर्च का निर्माण किया गया है।
- प्रारम्भ में इस क्षेत्र में यहूदियों का निवास था। बाद में/ कालान्तर में यहूदी, यूरोप के अन्य देशों में बस गये।
- इस क्षेत्र में अरब फिलिस्तिनीयों का अधिकार हो गया तथा यह क्षेत्र ओटोमन साम्राज्य के अधीन हो गया।
- 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र आधारित राज्यों की मांग बढ़ी।
- 1897 ई. में यहूदियों के द्वारा जायोनिस्ट आंदोलन की शुरूआत की गई। जिसका उद्देश्य एक अलग यहूदी राष्ट्र। राज्य का निर्माण करना था।
- 1917 में ब्रिटेन के विदेश मंत्री बेलफॉर ने घोषणा की कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन जायोनिस्ट आंदोलन का समर्थन करेगा। इसे बेलफॉर घोषणा कहा जाता है।
- प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया तथा यह क्षेत्र ब्रिटेन के अधीन आ गया।
- ब्रिटेन ने बेलफॉर घोषणा को लागू किया जिससे इस क्षेत्र में यहुदियों की संख्या बढ़ गई।
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहुदियों पर अत्यधिक अत्याचार किये गये जिससे भी इस क्षेत्र में यहुदियों की संख्या बढ़ने लगी।
- 1947 में यह विवाद UN में उठाया गया।
- UN ने समाधान में द्विराज्य सिद्धांत अपनाया (अर्थात् इस क्षेत्र को लगभग दो बराबर भागों में बाँट दिया गया है। जो निम्न हैः– (1) इजराइल (2) फिलिस्तीन
- येरूशलम को UN के अधीन एक अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित किया गया।
- यहुदियों ने इस समाधान को स्वीकार कर लिया परन्तु अरब देशों ने इसे नकार दिया।
- 14 मई, 1948 को ब्रिटेन द्वारा इस क्षेत्र को आजाद कर दिया गया तथा इसी दिन इजराइल नामक नये दशे की स्थापना की गई।

→ इस सिद्धान्त के तहत इस क्षेत्र 2 बराबर भागों में बाँट दिया जाना चाहिए।

→ एक भाग यहूदियों को दिया जाये जहाँ इजरायल की स्थापना हो सके।

→ दूसरा भाग फिलिस्तीनियों को दिया जाना चाहिए।

→ यहूदियों ने इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया किन्तु अरब देशों ने इसे नकार दिया।

→ 14 मई 1948 को ब्रिटेन ने इस क्षेत्र को आजाद कर दिया उस दिन इजरायल नामक देश की स्थापना हुई।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010004

प्रथम अरब - इजरायल युद्ध

→ 15 मई 1948 को अरब देशों के गठबंधन ने इजरायल पर आक्रमण कर दिया।

→ यह आक्रमण 1 वर्ष तक चला।

* परिणाम :-

→ लगभग 78% भाग पर इजरायल का अधिकार हो गया।

→ गाजापट्टी पर मिस्र तथा वेस्ट बैंक जॉर्डन का अधिकार हो गया।

→ येरुसलम को 2 भागों में विभाजित किया गया।

पश्चिमी येरुसेलम = इजरायल

पूर्वी = जॉर्डन

→ बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी शरणार्थी बन गये।

6-DAY WAR

→ 5 जून 1967 से 10 जून 1967 के मध्य

इजरायल V/S अरब राष्ट्रसंघ

→ इस युद्ध में इजरायल की एकतरफा जीत हुई।

→ इजरायल ने गाजा पट्टी
वेस्ट बैंक
गोलन पहाड़ियाँ
सिनाई प्रायद्वीप
→ पर अधिकार किया।

* योम-किप्पुर युद्ध :-

→ 1973 - इसमें अरब देश इजरायल को हरा नहीं सके।

⭐ कैम्प डेविड समझौता :- 1979 ई.

→ USA की मध्यस्थता से मिस्र-इजरायल के बीच यह समझौता हुआ।

→ मिस्र को सिनाई प्रायद्वीप वापस दे दिया गया।

→ इजरायल व मिस्र के बीच 1979 में राजनयिक संबंध शुरू हुए।

* प्रथम इंतीफादा :-

इंतीफादा → अरबी भाषा का शब्द → हिंसक विद्रोह

→ 1987-1993 तक फिलिस्तीनियों के द्वारा विद्रोह किये गये।

→ इसी समय फिलीस्तीनी आतंकी संगठन हमास की स्थापना हुई।

→ हमास को ईरान का समर्थन प्राप्त है।

ओस्लो समझौता - 1993 & 1995

इजरायल + PLO [Palestine Liberation Organization]

↓

मध्यस्थता = USA

→ स्थापना - 1964

नेता = यासीर अराफात

→ ओस्लो समझौते में द्विराज्य सिद्धान्त को स्वीकार किया गया।

→ अर्थात् वेस्टबैंक व गाजापट्टी फिलीस्तीन को दिया जाना तय हुआ।

→ यद्यपि आज भी यह समझौता पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है।

→ वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर ही फिलिस्तीनियों का कब्जा है।

* द्वितीय इंतीफादा [2000-2005]

→ 2005 में गाजापट्टी से इजरायली सेना को वापस बुला लिया गया

→ गाजा पट्टी के चारों ओर एक नाकेबंदी लागू कर दी गई जिससे एक मानवीय संकट उत्पन्न हो गया।

→ 2007 में गाजापट्टी पर हमास का शासन स्थापित हुआ।

→ हमास के द्वारा समय-समय पर आतंकी हमले किये जाते है जिसके कारण यहाँ युद्ध की स्थितियाँ बन जाती है

⊛ USA – इजरायल :–

→ 2018 - USA के द्वारा अपने दूतावासको येरूसेलम में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

→ अर्थात् USA ने आधिकारिक रूप से येरूसेलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता दी गई।

→ इजरायल द्वारा गोलन पहाड़ियों में से एक पहाड़ी का नाम ट्रम्प पहाड़ी रख दिया।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610110094

✱ अब्राहम समझौता – सितम्बर 2020 :–

→ USA की मध्यस्थता

→ इस समझौते से बहरीन व UAE ने इजरायल के साथ कूटनीतिक सम्बन्धों की स्थापना की।

→ इस समझौते से पश्चिम एशिया में शान्ति की राह खुलेगी।

→ इजरायल को मान्यता प्राप्त हुई। [राज्य के रूप में]

→ UAE व बहरीन को इजरायली तकनीक और निवेश प्राप्त होगा।

→ इससे पूर्व मिस्र ने 1979 व जॉर्डन ने 1994 में इजरायल से कूटनीतिक सम्बन्ध कर लिये थे।

→ इस समझौते से फिलिस्तीनी आन्दोलन कमजोर होगा।

Ⓓ समस्यायें :-

1. हमास की आतंकी गतिविधियाँ
2. वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियाँ
3. येरूसेलम का अधिकार
4. पेयजल का संकट / मीठे पानी का एकमात्र स्रोत = Sea of Galilee
5. फिलिस्तीन गाजापट्टी व वेस्ट बैंक के बीच एक गलियारा चाहता है।
6. USA की मध्यस्थता की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न है क्योंकि USA का झुकाव इजरायल की ओर है।

भारत - इजरायल सम्बन्ध

→ 1950 ई. में भारत ने दो राज्यों अर्थात् इजरायल व फिलिस्तीन के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया।

→ भारत व इजरायल सम्बन्धों को 3 चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books & Notes are Available ★ 7300134518, 7610104004

1. 1992 से पहले :-

→ प्रारम्भ में भारत फिलिस्तीन का समर्थक था

→ वर्ष 1992 में भारत व इजरायल के बीच राजनयिक सम्बन्ध स्थापित

2. 1992 – 2014

→ व्यावहारिक व संतुलित नीति

→ इजरायल व फिलिस्तीन के साथ अच्छे सम्बन्ध

3. 2014 से अब तक

→ भारत इजरायल का समर्थक बन गया।

→ डी-हाइफनेशन की नीति

→ भारत इजरायल व फिलिस्तीन दोनों के साथ अलग और स्वतंत्र सम्बन्ध बनाये रखेगा।

सहयोग के क्षेत्र

1. पश्चिम चतुर्भुज :- QUAD

→ यह चार देशों का एक समूह है —
- → भारत
- → इजरायल
- → USA
- → UAE

* महत्व :-

1. मजबूत सम्बन्धों की स्थापना एवं व्यापार में वृद्धि
2. भारत की रक्षा क्षमता में वृद्धि
3. भारत-अरब क्षेत्र की सुरक्षा
4. पश्चिम एशिया में शान्ति स्थापित
5. बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण
6. चीन का वर्चस्व कम।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010004

2. द्विपक्षीय व्यापार :-

→ भारत व इजरायल — द्विपक्षीय व्यापार → 9 अरब डॉलर

3. रक्षा सहयोग :-

→ इजरायल भारत का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा उपकरणों का निर्यातक है।

बराक - 8

स्पाइक [एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल]

ड्रोन - हारोप व हेरोन

4. ऊर्जा सहयोग :-

→ इजरायल ने अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में सदस्यता ले ली।

5. कृषि सहयोग :-

→ इजरायल राजस्थान राज्य में ड्रिप सिंचाई का समर्थन कर रहा है।

भारत - संयुक्त अरब अमीरात

→ भारत UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता [CEPA] = 18 फरवरी 2022

→ 5 वर्षों के अन्दर द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना

a) $100 बिलियन वस्तु में

b) $15 बिलियन = सेवाओं में

→ भारत के लगभग 90% उत्पादों पर UAE में शून्य शुल्क लगेगा।

→ BHIM UPI संयुक्त अरब अमीरात में उपलब्ध है।

[UPI- भूटान व नेपाल]

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010004

*** रक्षा सहयोग :-**

*** सैन्य अभ्यास :-**

→ समुद्री सहयोग के लिए डेजर्ट ईगल

2) **अंतरिक्ष :-**

→ इसरो ने UAE का पहला नैनो -सेटेलाइट नायिफ-1 लॉन्च किया।

I2U2

→ भारत - इजरायल - UAE - USA

→ इसे पश्चिमी एशिया क्वाड के नाम से भी जाना जाता है।

→ व्यापार व निवेश में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना।

→ चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक = 18 Oct 2021

* सहयोग के 6 क्षेत्र :-

1. पानी
2. ऊर्जा
3. यातायात/परिवहन
4. अंतरिक्ष
5. स्वास्थ्य
6. खाद्य सुरक्षा

* पहला I2U2 शीखर सम्मेलन [वर्चुअल] = जुलाई 2022

→ I2U2 गुजरात में हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा प्रोजेक्ट में निवेश करेगा।

भारत - सऊदी अरब संबंध

* रणनीतिक साझेदारी परिषद :-

स्थापित = अक्टूबर 2019

* 2 मुख्य स्तम्भ -

1. राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक व सांस्कृतिक समिति
2. अवसंरचना व निवेश पर समिति

सहयोग के क्षेत्र

1. कृषि एवं खाद्य सुरक्षा
2. ऊर्जा
   → भारत कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातकर्ता
3. प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी
4. उद्योग और बुनियादी ढांचा

5. सांस्कृतिक सहयोग :-

→ भारतीय सऊदी अरब के पवित्र शहरों मक्का व मदीना में हज यात्रा पर जाते है।

→ योग - सहयोग पर समझौता
[खाड़ी क्षेत्र में किसी देश द्वारा पहली बार]

6. रक्षा सहयोग

1. द्विपक्षीय अभ्यास -
   अल मोहम्मद अल हिन्दी
2. रक्षा सहयोग पर भारत सऊदी अरब संयुक्त समिति

PM का मिस्र दौरा

→ 24-25 जून 2023

→ द्विपक्षीय सम्बन्धों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाना

* इसमें 4 तत्व शामिल है –

1. राजनीतिक रक्षा व सुरक्षा
2. आर्थिक भागीदारी
3. वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक सहयोग
4. सांस्कृतिक एवं लोगों के बीच सम्पर्क

* समझौते :–

1. खाद्य
2. पुरातत्व और पुरावशेषों
3. प्रतिस्पर्धा कानून

→ भारतीय PM को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया।

→ PM ने काहिरा में अवास्थित 11 वीं सदी की अल हकीम मास्जिद का दौरा किया। [दाऊदी बोरा समुदाय स्थल]

* मिस्र का महत्व :–

* मिस्र का भू सामरिक महत्व :– मुख्य व्यापार मार्ग पर स्थित है।

* सू - राजनीतिक :- मिश्र विकासशील देशों के कई मंचों में भागीदार है

जैसे - गुट निरपेक्ष , G77

* भारत के लिए नया बाजार :-

→ मिश्र लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस आकाश मिसाइल जैसे रक्षा उपकरणों में दिलचस्पी दिखाई |

* ऊर्जा सुरक्षा :-

→ मिश्र कच्चे तेल व गैस का निर्यातक देश है |

पश्चिम एशीया का महत्व

1. भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयातों पर निर्भर है।

→ पश्चिमी एशीया से भारत को ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति की जाती है।

2. बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय पश्चिमी एशिया में निवास करते है। उनके हितों की रक्षा करना भारत के लिए महत्वपूर्ण है।

यमन व ईराक में फंसे भारतीयों को बाहर निकालना

3. भारत को इस क्षेत्र से सर्वाधिक रेमेटेन्स प्राप्त होता है।

4. इस क्षेत्र में बहुत से आतंकवादी व अपराधी संगठन सक्रिय है जिनके बारे में खुफिया जानकारी इन देशों से प्राप्त होती है।

5. भारत के निर्यातों को बढ़ाने के लिए ये देश बाजार उपलब्ध करवाते है।

6. इन देशों के पास पूंजी आधिक्य है। जिसका प्रयोग भारत में निवेश के लिए किया जा सकता है।

7. इन देशों के माध्यम से पाक पर दबाव बनाया जा सकता है। जैसे- कश्मीर विवाद पर

8. भारत को OIC [इस्लामिक सहयोग संगठन] में 2019 में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।

OIC की स्थापना = 1969
सदस्य = 57
मुख्यालय = जेद्दा
[सऊदी अरब]

→ हिन्द महासागर व अरब सागर में भारत के प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए।

→ चीन को प्रभुत्व को कम करने के लिए

* पश्चिम एशिया की समस्याएं :-

1. इस क्षेत्र के देशों में लोकतंत्र का अभाव है। अधिकतर देशों में तानाशाही राजतंत्र या धार्मिक शासन है।
2. धार्मिक कट्टरवाद अत्याधिक है।
3. शिया - सुन्नी विवाद — शियाओं का नेता - ईरान तथा सुन्नी का नेता सऊदी अरब है जो कि अपने क्षेत्रीय राजनीतिक प्रभुत्व के लिए संघर्षरत है। यहाँ एक छोटा शीत युद्ध चल रहा है।
4. इस क्षेत्र में वैश्विक महाशक्तियों का हस्तक्षेप अत्याधिक है जैसे
   सऊदी अरब का समर्थक = USA ईरान - समर्थक = रूस, चीन
5. बहुत से आतंकवादी संगठन यहाँ सक्रिय है। जिसके कारण आपराधिक गतिविधियाँ भी बढ़ी हुई है।
6. यहाँ नागरिक अधिकार अत्याधिक कम विशेषकर - महिला
7. इन देशों की अर्थव्यवस्था ऊर्जा संसाधनों पर अतिनिर्भर है आय के साधनों में विविधता का अभाव है।

इजरायल - फिलीस्तीन विवाद

शीत युद्ध के बाद उदीयमान वैश्विक प्रवृत्तियाँ

* आर्थिक :-

1. द्वितीय विश्व से एक ध्रुवीय विश्व बना। पहले USA एकमात्र महाशक्ति था।

→ वर्तमान में विश्व बहुध्रुविता की ओर अग्रसर है।

→ पूंजीवाद को वैश्विक स्वीकार्यता मिली। वैश्वीकरण को सभी देशों ने अपनाया।

→ नियम आधारित वैश्विक व्यापार व्यवस्था के लिए WTO की स्थापना

→ वैश्विक आर्थिक अन्तर्निर्भरता बढ़ी।

* संचार :-

→ संचार क्षेत्र में क्रान्ति हुई।

→ इंटरनेट के माध्यम से आपसी जुड़ाव बढ़ा सोशल मीडिया के माध्यम से विचारों का प्रवाह तेज गति से हुआ।

→ इंटरनेट के माध्यम से नई चुनौतियाँ सामने आई।
जैसे- साइबर अपराध

→ जलवायु परिवर्तन वैश्विक मुद्दा बन चुका है।
इसके लिए निम्न कदम उठाये गये-

1992- पृथ्वी सम्मेलन
1997- क्योटो प्रोटोकॉल
2015- पेरिस सम्मेलन

→ 9/11 घटना के बाद वैश्विक आतंकवाद की अवधारणा सामने आई तथा इसके विरुद्ध वैश्विक युद्ध की शुरुआत हुई।

→ गैर राज्य संस्थाये जैसे - NGO, MNC आदि सशक्त हुई।

→ दक्षीण - दक्षीण सहयोग में धीमी गति

→ NAM की प्रासंगीकता का प्रश्नचिह्न

→ नाभिकीय हथियार आज भी विश्व के सामने खतरा

→ नये देश नाभिकीय शक्ति प्राप्त कर रहे है - उत्तरी कोरिया

→ USA के वर्चस्व को चीन की चुनौती।

भारत की विदेश नीति

विदेश नीति के कारक

स्थायी कारक

- → भू-राजनीतिक कारक
- → सुरक्षा
- → राष्ट्रीय हित
- → आर्थिक हित
- → विचारधारा, परम्परा
- → संस्कृति, अनुभव

गतिशील कारक

- → अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ
- → घटनाएँ
- → देश की आन्तरिक स्थिति
- → नेतृत्व

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010064

निर्धारक तत्व

बाहरी कारक

- → अन्य राष्ट्रों की नीतियाँ
- → वैश्विक गठबंधन

ऐतिहासिक

- → वसुधैव कुटुम्बकम
- → बौद्ध धर्म
- → गाँधीवादी विचार

संवैधानिक

- → अनुच्छेद
  - → 51
  - → 253
- → राष्ट्र की एकता व अखण्डता
- → परिसंघीय प्रणाली
- → राज्यों की शक्तियाँ

आर्थिक

- → वैश्वीकरण
- → आयात निर्यात

भौगोलिक

- → अवस्थिति
- → जनसंख्या

आंतरिक कारक

- → घरेलू राजनीति
- → राजनीतिक नेतृत्व

* भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धान्त

1. राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना।
2. राष्ट्रों के बीच विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करना।
3. विभिन्न देशों के बीच शान्ति, मित्रता, सद्इच्छा व सहयोग को बढ़ाना
4. सामाजिक - आर्थिक विकास एवं राजनीतिक स्थिरता जैसे राष्ट्रीय हितों को प्रोत्साहित करना।
5. निशस्त्रीकरण का समर्थन करना
6. साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं निरंकुश शक्तियों का प्रतिरोध करना
7. विश्व के देशों के मामले में हस्तक्षेप का विरोध करना।
8. मानवाधिकारों का सम्मान करना एवं नस्लीय भेदभाव एवं असमानताओं का विरोध करना
9. पंचशील एवं गुट निरपेक्ष सिद्धांतों को प्रोत्साहित करना।

* विशेषतायें :-

→ 1. गुटनिरपेक्षता की नीति
2. शान्ति की विदेश नीति - गाँधी, बुद्ध, पंचशील
3. मैत्री व शान्तिपूर्ण - सहअस्तित्व की नीति
4. साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नृजातीय भेदभाव → विरोध

THE NOTES HUB * All Competition Books * Notes are Available * 7300134518, 7610010004

5. निशस्त्रीकरण का समर्थन

6. UNO का समर्थन करने वाली संस्था

✱ विदेश नीति के सिद्धान्त :-

1. संवैधानिक प्रावधान
2. गुजराल सिद्धान्त
3. पंचशील सिद्धान्त
4. गुटनिरपेक्ष आन्दोलन
5. उपनिवेशीकरण का विरोध

✱ विदेश नीति का उद्विकास :- [2014 से पूर्व व पश्चात विदेश नीति]

1. [नया पंचशील]

→ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिया गया - 5S

1. सोच [विचार]
2. सम्पर्क
3. सहयोग
4. संकल्प
5. सपने

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010034

2. **पूर्व की ओर देखो नीति :-** 1991

→ वैश्वीकरण के बाद आर्थिक गतिविधियों व आर्थिक भागीदारी को बढ़ाना

→ आसियान देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाना।

3. एक्ट ईस्ट पॉलिसी - 2014

→ आसियान देशों के साथ हिन्द प्रशान्त क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाना

→ आर्थिक के साथ-साथ सांस्कृतिक व रणनीतिक क्षेत्र में सहयोग

→ इसके तहत विभिन्न FTA समझौते किये गये
जैसे - इंडिया - आस्ट्रेलिया - 2022

→ बौद्ध सर्किट की स्थापना

→ रक्षा सहयोग - फिलिपीन्स
वियतनाम

4. पश्चिम की ओर देखो नीति - 2005

→ ऊर्जा और प्रवासी भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए अपनाया

★ लिंक पश्चिम नीति -

→ इसे लुक वेस्ट के विस्तार के तौर पर देखा जाता है।

2. यह पश्चिम एशिया व उत्तरी अफ्रीका पर केन्द्रित है।

3. इसे I2U2 [प. एशिया क्वाड] जैसे सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है।

5. प्रोजेक्ट मौसम

→ सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से हिंद महासागर के देशों के बीच सम्पर्क स्थापित करना व संचार स्थापित करना

→ लॉन्च = सांस्कृतिक मंत्रालय

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010064

6. मेरीटाइम स्ट्रेटजी [समुद्री रणनीति]

→ हिन्द महासागर की गतिविधियों और प्रभुत्व को नियंत्रित करना

1. स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर
2. डायमंड नेकलेस
3. मिशन सागर

★ नीली अर्थव्यवस्था का इष्टतम उपयोग

→ इसमें समुद्री संसाधन शामिल है।

7. पड़ोसी प्रथम नीति

→ पूरे पड़ोस का विकास व समृद्धि

→ यह पड़ोस ही है जो हमारी सभी विदेश नीति में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर आता है।

भारतीय विदेशी नीति के निर्धारिक तत्व

- प्रायः सभी देशों की विदेशी नीति को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में बाँटा जा सकता है।

विदेश नीति के कारक

स्थायी कारक
- भू-राजनीतिक स्थिति
- सुरक्षा
- राष्ट्रीय हित
- आर्थिक हित
- विचारधारा, परम्पराएँ, संस्कृति, अनुभव

गतिशील कारक
- अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ
- घटनाएँ
- देश की आन्तरिक स्थिति
- नेतृत्व
- वैश्विक परिदृश्य

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010024

(i) **भौगोलिक कारकः–** अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर भूगोल के प्रभावों का अध्ययन भू–राजनीति (Geopolitics) कहलाता है। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जिसकी 1516 km. सीमा हिन्द महासागर में स्थित है। इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बनाये रखने के लिए भारत श्रीलंका, मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स से अपने सम्बन्धों को सुदृढ़ कर रहा है। इसी कारण भारत Indian Ocean Rim Association का संस्थापक सदस्य बना। पाक व चीन के साथ सीमा विवाद भी भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। मध्य एशिया से जुड़ने हेतु भारत ने 'मध्य एशिया से जुड़ो' नीति बनाई है।

(ii) ऐतिहासिक कारकः– आधारभूत रूप से किसी देश की विदेश नीति उसके तत्कालीन ऐतिहासिक अनुभवों परम्पराओं और संस्कृति से निर्धारित होती है। भारत साम्राज्यवाद, औपनिवेशवाद, रंगभेद, नस्लवाद का विरोध करता रहा है क्योंकि भारत इनसे पीड़ित रहा है। अन्य देशों से भारत के सांस्कृतिक सम्बन्ध अच्छे रहे है। भारतीय संस्कृति साम्राज्यवाद के घोर विरोधी 'जियो और जिने दो' जैसे विचारों की पोषक रही है।

(iii) वैचारिक कारकः– भारत ने सदैव "वसुधैव कुटुकम्बक" के आदर्श वाक्य को आधार बनाकर अपनी विदेश नीति को विश्व शांति और सद्भाव के मार्ग पर गतिमान रखा है। इसलिये भारत अपनी नीति के आचरण में पाँच नैतिक सिद्धांत 'पंचशील सिद्धांत' को प्रमुख आधार बनाते हुए शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व को अपनाने के लिये विश्व के राष्ट्रों का सम्मान करता रहा है। वैचारिक रूप से भारत में बुद्ध और गाँधी ने अहिंसा का सन्देश दिया व यही कारण रहा है कि भारतीय विदेश नीति अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा की समर्थक रही है। भारतीय दर्शन भी सहिष्णुता पर बल देता है।

(iv) आर्थिक कारकः– भारतीय निर्यात को बढ़ाना, जरूरी आयातों को सुनिश्चित करना तथा देश में निवेश को आकर्षित करना भारतीय विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य है। इसके लिये एसएअफटीए तथा भारत–आसियान जैसे मुक्त समझौते किये गये। भारत WTO का संस्थापक सदस्य बना तथा 1991 में आर्थिक सुधारों के तहत् वैश्वीकरण को अपनाया।

(v) सैन्य / रक्षा कारकः– प्रत्येक देश की विदेशनीति का लक्ष्य राष्ट्र की संस्कृति एवं धरोहर की सुरक्षा और विकास है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सदा स्थायी न रहकर चलायमान रहती है। अर्थात् कोई स्थायी शत्रु या

मित्र नहीं रहते। यह सभी राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर बनते एवं बिगड़ते है। शीत युद्ध के काल में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये USSR के साथ 1971 ई. में संधि की गई। निवारक क्षमता विकसित करने के लिये भारत ने नाभिकीय परीक्षण किये। घरेलू रक्षा उद्योग को विकसित करने के लिये वर्तमान में संयुक्त उत्पादन पर भी जोर दिया जा रहा है।

(vi) घरेलू कारकः— भारतीय विदेश नीति घरेलू राजनीति से भी प्रभावित होती है। जैसे — कि श्रीलंका के साथ सम्बन्धों को तमिलनाडु की राजनीति ने, बांग्लादेश के साथ सम्बंधों को पश्चिमी बंगाल, असम, त्रिपुरा की राजनीति ने तथा नेपाल के साथ सम्बंधों को बिहार की राजनीति ने प्रभावित किया है।

(vii) व्यक्तिगत कारकः— भारतीय विदेश पर सर्वाधिक प्रभाव नेहरू जी का रहा। गुट निरपेक्षता का सिद्धांत, तीसरे विश्व का नेतृत्व, पंचशील सिद्धांत, साम्राज्यवाद, नस्लवाद, रंगभेद, उपनिवेशवाद का विरोध आदि इनके ही विचार थे। इसके अलावा इंदिरा गांधी, इन्द्र कुमार गुजराल आदि ने भी विदेश नीति पर अपने प्रभाव डाले।

(viii) तकनीकी कारकः— तकनीकी ज्ञान में निरन्तर विकास के फलस्वरूप प्रत्येक राष्ट्र अपने आर्थिक विकास के लिये अत्याधुनिक तकनीक अपनाना चाहता है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक पावर, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, उपग्रह प्रणाली पर एकाधिकार रखने वाले देश इन जानकारियों के स्थानान्तरण एवं प्रयोग की अनुमति के लिये शर्तें रखकर अन्य विकसित और विकासशील देशों की विदेशी नीति को प्रभावित करते हैं।

(ix) सरकार का स्वरूपः— लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत, दबाव समूहों एवं जनसंचार की नीति—निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोकतांत्रिक राज्यों में निर्वाचन व्यवस्था भी विदेश नीति निर्माण में अपना प्रभाव रखती है। जैसे कि नेता सामान्यतः ऐसे निर्णय लेते जिससे लोग उनसे दूर न हो वहीं एक निरकुंश व्यवस्था में अधिकतर निर्णय शासक की निजी सोच के अनुसार होते है।

(x) देश की आन्तरिक बाध्यताएँः— न केवल अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएँ अपितु घरेलू घटनाक्रम भी विदेश नीति को निर्धारित करते हैं जैसेः— देश में निर्वाचन परिणामों को प्रभावित करने या फिर देश की नाजुक स्थिति व कमजोर आर्थिक हालात से लोगों का ध्यान हटाने के लिये भी ऐसा किया जाता है।

(xi) वैश्विक परिदृश्यः— शीत युद्ध के काल में गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को समर्थन प्रदान किया। USSR के विघटन के बाद USA से अच्छे सम्बन्ध बनाने की कोशिश की तथा एक ध्रुवीयता के काल में बहुध्रुवीयता का समर्थन किया। बदलते हुए राजनैतिक परिदृश्य के अनुसार भारत ने UN में सुधार की भी माँग की।

भारतीय विदेश नीति की विकास यात्रा

- स्वतंत्रता से अब तक भारतीय विदेश नीति को निम्न प्रकार विभाजित कर समझा जा सकता हैः—

1. पं. जवाहर लाल नेहरू का कालः—

- सम्भवतया इन्हें भारत की विदेश नीति का सूत्रधार कहा जा सकता है। ये अखिल एशियावाद तथा अन्तर्राष्ट्रीयता के समर्थक तथा साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, फासीवाद तथा रंगभेद नीति के विरोधी रहे। इनके शासन काल में।

— सन् 1954 में दादरा व नागर हवेली में पुर्तगाली आधिपत्य समाप्त किया तथा सन् 1961 में उसे केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया।

—'गोवा के प्रश्न' पर शक्ति का प्रयोग कर पुर्गगाली अत्याचारों से मुक्ति दिलाकर सन् 1961 में स्थायी रूप से गोवा को भारत में शामिल किया।

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610100064

–1961 ई. में दमन एवं दीव को पुर्तगाल मुक्त करवाकर भारतीय संघ में मिलाया।

नोटः– 1987 में गोवा को दमन एवं दीव से अलग कर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया तथा दिसम्बर 2019 में दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव को मिलाकर एक केन्द्र शासित प्रदेश बना दिया गया।

2. लाल बहादुर शास्त्री का कालः–

- नेहरू की नीति का अनुसरण कर पड़ोसी देशों (विशेषकर दक्षिण–पूर्वी एशिया के देश) से सबन्ध घनिष्ठ बनाने की पहल की गई।
- गुटनिरपेक्षता से परे राष्ट्रीय सुरक्षा पर बल दिया तथा 1965 के भारत–पाक युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह हराया।
- द्विध्रुवीय वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद अमेरिका तथा सोवियत संघ में उभरे सीमित सहयोग के कारण भारत को महाशक्तियों का एक साथ सामना करने हेतु तैयार किया। उदाहरणः– भारत ने 1965 में जैसा ताशकंद में किया
- 'जय जवान, जय किसान' का नारा देकर सैनिकों तथा किसान वर्ग को प्रोत्साहित कर सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का संदेश दिया।

3. इन्दिरा गांधी का कालः–

- भारतीय विदेश नीति की कुछ नवीन विशेषताएँ– लचीलापन, यथार्थ एवं आदर्श का समन्वय, राष्ट्रीय हित तथा आर्थिक सहयोग पर बल तथा विशेषज्ञों की विशेष भूमिका उभरी।
- 'चीन–अमेरिकी मैत्री' चुनौती का उत्तर 'भारत–सोवियत संघ मैत्री' संधि, शिमला समझौता तथा परमाणु विस्फोट आदि से दिया गया।
- वियतनाम मामले पर अमेरिका की आलोचना की तथा साम्राज्यवादी नीति पर अंकुश लगाने की बात कहीं।
- परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने का अत्यधिक दबाव होते हुए भी 1974 ई. में पोकरण परमाणु विस्फोट कर विश्व को चकित किया।

4. जनता सरकार कार्यकालः–

- आन्तरिक विरोध, वैचारिक अन्तर्विरोध तथा व्यवस्था में सुसंगत लक्षणों में अभाव के बावजूद विशुद्ध गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने तथा भारत–सोवियत संघ मैत्री संधि को कायम रखने में सफलता हासिल की।
- पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने, अरब देशों को समर्थन पर बल तथा रंगभेद, जातिभेद, उपनिवेशवाद आदि का विरोध किया।
- इजरायल के साथ राजनीतिक एवं रक्षा सम्बन्धी सम्पर्क स्थापित करने की पहल की।
- विदेश मन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत–पाक सम्बन्धों तथा भारत–चीन सम्बंधों में सुधार का प्रयास किया।

5. इंदिरा गांधी का द्वितीय कालः–

- 1982 ई. में नई दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों व 1983 ई. में 7वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन करवाया अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया।

6. राजीव गांधी का कालः–

- विदेशी नीति के चार मुख्य तत्वों निःशस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद–उन्मूलन, विकास तथा शान्ति की कूटनीति पर सर्वाधिक बल दिया।
- 1988 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 'आण्विक हथियार मुक्त और अहिंसक विश्व व्यवस्था' की योजना प्रस्तुत की।

- दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों की विश्व राजनीति में क्षेत्रीय सहयोग की प्रथम पहल हेतु 'दक्षेस' (SAARC) का गठन बांग्लादेश के ढाका में 7 – 8 दिसम्बर 1985 को किया जिसमें भारत भी सदस्य देश था।

नोट – विश्वनाथ प्राप्त सिंह एवं चन्द्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकारों द्वारा विदेशी नीति में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ।

7. पी.वी. नरसिम्हा राव कालः–

- अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों एवं कूटनीतिक समीकरणों में परिवर्तनों के कारण विश्व के परिदृश्य में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन नेतृत्वहीनता की स्थिति में था तथा साथ ही भारत में भी गम्भीर आर्थिक संकट की स्थिति विद्यमान थी।
- सरकार ने सुरक्षा परिषद् में भारतीय स्थायी सदस्यता का दावा मजबूती से रखने, सार्क के अधीन एसएएफटीए समझौता, जी–15 शिखर सम्मेलन आयोजन द्वारा उत्तर–दक्षिण वार्ता पर जोर तथा भारत के आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण कार्यक्रम द्वारा विदेशी सहयोग एवं पूँजी निवेश जैसे कार्य कियें।
- 'पूर्व की ओर देखो नीति' (Look East Policy) द्वारा नब्बे के दशक में भारत के पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी देशों के साथ सम्बन्धों को अधिक मजबूत किया।

8. एच.डी. देवेगौड़ा का कालः–

- विदेशी मंत्री के रूप में इन्द्र कुमार गुजराल ने 1996 ई. में गुजराल सिद्धांत की घोषणा की। यह सिद्धांत पड़ोसी देशों (खासतौर पर दक्षिण एशियाई देशों) के साथ मधुर सम्बंधों पर बल देता है।
- पड़ोसी देशों को एक तरफा वित्तीय मदद, व्यापार में छूट एवं गैर–रणनीतिक मुद्दों पर सहायता देने जोर दिया गया।

9. अटल बिहारी वाजपेयी का कालः–

- मई, 1998 में परमाणु परीक्षण सम्पन्न कर परमाणु आयुध के सन्दर्भ में "पहले उपयोग नहीं (No first Use)" की नीति की घोषणा की। इससे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा निः शस्त्रीकरण की भावना उभरी।
- 1999 के कारगिल युद्ध के बाद भी पाक तथा चीन के साथ सम्बन्ध सुधारने के प्रयास कर वैश्विक शान्ति का संदेश दिया।
- विदेशों में रह रहे भारतीयों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने हेतु 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का आरम्भ किया गया।

10. डॉ. मनमोहन सिंह का कालः–

- सन् 2014 तक के इनके कार्यकाल में न केवल भारत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई वरन् भारत– अमेरिका परमाणु समझौता भी सम्पन्न हुआ।
- पी.वी. नरसिम्हा राव ने जहाँ 'पूर्व की ओर देखो' नीति का नवोन्मेष किया, वहीं 2014 ई. में म्यांमार मे आयोजित आसियान–भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने व्यक्तिगत रूचि के कारण 'पूर्व में सक्रिय होने की नीति' में बदलने का श्रम किया।
- भारत चाहता है कि इसके जरिये वह पूरे एशिया– प्रशान्त क्षेत्र में अपने बेहतर संबंधों को स्थापित करें।

THE NOTES HUB

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद

परिभाषा – संयुक्त राज्य रक्षा विभाग ने आतंकवाद को प्रायः राजनीतिक, धार्मिक अथवा वैचारिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार अथवा समाज को अवपीड़ित या भयभीत करने हेतु व्यक्तियों अथवा संपत्ति के विरूद्ध बल अथवा हिंसा का गैर कानूनी अथवा धमकी भरे प्रयोग के रूप में परिभाषित किया है।

आतंकवाद के प्रकार –

- **धार्मिक आतंकवाद** – जो आतंकवादी गतिविधियाँ धार्मिक आदेशों और आवश्यकताओं से प्रेरित होती है।
- **विचारधारा से प्रेरित आतंकवाद** – सामान्यतः दो वर्गों में बाँटा जा सकता है।
  1. **वामपंथी आतंकवाद** – यह विचारधारा विश्वास करती है पूंजीवाद समाज में मौजूदा सभी सामाजिक संबंध और राज्य की प्रकृति शोषणात्मक है और हिंसक साधनों के माध्यम से एक क्रांतिकारी परिवर्तन अनिवार्य है उदाहरण – भारत और नेपाल में माओवादी गुट इसके उदाहरण है।
  2. **दक्षिणपंथी आतंकवाद** –
     ये समुह आमतौर पर यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं अतीत की, पूर्व की स्थिति को स्थापित करना चाहते है। जिसमें वे संरक्षित महसूस करते हैं। कभी– कभी ये नृजातीय चरित्र भी अपना लेते हैं। उदाहरण – जर्मनी में नाजी पार्टी, इटली में फाशीवादी।
- **मानवजातीय** – राष्ट्रवादी आतंकवाद (Ethno- Nationalist Terearish) अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी उपराष्ट्रीय मानव जातीय समूह द्वारा जान बुझकर की गई हिंसा को मानव जातीय आतंकवाद कहा जा सकता है उदाहरण – श्रीलंका में तमिल राष्ट्रवादी समूह और पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी समूह इसके उदाहरण है।
- **राज्य प्रायोजित आतंकवाद** – इसका उपयोग राष्ट्र द्वारा अन्य राष्ट्र के विरूद्ध अपनी विदेशी नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है उदाहरण – भारत, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की समस्या से परेशान है।
- **नारको आतंकवाद (NARCO Terrorism)** – यह आतंकवाद का प्रकार एवं आतंकवाद के साधन /वित्तीयन दोनों की श्रेणी में है। स्वापक पदार्थो के अवैध व्यक्तियों की क्रमबद्ध धमकी अथवा हिंसा द्वारा सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के प्रयास के रूप में देखा जाता है उदाहरण– पाक की आई एस आई ऐजेंसी समर्थित इस्लामी आतंकी गुटो द्वारा– भारत में मादक पदार्थो के अवैध व्यापार में सही संलिप्त पाया गया है।
- **जैव आतंकवाद (Bio Terrorism)** – किसी क्षेत्र की आबादी के विनाश के उद्देश्य से व्यापक पैमाने पर जीवन के लिए संकट उत्पन्न करने वाले रोगों को फैलाने हेतु बैक्टीरिया, वायरस या उनके विषाक्त पदार्थो जैसे – सूक्ष्मजीवों के रोगजनक उपभेदों का एक नियोजित एव सुविचारित उपयोग है।
- **साइबर आतंकवाद** – यह आतंकवाद और साइबर स्पेस का संयोजन है।
  – अपने राजनीतिक अथवा सामाजिक हितों की पूर्ति के लिए अथवपा सरकार या लोगों को भयभीत अथवा पीड़ित करने के आशय से कम्प्यूटरों, नेटवर्क और उसमें संग्रहित सूचना के विरूद्ध गैर–कानूनी आक्रमण और आक्रमण की धमकी के अर्थ में समझा जा सकता है।

आतंकवाद के कारण –

- **राजनैतिक** – आतंकवाद को गैर राज्य सेना या समूह द्वारा संगठित राजनीतिक हिंसा के रूप में उपयोग किया जाता है। क्योंकि उन्हें समाज का मौजूदा संगठन पसंद नहीं है और वे इसे बदलना चाहते हैं।

- **सामरिक** – कुछ आतंकी समूह अपने बड़े लक्ष्य के लिए एक रणनीति के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। यह मजबूत शक्तियों के विरूद्ध लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आतंकवाद का उपयोग करते हैं।
- **धार्मिक** – कुछ कट्टरपंथी समूह धर्म की गलत व्याख्या कर आतंक की गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।
- सामाजिक आर्थिक – वंचितता लोगों को आतंकवाद के प्रति सुभेदय बनाती है। जैसे – गरीबी, शिक्षा में कमी, राजनैतिक स्वतंत्रता की कमी के कारण आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है।

विभिन्न आतंकवादी संगठन –

– अफगानिस्तान में तालिबान

– अल–कायदा

– बब्बर खालसा इंटरनेशनल

– जेश–ए–मोहम्मद

– जम्मू एण्ड कश्मीर इस्लामिक फ्रंट

– नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलेण्ड (NBFD) – असम

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010004

वैश्विक प्रयास –

FATF (Financial Action Task Force) वैश्विक धन शोधन एवं आतंकवाद के वित्त पोषण की निगरानी करने वाला निकाय।

– 37 सदस्य (भारत सहित 1 + EU+GCC)

– 1989 में जी–7 द्वारा पेरिस शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापना।

– दो सूचियों जारी की जाती है।

ब्लेक लिस्ट – उदाहरण – उत्तर कोरिया, ईरान

ग्रे लिस्ट – पाकिस्तान

– United Nations Security Council Resolution, 1267

– 2011 में स्थापित Global Counter – Terrorism Froum

– हाल ही में वियना में पहली Global Parliamentary Summit On Counter Terrorism संपन्न हुई।

भारत के आतंकवाद – रोधी उपाय

– राष्ट्रीय स्तर पर – राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण (NIA)

- नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NAT GRID)

- राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)
- गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम, 1967 (UAPA)
- धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2005
- हाल ही में दिया गया फाइव पाइंट फार्मूला। आदि के माध्यम से आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना।

– **अंतरराष्ट्रीय स्तर पर** –भारत ने निम्नलिखित के माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक अंतर–सरकारी ढाँचे के अंगीकरण को प्राथमिकता दी है–

- CCIT (Comprehensive Convention On International Terrorism) का प्रस्ताव भारत द्वारा पेश किया गया।
- US – इंडिया होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग।
- FATF के साथ मिलकर आतंकी वित्त पोषण का मुकाबला
- ब्रिक्स–आतंकवाद रोधी रणनीति
- आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद का मुकाबला करने पर शंघाई कन्वेशन

– आंतकवाद विरोधी कानून –

- आतंकवादी और विघटनकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (TADA), 1987 – वर्ष 1999 में समाप्त।
- पोटा, 2002 – 2004 में समाप्त
- मकोका (MCOCA),1999 – वर्तमान में महाराष्ट्र में लागू।
- GCTOC अधिनियम,2019 – वर्तमान में गुजरात में लागू ।

UAPA, 2019 में संशोधन –

- एकल व्यक्ति को भी आतंकवादी के रूप में नामित करने की शक्ति सरकार को सौप दी है। (पहले केवल संगठन को घोषित करने की शक्ति थी।)
- जाँच NIA के अधिकारी के द्वारा तो आतंकवाद से जुड़ी सम्पति को जब्त करने के लिए NIA के महानिदेशक स्वीकृति अनिवार्य होगी। (पहले पुलिस महानिदेशक की स्वीकृति आवश्यक थी।)
- मामलों की जाँच के लिए इंस्पेक्टर या उस से ऊपर की रैंक के अधिकारी को अधिकृत किया गया है।
- इस अधिनियम के तहत अनुसूची में "परमाणु आतंकवाद संबंधी कृत्यों का दमन करने संबंधी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय" के प्रावधानों को शामिल किया गया है।

NAM [गुटनिरपेक्ष आन्दोलन]

- सदस्य = 120 देश

→ यह एक अन्तर्राष्ट्रीय नीति है।

* **3 मुख्य घटक** :-

1. किसी भी सैन्य समूह में शामिल नहीं होना
2. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रियता बनाये रखना
3. विदेश नीति में स्वतंत्रता रखना

* गुट निरपेक्ष शब्द = वी.के मेनन [भारत के पूर्व रक्षा मंत्री]

* 1955 :- अफ्रीकी - एशीयाई सम्मेलन - बांडुंग [इण्डोनेशीया]

→ इस अवधारणा जवाहर लाल नेहरू ने विस्तृत किया।

* बेलग्रेड सम्मेलन [1961] :- गुटनिरपेक्ष आन्दोलन आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ

JLN = भारत

ऊ नू = म्यांमार

अब्दुल नासिर नासिर = मिस्र

टीटो = युगोस्लाविया

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610100024

✱ NAM का महत्व :-

1. तीसरे विश्व के देशों को अपनी बात रखने का मंच उपलब्ध करवाया गया।

2. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक उपनिवेशवाद
साम्राज्यवाद
नस्लीय भेदभाव
रंगभेद

3. शीतयुद्ध के काल में शान्ति का समर्थन किया।

4. नाभिकीय निशस्त्रीकरण का समर्थन

5. हथियारों की दौड़ का विरोध

THE NOTES HUB ★ All Competition Books ★ Notes are Available ★ 7300134518, 7610010064

✱ NAM की आलोचनाएँ :-

→ 1991 में USSR के विघटन के बाद गुटनिरपेक्षता अप्रासंगिक हो गई।

→ प. देशों का आरोप है कि NAM का झुकाव USSR की ओर था।

→ NAM की उपलब्धियाँ अत्यधिक सीमित है।

✱ प्रासंगिकता :-

1. राजनीतिक :-

→ विश्व राजनीति में अमेरिकी आधिपत्य को कम करना।

→ बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण करना।

→ संयुक्त राष्ट्र में सुधार

→ विकासशील व अल्प-विकसित देशों के हितों की रक्षा करना।

→ नवसाम्राज्यवाद का विरोध।

2. आर्थिक क्षेत्र में।

1. वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में सुधार लागू करना।

2. WTO में विकासित देशों के प्रभाव को कम करना।

3. संरक्षणवाद का विरोध करना।

4. WTO में वि

5. दक्षिण - दक्षिण सहयोग को बढ़ाना।

3. रक्षा क्षेत्र में

1. नाभिकीय निशस्त्रीकरण को बढ़ाना

2. आतंकवाद का विरोध

3. साइबर सुरक्षा

4. <u>अन्य क्षेत्र में :-</u>

1. जलवायु परिवर्तन को रोकना

2. विश्व के ज्वलंत मुद्दो को हल करना

जैसे- शरणार्थियों का संकट

यूक्रेन संकट

Notes